सुविचार

निगाह चौमुखी रहे, विचार लक्ष्य पर रहे, जिधर से शत्रु आ रहा, उसी तरफ नजर रहे।

-वंशीधर शुक्ल

Daily

THE PHOTON NEWS

सच के हक में...

द फोटोन न्यूज Published from Ranchi

Ranchi ● Tuesday, 03 February 2026 ● Year : 05 ● Issue : 21 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com

E-Paper : epaper.thephotonnews.com

12

Bhumi Pednekar Felicitated...

SHARE

संसेक्स	:	81,666.46
निफ्टी	:	25,088.40

SARAFA

सोना	:	14,040
चांदी	:	300.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

तीनों सेनाओं के लिए फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स शुरू

NEW DELHI : तीनों सेनाओं के लिए तीसरा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स सोमवार से मानेकशॉ सेंटर में शुरू हुआ, जो 25 फरवरी तक चलेगा। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में और संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र (सीईएनजेओडब्ल्यूएस) के सहयोग से संचालित इस कोर्स में विशिष्ट विषयों का अध्ययन कराया जायेगा। साथ ही सैन्य अभियानों में क्षेत्र विशिष्ट पर आधारित युद्धक क्षेत्र के बदलाव को भी इस कोर्स में शामिल किया गया है। सेना के अनुसार यह कोर्स इस बात की गहन समझ विकसित करने पर केंद्रित है कि प्रौद्योगिकी युद्ध संचालन को कैसे प्रभावित कर रही है। इसके लिए हमारी सोच, अवधारणाओं, सिद्धांतों, रणनीतियों और युद्ध रणनीति पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। इसमें महत्वपूर्ण विषयों का गहन अध्ययन, उभरती प्रौद्योगिकियों के व्यावहारिक प्रदर्शन और रक्षा बलों की क्षमताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थानों का दौरा भी शामिल है। इस कोर्स में तीनों सेनाओं के साथ-साथ रक्षा क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप, एमएसएमई, डीपीएसयू और निजी उद्योगों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

इंदौर में दूषित पानी से एक और मरीज की मौत

INDORE : मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से फैली बीमारी के कारण एक और मरीज की मौत हो गई। एक माह से भी अधिक समय से अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग महिला मरीज रविवार देर रात इलाज के दौरान तोड़ दिया। इसके बाद क्षेत्र में दूषित पानी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। जानकारी के अनुसार, भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैली बीमारी के बाद करीब एक माह पहले 65 वर्षीय अनिता कुशवाह की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनका 04 जनवरी से बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर थीं।

केंद्रीय बजट में रेलवे के विकास के लिए झारखंड को मिले 7536 करोड़

₹63470 करोड़ की योजनाओं पर चल रहा काम, रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर रांची स्टेशन होगा डेवलप

यात्रियों की सुविधा के लिए प्रदेश के लोगों को मिलेंगी दो जोड़ी नई अमृत भारत ट्रेनें

PHOTON NEWS RANCHI : आम बजट पेश होने के बाद सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कई डिविजनों के जीएम और डीआरएम के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग राज्यों को बजट में कितनी राशि की योजनाएं दी गईं, इसकी जानकारी साझा की। साथ ही बताया कि झारखंड को 7536 करोड़ रुपये दिए गए है। उन्होंने कहा कि राज्य में 63,470 करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम जारी है। इसमें लाइन बिछाने, स्टेशन री-डेवलपमेंट और सेफ्टी जैसे मुख्य काम शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे झारखंड के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा दो अमृत भारत ट्रेनों के परिचालन को भी मंजूरी दी गई है।

- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कई डिविजनों के जीएम और डीआरएम के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े
- लाइन बिछाने, स्टेशन री-डेवलपमेंट और सेफ्टी जैसे होंगे मुख्य कार्य
- 57 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा विकसित रांची डिविजन में भी 15 स्टेशनों का होगा कायाकल्प

तीन महीने में स्टेशनों का पूरा हो जाएगा काम

रांची रेल डिविजन के डीआरएम करुणानिधि सिंह ने बताया कि झारखंड में 57 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत डेवलप किया जा रहा है। रांची डिविजन में भी 15 स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इसमें एक स्टेशन गोबिंदपुर रोड का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। इसके अलावा 3 स्टेशनों का काम पूरा होने को है। इन स्टेशनों में लोहरदगा, पिस्का, गोबिंदपुर रोड, बानो, ओरगा, बालसीरिंग, नामकुम, टाटीसिल्वे, मुरी, रामगढ़ कैंट, झालिदा, सुइसा, तुलिन शामिल है। अगले तीन महीने में इन स्टेशनों का काम पूरा हो जाएगा।

रांची के रास्ते एक अमृत भारत ट्रेन

12 वंदे भारत झारखंड से होकर चल रही हैं। उन्होंने कहा कि 2 अमृत भारत ट्रेन और झारखंड को मिलने वाली है। जिसमें एक ट्रेन धनबाद से कोयंबटूर वाया रांची अमृत भारत ट्रेन का परिचालन होगा। इसके अलावा एक और ट्रेन की जानकारी फिलहाल रेलवे की ओर से नहीं दी गई है। लाइन डबलिंग को प्राथमिकता में रखा गया है। रांची से टोरी और चांडिल से मुरी और मुरी से बरकाकाना लाइन डबल करने की योजना है। इसके साथ ही रांची से हटिया के बीच चार लाइन बिछाने की भी योजना है।

वर्ल्ड क्लास बनेगा रांची स्टेशन, रैंप और लिफ्ट की सुविधा

डीआरएम ने बताया कि रांची डिविजन में कई प्रोजेक्ट चल रहे है। इसमें रांची और हटिया स्टेशन का रीडेवलपमेंट भी किया जा रहा है। अगले दो महीने में रांची का साउथ गेट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद पैसेंजर्स को कुछ नया मिलेगा। एयरपोर्ट की तरह सुविधाएं रांची स्टेशन पर मिलेंगी। रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर रांची स्टेशन को नया लुक दिया जा रहा है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन में लोगों को अराइवल-डिपार्चर के लिए अलग-अलग रास्ते होंगे। वहीं डिजेबल्स के लिए रैंप और लिफ्ट की सुविधा मिलेगी। वेटिंग एरिया और फूड लाउंज भी यात्रियों के लिए होगा।

सेरेंगसिया के शहीदों को मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि, विकास योजनाओं की सौगात

अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देते हैं वीर शहीद : हेमंत

PHOTON NEWS CHAIBASA : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोन्टो प्रखंड स्थित सेरेंगसिया गांव पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद स्थल पर सेरेंगसिया घाटी में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों की यह धरती आज भी अधिकारों की लड़ाई के लिए प्रेरणा देती है। सेरेंगसिया घाटी में यहां के वीर आदिवासियों ने 1837 में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। बाद में ब्रिटिश सिपाहियों ने छलपूर्वक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर इसी घाटी में फांसी पर लटका दिया था।

इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार रांची से नहीं, गांवों से चलती है। झारखंड की सरकार फाइलों और हेडक्वार्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचने वाली, जनता को उसका अधिकार देने वाली और जनता के सुख-दुख की जिम्मेदारी उठाने वाली सरकार है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

गांव-गांव तक पहुंचने और जनता के सुख-दुख की जिम्मेदारी उठाने वाली है हमारी सरकार

1479 युवाओं को विभिन्न विभागों के सौंपे गए नियुक्ति पत्र

हेमंत ने राज्य के 1479 युवाओं को विभिन्न विभागों के नियुक्ति पत्र सौंपे। नियुक्ति पत्र पाते ही युवाओं के चेहरों पर उम्मीद और आत्मविश्वास साफ नजर आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि - सरकार आपके द्वार- कार्यक्रम के तहत गांवों में जाकर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने बीते दौर पर तंज कसते हुए कहा कि पहले गांवों में बिजली नहीं आती थी, लेकिन बिल जरूर पहुंच जाता था। अब सरकार ने एकमुश्त बिजली बकाया माफ कर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है। शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने असम में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एक ही देश में आदिवासियों के लिए दो तरह के कानून लागू होना दुर्भाग्यपूर्ण है।

भाजपा ने राज्य को बना दिया था लूट का केंद्र

राजनीतिक हमले के दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर आरोप लगाया कि झारखंड के 25 वर्षों में भाजपा ने राज्य को लूट का केंद्र बना दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकारें वादों से मुकरती रहीं, जबकि झामुमो की सरकार वादों को निभाने का काम कर रही है। महिलाओं के सशक्तीकरण का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि मंईयां सम्मान योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। केवल पश्चिमी सिंहभूम जिले में ही दो लाख से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। वहीं, जेपीएससी के माध्यम से हजारों युवाओं को नौकरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 के पहले महीने तक 25-26 हजार नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

ईसीआईआर दर्ज करने के बाद ईडी की जांच तेज, 28 अफसरों से मांगा संपत्ति ब्योरा

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) की द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एनफोर्समेंट केस इनफॉरमेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करने के बाद मनी लाउंड्रिंग के बिंदु पर जांच तेज कर दी है। ईडी ने इस मामले में सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) की ओर से आरोपित झारखंड पुलिस और प्रशासन के 28 अधिकारियों से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी है। सीबीआई द्वारा जेपीएससी-2 में हुए घोटाले की जांच के बाद आरोपपत्र दायर किया जा चुका है। आरोपित सभी 28 अधिकारी फिलहाल जमानत पर हैं। जानकारी के अनुसार, सीबीआई ने कुल 60 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें जेपीएससी के छह अधिकारी, ग्लोबल इंफॉरमेटिक्स के एक, गलत तरीके से सफल घोषित 28 परीक्षार्थी और 25 परीक्षक शामिल थे। ईडी ने ईसीआईआर में इन सभी को अभियुक्त बनाया है। इस परीक्षा में सफल होकर अफसर बने राज्य प्राशसनिक सेवा के अधिकारी अब एडीएम रैंक में प्रोन्नत हो चुके हैं। राज्य पुलिस सेवा के दो अधिकारी प्रोन्नत होकर आईपीएस रैंक में नियुक्त हो चुके हैं।

द्वितीय जेपीएससी घोटाला

- सीबीआई की ओर से कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है चार्जशीट
- राज्य पुलिस सेवा के दो अधिकारी प्रोन्नत होकर आईपीएस रैंक में हो चुके हैं नियुक्त
- राज्य प्राशसनिक सेवा के कई अधिकारी अब एडीएम रैंक में हो चुके हैं प्रोन्नत

पुलिस व राज्य प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारी दायरे में

इस सूची में पुलिस उपाधीक्षक स्तर के कई अधिकारी शामिल हैं। इनमें राधा प्रेम किशोर, मुकेश कुमार महतो, शिवेंद्र, अरविंद कुमार सिंह और विकास कुमार पांडेय शामिल हैं। ये सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यकाल में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त रहे हैं।राज्य प्रशासनिक सेवा से जुड़े बड़ी संख्या में अधिकारी भी ईडी की जांच के दायरे में आए हैं। इनमें बिनोद राम, हरिशंकर बड़ाइक, कानू राम नाग, प्रकाश कुमार, रजनीश कुमार, संतोष कुमार चौधरी, रोहित सिन्हा, अमित कुमार, राहुल जी आनंद जी, शिशिर कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह, राम कृष्ण कुमार, प्रमोद राम और मनोज कुमार शामिल हैं। ईडी ने डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट पद पर नियुक्त रहे अधिकारियों से भी संपत्ति का ब्योरा मांगा है। इस श्रेणी में हरिहर सिंह मुंडा और रवि कुमार कुजूर के नाम शामिल हैं। वित्त सेवा से जुड़े कई अधिकारी भी इस जांच सूची में हैं। इनमें कुंदन कुमार सिंह, मौसमी नागेश, संगीता कुमारी, शैलेश कुमार श्रीवास्तव, इंद्रजीत सिंह और सुदामा कुमार शामिल हैं। ईडी की सूची में सहकारिता सेवा से जुड़े अधिकारी कुमुद कुमार का नाम भी शामिल है। ईडी ने राज्य सरकार को पत्र लिख कर इन सभी अधिकारियों को पोस्टिंग और संपत्ति का ब्योरा मांगा है।

शिक्षा विभाग व प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारी

आज से शुरू होंगी जैक बोर्ड की मैट्रिक-इंटर की परीक्षाएं

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) द्वारा आयोजित मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 3 फरवरी से से शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं। इन केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस बल एवं उड़नदस्ता टीम की तैनाती की गई है। कदाचार रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू की गई है। वहीं परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ले जाने पर प्रतिबंध है। जैक ने परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचने को कहा है। प्रवेश पत्र के बिना किसी भी छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस बल एवं उड़नदस्ता टीम की हुई तैनाती

रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित कडरू की न्यू एजी कॉलोनी की घटना

परिवार के 3 लोगों ने किया सुसाइड अटेम्प्ट, बेटे की मौत

PHOTON NEWS RANCHI : राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित कडरू, न्यू एजी कॉलोनी (मंदिर मार्ग) में एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने आत्महत्या की कोशिश की। इस घटना में परिवार के इकलौते बेटे की मौत हो गई है, जबकि मां और बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान मिहिर के रूप में हुई है। मिहिर ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। उसकी मां स्नेहा अखौरी और 14 वर्षीय बहन ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

मां-बेटी की हालत गंभीर, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम

- हाल ही में कोलकाता से सीए की पढ़ाई पूरी कर रांची लौटा था मिहिर
- पुलिस को अभी तक सुसाइड नोट या किसी ठोस कारण की नहीं मिली है जानकारी

हाईकोर्ट की अधिवक्ता हैं स्नेहा अखौरी

बताया जा रहा है कि मिहिर हाल ही में कोलकाता से अपनी सीए की पढ़ाई पूरी कर रांची लौटा था। चर्चा है कि उसका चयन प्रतिष्ठित उषा मार्टिन कंपनी में हुआ था और वह जल्द ही अपनी पेशेवर जिंदगी की शुरुआत करने वाला था। मिहिर की मां स्नेहा अखौरी, झारखंड हाई कोर्ट में एक अधिवक्ता हैं। उन्होंने और उनकी 14 साल की नाबालिग बेटी ने जहर खा लिया है। दोनों को आनन-फानन में रांची के गुरुनानक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। डॉक्टर उन्हें बचाने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं।

बड़ी उपलब्धि इसरो के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ाए ऐतिहासिक कदम

भारत स्पेस स्टेशन के कोर स्ट्रक्चर पर अब शुरू हो गया काम

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK : दशकों पहले पड़ी बुनियाद के आधार पर विगत चंद वर्षों में हिंदुस्तान ने स्पेस साइंस यानी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाए हैं। इसका यह एक पुख्ता प्रमाण है कि भारत अब कुछ वर्षों में स्पेस स्टेशन वाले देशों के एलीट क्लब में शामिल हो सकता है। इस क्षेत्र में एतिहासिक कदम बढ़ाते हुए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑगेर्नाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों ने भारत स्पेस स्टेशन (बीएसएस) के कोर स्ट्रक्चर पर काम शुरू कर दिया है। यह स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जहां भारतीय अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिक लंबे समय तक रहकर शोध कर सकेंगे। शोधार्थियों की दृष्टि में यह प्रोजेक्ट मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई दिशा देने वाला है। गौरतलब है कि इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने भारत स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल के निर्माण के लिए देश की एयरोस्पेस कंपनियों से भी संपर्क किया है। जानकारी के अनुसार, बीएस-01 नाम का यह पहला मॉड्यूल वर्ष 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही भारत का अंतरिक्ष में स्थायी लैब स्थापित करने का सपना औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा।

बीएसएस को पूरी गति से कुशलता के साथ लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर रहा सिस्टम

भारतीय अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिक लंबे समय तक वहां रहकर कर सकेंगे शोध

- शोधार्थियों की दृष्टि में मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई दिशा देने वाला है प्रोजेक्ट
- परियोजना के प्रारंभ के पहले देश की एयरोस्पेस कंपनियों से भी किया गया संपर्क

- बीएसएस-01 नाम का यह पहला मॉड्यूल दो साल बाद किया जाने वाला है लॉन्च
- स्पेस में स्थायी लैब स्थापित करने का सपना औपचारिक रूप से जल्द हो जाएगा शुरू

'गगनयान' मिशन के बाद और तेज होगी तैयारी

भारत स्पेस स्टेशन की योजना 'गगनयान' कार्यक्रम के बाद तेज गति से आगे बढ़ेगी। इसरै का मानना है कि यह स्टेशन लंबी अवधि के वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए बेहद अहम होगा। इसके जरिए भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं और नई तकनीकों के विकास में भी मदद मिलेगी। बता दें कि 'गगनयान' भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, जिसे 2027 तक लॉन्च करने की तैयारी है। कुछ दिन पहले इसरो प्रमुख वी. नारायणन ने बताया था भारत 2040 तक अपना पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन भेज सकता है, जिसके लिए इसरो ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इहरो की योजना के मुताबिक, स्पेस स्टेशन को एक साथ नहीं, बल्कि चरणबद्ध तरीके से तैयार किया जाएगा। पहले मॉड्यूल के बाद अन्य मॉड्यूल अलग-अलग लॉन्च किए जाएंगे और अंतरिक्ष में ही जोड़े जाएंगे। अनुमान है कि वर्ष 2035 तक भारत स्पेस स्टेशन पूरी तरह कार्यशील हो जाएगा। हर मॉड्यूल का व्यास लगभग 3 .8 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर होगी।

जूनियर इंजीनियर परीक्षा पेपर लीक में आउटसोर्सिंग कंपनी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

RANCHI : साल 2022 में जूनियर इंजीनियर परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी आउटसोर्सिंग कंपनी को जेएसएससी ने ब्लैकलिस्टेड करने का आदेश दिया था। जेएसएससी के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज किया था। आउटसोर्सिंग कंपनी मामले में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल करने को चुनौती वाली जेएसएससी की याचिका की पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में हाईकोर्ट में आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा दाखिल अवमानना याचिका की कार्यवाही पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। साथ ही आरोपी आउटसोर्सिंग कंपनी को नोटिस जारी किया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में जेएसएससी की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा।

बजट सत्र : शाह-राजनाथ ने टोका तो पूछा- क्यों डर रही सरकार

राहुल के भाषण के साथ लोकसभा में हंगामा, कल तक के लिए स्थगित

NEW DELHI @ PTI : सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी की स्पीच के दौरान ट्रेजरी बेंच की ओर से जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने दो बार सदन के कार्यवाही स्थगित की। बाद में शाम 4 बजे अगले दिन तक के लिए लोकसभा स्थापित कर दी गई। प्रारंभ में राहुल गांधी 46 मिनट तक अपनी बात रखने की कोशिश करते रहे। हर बार उनके बोलने पर स्पीकर ओम बिरला ने टोका और नियमों का हवाला दिया। राजनाथ, अमित शाह और किरेन रिजिजू भी उनका विरोध करते दिखे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आखिर सरकार क्यों डर रही है। दरअसल, राहुल ने कहा, डोकलाम में चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंच गए थे। मैं यह बात एक मैगजीन के आर्टिकल के हवाले से कह रहा हूं। इसमें पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब (मेमॉयर) को कोट किया गया है। राहुल बोले- आप सब ध्यान से सुनें कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, इससे पता चल जाएगा कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं।

दुबई में फंसे झारखंड के 14 प्रवासी मजदूरों ने सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार

तीन माह से नहीं मिला वेतन, वीडियो जारी कर मांगी गई है सहायता, गिरिडीह, हजारीबाग व बोकारो के रहने वाले हैं सभी मजदूर

- भोजन-आवास का संकट तय समय-सीमा से अधिक काम करने के बावजूद नहीं दी जा रही मजदूरी

वीडियो संदेश जारी करते दुबई में फंसे श्रमिक

PHOTON NEWS GIRIDIH : दुबई में आर्थिक तंगी और असुरक्षित हालात के बीच झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिलों के 14 मजदूर फंसे हुए हैं। इन्हें बीते तीन माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने भोजन और आवास का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि इनसे तय समय से अधिक काम भी कराया जा रहा है, लेकिन मेहनत के बदले मजदूरी नहीं दी जा रही। मजदूरों का आरोप है कि जिस कंपनी में वे काम कर रहे हैं, वहां उनसे तय समय से अधिक काम कराया जा रहा है और मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से रहने, खाने-पीने और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में भारी कठिनाई हो रही रहा है। विदेश में फंसे मजदूरों ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी पीड़ा साझा की है और भारत व झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई है। यह वीडियो प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली को भेजा गया है, जिसे उन्होंने मीडिया के साथ साझा किया है। सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि दुबई में फंसे मजदूरों की सकुशल वतन वापसी के लिए ठोस और प्रभावी कूटनीतिक पहल की जाए।

ट्रांसमिशन लाइन का काम करने गए थे दुबई

जानकारी के अनुसार, सभी मजदूर अक्टूबर 2025 में ईएमसी कंपनी में ट्रांसमिशन लाइन का काम करने के लिए दुबई गए थे। लेकिन, बीते तीन महीनों से किसी भी मजदूर को नियमित वेतन नहीं मिला है। मजदूरों ने सरकार से जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर उन्हें सुरक्षित देश वापस लाने की मांग की है। दुबई में फंसे मजदूरों में गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चिचाकी निवासी रोशन कुमार व अजय कुमार, बगोदर थाना क्षेत्र के तिरला निवासी राजेश महतो और डुमरडेली निवासी अजय कुमार और बोकारो जिले के पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कंजकीरो निवासी डालेश्वर महतो शामिल हैं। इसके अलावा हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के खेदाडीह निवासी जागेश्वर महतो व फालेन्द्र महतो, सिरैय निवासी बैजनाथ महतो, पारजोरिया निवासी दिलीप महतो, गंगाधर महतो व त्रिलोकी महतो, चकचुको बसरिया निवासी दीपक कुमार और गोरहर निवासी रोहित महतो व सेवा महतो भी दुबई में फंसे हैं।

सऊदी में एक मजदूर की पहले हो गई थी मौत

सिकंदर अली ने बताया कि यह कोई पहला मामला नहीं है, जब प्रवासी मजदूर अच्छी कमाई की लालच में विदेश जाकर फंसे हैं। इससे पहले भी विदेशों में फंसे झारखंड के कई मजदूरों को काफी प्रयासों के बाद वतन वापसी कराई गई है। कहा कि गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मधगोपाली पंचायत (दूधपनिया गांव) निवासी प्रवासी मजदूर विजय कुमार महतो की 23 अक्टूबर 2025 को सऊदी अरब में मौत हो गई थी। घटना के तीन महीने बीत जाने के बावजूद अब तक न तो उनका शव देश लाया जा सका है और न ही उनके परिजनों को कोई मुआवजा मिला है।

एमपी के सड़क हादसे में पलामू निवासी की हुई मौत, 10 घायल

PALAMU : मध्यप्रदेश के मुरैना में सड़क हादसे में पलामू जिला स्थित पांकी निवासी उमेश कुमार की मौत हो गई। इस दुर्घटना में पलामू जिले के 10 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, उमेश कुमार अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मथुरा-वृंदावन का भ्रमण कर लौट रहे थे। इसी क्रम में रविवार की रात करीब 1.30 बजे टेंपो- ट्रैवलर मुरैना के पास ओवरटेक करने के दौरान डंपर से टकरा गई। धक्का लगते ही उमेश कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायलों में वाहन चालक दिल्ली निवासी विपिन कुमार, पांकी निवासी डबलू गुप्ता और उसकी पत्नी आरती देवी, तरहसी निवासी प्रमोद कुमार, चैनपुर के सलतुआ निवासी अनिल गुप्ता व उसकी पत्नी कुसुम गुप्ता, तरहसी निवासी द्वारिका प्रसाद व उसकी पत्नी शोभा देवी, पांकी के मंझौली निवासी रविंद्र कुमार व देवरानी देवी शामिल हैं। सभी घायलों को मुरैना स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल प्रमोद कुमार ने बताया कि उमेश कुमार के शव का सोमवार को पोस्टमॉर्टम कराकर वाहन से पांकी भेज दिया गया। सामान्य रूप से घायल लोगों को मंगलवार को डिस्चार्ज किया जाएगा, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर अस्पताल में रेफर किया जाएगा।

BRIEF NEWS

मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के लिए बना कंट्रोल रूम

RAMGARH : रामगढ़ जिले में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम पाली और इंटर की परीक्षा द्वितीय पाली में होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जिला प्रशासन के द्वारा परीक्षा सेल और कंट्रोल रूम बनाया गया है। मैट्रिक परीक्षा 03 फरवरी 2026 से 17 फरवरी एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 03 फरवरी 2026 से 23 फरवरी तक होगी। रामगढ़ एसडीओ अनुराग कुमार तिवारी ने परीक्षा सेल-सह-जिला नियंत्रण कक्ष का गठन किया है। उक्त परीक्षा के दौरान विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न-पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं की समय पर आपूर्ति, परीक्षा उपरांत सामग्री को जिला कोषागार तक सुरक्षित पहुँचाने तथा सतत निगरानी हेतु परीक्षा सेल का गठन किया गया है। नियंत्रण कक्ष अनुमंडल कार्यालय में स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष संख्या 06553-222005 है। परीक्षा अवधि के दौरान प्रतिनियुक्त कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिदिन प्रातः 7:00 बजे से संध्या 7:00 बजे तक उपस्थित रहकर परीक्षा से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करेंगे। किसी भी समस्या की सूचना तत्काल संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही, परीक्षा सेल में प्राप्त शिकायतों की प्रविष्टि कर उनका त्वरित निष्पादन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

मैट्रिक के 43 व इंटर के 35 केंद्रों पर आज से परीक्षा

HAZARIBAG : हजारीबाग सदर अनुमंडल अंतर्गत मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो रही है। इसके तहत मैट्रिक के 43 व इंटर के 35 केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी। इसे लेकर डीसी व एसएसपी के संयुक्त आदेश पर एसडीओ आदित्य पांडेय ने सभी परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू कर दी है। वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा 3 फरवरी से 17 फरवरी तक प्रथम पाली (सुबह 9.45 बजे से दोपहर 1 बजे तक) होगी। वहीं, इंटरमीडिएट सैद्धांतिक परीक्षा 3 फरवरी से 23 फरवरी तक द्वितीय पाली (दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक) संचालित होगी।

नवनिर्मित शिव मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा पांच से

KHUNTI : तोरपा प्रखंड के बास्की गांव में नवनिर्मित शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे गांव में उत्साह और भक्ति का वातावरण व्याप्त है। तीन दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ 5 फरवरी से होगा, जिसका समापन सात फरवरी, शनिवार को पूर्णाहुति के साथ किया जाएगा। इस अवसर पर गांव को आकर्षक झंडों और सजावट से सुसज्जित कर दिया गया है। मंदिर का रंगरोगन कार्य पूर्ण हो चुका है तथा रविवार को विधि-विधान से मंदिर के गुंबद पर पांच शूल स्थापित कर दिए गए हैं। आयोजन समिति के सदस्य राजनाथ सिंह, शिव कुमार सिंह, एमपी सिंह, राम नरेश सिंह, गोपाल सिंह, आनन्द सिंह, राजेंद्र सिंह, सोनू सिंह, सुरेंद्र सिंह, विक्रमा महतो सहित गांव के महिला-पुरुष इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने के लिए दिन-रात जुटे हुए हैं। समिति ने बताया कि बनारस से पधारे विद्वान आचार्यों की उपस्थिति में सभी अनुष्ठान वैदिक विधि-विधान से संपन्न कराए जाएंगे।

महापौर पद के लिए 11 ने किया नामांकन

DHANBAD : नगर निकाय चुनाव में महापौर के पद के लिए सोमवार को 11 प्रत्याशियों ने निवार्ची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता विनोद कुमार, सहायक निवार्ची पदाधिकारी बाल किशोर महतो तथा सहायक निवार्ची पदाधिकारी विशाल कुमार पांडेय के समक्ष नामांकन दाखिल किया। महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल करने वालों में लक्ष्मी देवी, रवि चौधरी, कृष्ण चंद्र सिंह राज, शमशेर आलम अंसारी, दिलीप कुमार, विनोद कुमार सिंह, डॉ नीलम मिश्रा, डॉ सुशील कुमार, प्रकाश कुमार, मोहम्मद जावेद इकबाल एवं रवि बुंदेला शामिल है।

रामगढ़ : सरकारी आदेश की अनदेखी कर रहे ईंट भट्ठा संचालक, 26 लोगों को थमाया गया नोटिस

लंबे समय से भट्ठा चलाने वालों को सरकार कर रही आगाह, नहीं सौंप रहे दस्तावेज

ईंट भट्ठा संचालक को नोटिस थमाते सीओ रमेश रविदास

AGENCY RAMGARH : सदर प्रखंड क्षेत्र में ईंट भट्ठा संचालकों द्वारा सरकारी आदेशों की लगातार अनदेखी किए जाने का मामला सामने आया है। इसे गंभीरता से लेते हुए अंचल अधिकारी (सीओ) रमेश रविदास ने अब भट्ठा मालिकों को व्यक्तिगत इश्तेहार जारी करना शुरू कर दिया है। रामगढ़ प्रखंड क्षेत्र में संचालित कुल 36 ईंट भट्ठा संचालकों को पूर्व में अपने-अपने भट्ठों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अब तक केवल सात संचालकों ने ही दस्तावेज जमा किए हैं। शेष संचालकों की ओर से किसी भी प्रकार का अनुपालन नहीं किया गया है।
सीओ रमेश रविदास ने सोमवार को बताया कि 26 ईंट भट्ठा संचालकों को व्यक्तिगत रूप से इश्तेहार उपलब्ध कराए गए हैं और सभी को 7 फरवरी तक अनिवार्य रूप से दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर को आयोजित जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त द्वारा ईंट भट्ठा संचालकों के दस्तावेजों की जांच का स्पष्ट आदेश दिया गया था।
उन्होंने बताया कि भट्ठा संचालकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ही उनकी वैधता और नियमों के अनुपालन की जांच की जानी है, लेकिन अधिकांश संचालकों की उदासीनता के कारण यह प्रक्रिया बाधित हो रही है।
अब तक दस्तावेज जमा करने वाले ईंट भट्ठा संचालकों में सुरेश महतो, वसंत कुशवाहा, जगन्नाथ महतो, महेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र कुमार साहू, सतीश गुप्ता और अजय सिंह उर्फ आजाद सिंह शामिल हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि तक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले ईंट भट्ठा संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस गिरफ्त में आरोपी • फोटोन न्यूज

हथियार के साथ राहुल सिंह गिरोह के दो अपराधी धराए

LATEHAR : लातेहार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सदर थाना क्षेत्र के कैमा गांव के पास से दो अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है।एसपी कुमार गौरव को मिली सूचना पर सोमवार को यह कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार अपराधियों में दीपक उरांव और अनिल उरांव शामिल है। पुलिस ने उनके पास से तीन बंदूक, 10 गोलियां सहित अन्य सामग्री बरामद किए। गिरफ्तार अपराधी लातेहार थाना क्षेत्र के इचाबार और परसही के रहने वाले हैं। दोनों अपराधी कुख्यात अपराधी संगठन राहुल सिंह गिरोह के सदस्य हैं। सोमवार को प्रेस वार्ता करते हुए डीएसपी अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए सदर थाना क्षेत्र के कैमा गांव के पास जमा हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस की एक टीम गठित की गई और अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की गई।

कपड़ों से लदा ट्रक पेड़ से टकराया, चालक की मौत

घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त ट्रक

PALAMU : जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया क्रशर मोड़ पर रांची-डालटनगंज मुख्य पथ पर सोमवार तडके सुबह एक ट्रक (डब्लूबी29जी 0911) महुआ पेड़ से टकरा गया। इस घटना में ट्रक के परखच्चे उड़ गए और मलबे में फंसकर चालक की मौत हो गई। ट्रक पर कपड़ा लोड था। वाहन रांची से डालटनगंज आ रहा था। सूचना मिलने पर सतबरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी में फंसे चालक के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरे मामले में जांच की जा रही है। चालक की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी देव प्रकाश राय (45) के रूप में हुई है। चालक लंबे समय से अपने परिवार के साथ पश्चिम बंगाल में रहता है। ट्रक पश्चिम बंगाल का है और वहीं से कपड़ा लेकर आ रहा था। सतबरवा ओपी प्रभारी विश्वनाथ कुमार राणा ने कि घटना तडके सुबह 4 बजे के आसपास हुई। इसके बाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ट्रक के मलबे में फंसी चालक के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच में भेजा। उसकी पहचान की और परिजनों को दे सूचना दी गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रक में कपड़ा लोड था और डाल्टनगंज के ही किसी व्यापारी का है।

तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर युवक की मौत

LOHARDAGA : किस्को रिचुघटा मुख्य सड़क पर रफ्तार का कहर देखने को मिला,जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक की जान ले ली,घटना जोबांग थाना के खरवा बिरहोर कॉलोनी के समीप घटी। ट्रक की चपेट में आने के कारण एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के मुर्मू निवासी सिताराम प्रसाद के पुत्र अनुज प्रसाद टीवीएस बाइक (जेएच 08 के 2382)से मुर्मू से खरचा की ओर आ रहा था। तभी खरचा धर्मकांटा के ओर जा रहे ट्रक ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया। युवक को पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से सदर अस्पताल लोहरदगा पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद ट्रक ड्राइवर धर्मकांटा के समीप ट्रक छोड़ फरार हो गया। दुर्घटना के बाद मृतक युवक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। दोनों वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

नगर निकाय चुनाव के बीच सिंह मेंशन में की गई बमबाजी, जांच में जुटी पुलिस

आवास के बाहर मौजूद लोग

AGENCY DHANBAD : आनगर निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच रविवार देर रात सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित सिंह मेंशन में बमबाजी की घटना सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की। मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 11:30 से 12 बजे के बीच बाइक सवार अपराधियों ने सिंह मेंशन को निशाना बनाते हुए दो बम फेंके। इनमें से एक बम सिंह मेंशन के गेट के अंदर जाकर ब्लास्ट हुआ, जबकि दूसरा बाहर ही गिर गया। बताया जा रहा है कि जहां बम ब्लास्ट हुआ, वहां आमतौर पर लोग बैठते हैं। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के वक्त झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, उनकी धर्मपत्नी झरिया विधायक रागिनी सिंह अपने कमरे में मौजूद थी। बमबाजी के बाद आवास परिसर में अफरातफरी मच गई। भीतर मौजूद लोग और सुरक्षा गार्ड बाहर की ओर दौड़े, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। सूचना मिलने के बाद सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और सबसे पहले पूर्व विधायक संजीव सिंह से घटना की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने सिंह मेंशन में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। जांच के लिए सीसीटीवी का डीवीआर पुलिस अपने साथ ले गई है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों के फुटेज भी खंगाल रही है। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि बमबाजी की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है।

झारखंड दिवस तीन किलोमीटर तक दिखी कार्यकर्ताओं की कतार, झामुमो ने किया शक्ति प्रदर्शन

बसंत सोरेन की अगुवाई में निकली विशाल रैली

सिदो-कान्हू को नमन करतीं लुईस मरांडी व रैली में शामिल झामुमो के नेता-कार्यकर्ता • फोटोन न्यूज

217 बसों में आए झामुमो कार्यकर्ता व समर्थक

झारखंड दिवस पर दुमका जिले के झामुमो कार्यकर्ता व समर्थक 217 बसों में सवार होकर पहुंचे थे। संथाल परगना के दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा समेत राज्य के अन्य जिलों से भी काफी संख्या में कार्यकर्ता आए थे। झारखंड दिवस के आयोजन में वही पुरानी रौनक दिखी, सिर्फ पहली बार दिशोम गुरु शिबू सोरेन की कमी सबको खली। शिब सोरेन ने ही इस आयोजन की शुरूआत की थी।

PHOTON NEWS DUMKA : झामुमो का 47वां झारखंड दिवस सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरूआत विशाल रैली से हुई, जिसकी अगुवाई विधायक बसंत सोरेन ने की। पारंपरिक वेशभूषा में एसपी कॉलेज मैदान से गांधी मैदान तक लगभग तीन किलोमीटर तक कार्यकर्ताओं-समर्थकों की कतार दिखी। इसमें दुमका के सांसद नलिन सोरेन, जामा की विधायक प्रो. डॉ. लुईस मरांडी, शिकारीपाड़ा के विधायक आलोक सोरेन, बोरियो के विधायक धनंजय सोरेन, दुमका के जिला अध्यक्ष शिव कुमार बास्की आदि भी रहे। तीर-धनुष व ढोल-नगाड़े के साथ आए झामुमो कार्यकर्ताओं के हाथ में पार्टी के सुप्रीमो रहे दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर वाला झंडा था। डीजे की धुन पर झूमते हुए कार्यकताओं का हुजूम सिदो-कान्हू चौक पहुंचा, तो वहां दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने सिदो-कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रैली यहां से टीन बाजार चौक होते हुए रैली गांधी मैदान में जाकर जनसभा में तब्दील हो गई। रैली-जुलूस का स्वागत शहरवासियों ने पुष्पवर्षा से किया। संथाल परगना के कोने-कोने से आए हजारों लोग देर रात तक गांधी मैदान में जनसभा संपन्न होने तक जमे रहे। जनसभा में झामुमो अपने एजेंडा को मजबूती से रखा। केंद्र सरकार से अपना हक-अधिकार लेने की बात जोरदार तरीके से रखी। गांधी मैदान को एलईडी हैलोजन से चकाचक किया गया था। ठंड से बचाव के लिए सभास्थल पर जगह-जगह अलाव भी जलाए गए थे।

झारखंड आंदोलनकारियों ने भी किया नमन

DUMKA : सिदो-कान्हू चौक पर स्थापित शहीद सिदो-कान्हू की प्रतिमा पर झारखंड आंदोलनकारियों ने भी श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इनमें अनूप कुमार सिन्हा, मनोज पांडेय, अरुण मंडल, बुधन मरांडी, अमित दे, जियालाल राय, रंजन कुमार सहाय, देवशंकर दे आदि भी शामिल थे। दुमका के टीन बाजार चौक पर झामुमो नेता राजेश कुमार राउत की अगुवाई में रैली पर पुष्पवर्षा की गई। रैली को संपन्न कराने वालों में झामुमो के जिला सचिव निशित वरण गोलदार, संगठन मंत्री रवि यादव, जिला प्रवक्ता मो. सलाम अंसारी, केंद्रीय कमेटी के सदस्य राजेश कुमार सिंह, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुनीता मरांडी, सविता टुडू, प्रिया रक्षित, कृष्णा देवी, इंदु चौबे, पराक्रम शर्मा, मनोज कामत, चंदन भुवानियां, दीपक केवट आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सेरेंगसिया का अधिकार : चम्पाई

शहीद स्थल पर पूर्व सीएम चम्पाई सोरेन • फोटोन न्यूज

CHAIBASA : पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोन्टो प्रखंड अंतर्गत सेरेंगसिया घाटी पहुंचे, जहां उन्होंने वीर पोटो हो समेत कोल विद्रोह के अमर बलिदानियों को श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वीर शहीदों को नमन करने के बाद पूर्व सीएम ने उनके बलिदान को याद करते हुए कहा कि जिस जल, जंगल, जमीन एवं परंपराओं की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ विद्रोह किया, वह आज भी संकट में है। झारखंड की गठबंधन सरकार को आदिवासी विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार ने कई दशकों से चली आ रही परंपरा को तोड़ कर, सेरेंगसिया के ग्रामीणों द्वारा हर साल किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद के आयोजनों को जबरन रद्द करा दिया। उनका कसूर सिर्फ यही था कि उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के तौर कर बुलाया था। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुये कहा कि भोगनाडीह से लेकर सेरेंगसिया तक, शहीदों के परिवारों तथा पारंपरिक ग्राम प्रधानों के निर्णयों को दरकिनार कर, पुलिस के दम पर सरकारी आदेशों को थोपने का जो प्रयास चल रहा है, उसे आदिवासी समाज बर्दास्त नहीं करेगा।

BRIEF NEWS

सुधार नहीं होने पर सीएस के वेतन पर लगाई जाएगी रोक : अपर मुख्य सचिव

RANCHI : स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आईपीएच सभागार,नामकुम में सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की समीक्षा में कम खर्च पर नाराजगी जताते हुए शून्य प्रगति वाले जिलों पर कारण बताओ और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सुधार नहीं होने पर संबंधित सिविल सर्जनों के वेतन पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की प्रशंसा की गई और पिछड़े जिलों को उनसे सीख लेने का निर्देश दिया गया। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि न्यूनतम 60 प्रतिशत राशि का उपयोग अनिवार्य है तथा 13 फरवरी तक नगर परिषद और उप विकास आयुक्त द्वारा खर्च की गई राशि का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करना होगा।

रितेश पातर ने बुंडू नगर अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन

RANCHI : झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) समर्थित प्रत्याशी रितेश पातर ने सोमवार को बुंडु नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। रांची समाहरणालय में आयोजित नामांकन प्रक्रिया के दौरान उन्होंने दो सेटों में अपना नामांकन भरा। इस दौरान रितेश पातर के समर्थक हेमंत कुमार, प्रस्तावक दिनेश महतो, मुख्तार खान, राजू सेठ, तिजु महतो, राजन सींह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं शुभचिंतक मौजूद थे। इस दौरान समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया। मौके पर पार्टी के कार्यकताओं ने नारेबाजी करते हुए जीत का दावा किया। जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि संगठन पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में उतर रहा है।

अश्विनी महतो की प्रतिमा स्थापना को लेकर हुआ भूमि पूजन

RANCHI : तमाड़ प्रखंड के चिरूडीह मुचिडीह बाजार में पूर्व पंचायत समिति सदस्य सह झारखंड आंदोलनकारी स्व. अश्विनी कुमार महतो की स्मृति में प्रतिमा स्थापित करने को लेकर भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि ऋषिकेश महतो ने स्व. अश्विनी कुमार महतो ने कहा कि झारखंड राज्य के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने हमेशा अपने पंचायत के प्रत्येक वर्ग के लोगों की सेवा की और अंतिम समय तक इसी मार्ग पर चले। कार्यक्रम में मुखिया राजकिशोर सिंह मुंडा, उदय सिंह मुंडा, मनीष कुमार सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे।

नेशनल डिफेंस कॉलेज के प्रतिनिधिमंडल से राज्यपाल ने किया संवाद, बोले-

राष्ट्रीय सुरक्षा व रणनीतिक अध्ययन का प्रतिष्ठित संस्थान है एनडीसी

भारत ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है इसका गौरवशाली इतिहास

पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण के केंद्र हैं राज्य की झीलें, झरने और धार्मिक स्थल

PHOTON NEWS RANCHI : सोमवार को लोकभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी) के प्रतिनिधिमंडल से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने एनडीसी को राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन का एक प्रतिष्ठित संस्थान बताया। साथ ही कहा कि इसका गौरवशाली इतिहास भारत ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने झारखंड को वीरों की धरती बताते हुए कहा कि यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदा, समृद्ध संस्कृति और विविध परंपराओं से परिपूर्ण है। उन्होंने विशेष रूप से झारखंड के जनजातीय समाज की चर्चा करते हुए कहा कि यहां की जनजातीय परंपरा विश्वप्रसिद्ध हैं। जनजातीय समुदाय प्रकृति-प्रेमी होता है। जिसकी झलक उनके पर्व-त्योहारों, नृत्य-संगीत और जीवन शैली में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। राज्य के लोग सरल, परिश्रमी, साहसी और अतिथि-सत्कार के लिए जाने जाते हैं। राज्यपाल ने झारखंड की पर्यटन संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य में झीलें, झरने और विश्वप्रसिद्ध धार्मिक आस्था केंद्र पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण हैं। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से समय मिलने पर इन पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने का आग्रह किया। राज्यपाल ने यह भी जानकारी दी कि लोक भवन स्थित उद्यानों को आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। उद्यान में 100 से अधिक प्रजातियों के गुलाब उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि वे स्वयं आगंतुकों से संवाद कर उनके सुझाव जानने का प्रयास करते हैं, ताकि उद्यान को और बेहतर बनाया जा सके।

नेशनल डिफेंस कॉलेज के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करते राज्यपाल संतोष गंगवार

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की जरूरत

उच्च शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी सुधार की आवश्यकता है, जिस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी पर उन्होंने 'लखपति दीदी योजना' का उल्लेख करते हुए कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी इस दौरान विचार-विमर्श हुआ।

प्रतिनिधिमंडल में 17 सदस्य

संवाद के दौरान प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख मेजर जनरल हरतेज सिंह बजाज ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में कुल 17 सदस्य शामिल हैं। जिनमें इथोपिया, बांग्लादेश, फ्रांस, ब्राजील और जापान के पांच विदेशी सदस्य भी सम्मिलित हैं। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य झारखंड राज्य के बारे में अधिक से अधिक जानने और अध्ययन करने के इच्छुक हैं। सदस्यों ने झारखंड में खेलों की असीम संभावनाओं की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि हॉकी और तीरंदाजी जैसे खेलों में राज्य की विशेष पहचान है। यदि कम उम्र से ही प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया जाए तो राज्य और बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इस पर राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में खेलों के प्रति विशेष अभिरुचि है। हॉकी, तीरंदाजी और फुटबॉल में राज्य निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इसी राज्य से हैं। राज्य की बेटियां हॉकी के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया लीग का सफल आयोजन भी राज्य में हुआ है।

हाईकोर्ट में रिम्स ने कहा- नई कंपनी को दी गई बायो मेडिकल वेस्ट उठाने की जिम्मेदारी

PHOTON NEWS RANCHI : राजधानी रांची स्थित राजेंद्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान (रिम्स) में बायो मेडिकल वेस्ट के उठाव का काम अब नई कंपनी ने संभाल लिया है। इस संबंध में रिम्स ने झारखंड उच्च न्यायालय को शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी दी। रिम्स ने सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि पुरानी कंपनी का कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को समाप्त हो गया और अब यह काम मेसर्स मेडिकेयर एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, लोहरदगा कर रही है। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने की। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता समावेश देव ने पक्ष रखा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अधिवक्ता रिचा संचित ने अदालत को बताया कि झारखंड के कई जिलों में बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं और अस्पतालों एवं नर्सिंग होम को क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया जा चुका है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रार्थी को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई 16 फरवरी को एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करें, जिसमें पूर्व आदेश, उसका अनुपालन और सुझाव शामिल हों। उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई में अदालत ने रिम्स की ओर से आदेश का अनुपालन न करने पर नाराजगी जताई थी। खंडपीठ ने रिम्स डायरेक्टर को निर्देश दिया था कि वे बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए टेंडर पूरा करने के कदमों की जानकारी अगली सुनवाई में शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करें। प्रार्थी की याचिका में झारखंड के अस्पताल, क्लिनिक और नर्सिंग होम से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का निष्पादन एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स के तहत सुनिश्चित कराने का आग्रह किया गया है।

वर्द्धमान कंपाउंड में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा, पिता-पुत्र समेत तीन गिरफ्तार

PHOTON NEWS RANCHI : रांची के लालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोवर वर्द्धमान कंपाउंड (धोबी घाट) में शनिवार रात हुई मधेश्वर सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुन्ना कच्छप और उसके दो बेटे अमन कच्छप तथा अनिकेत कच्छप शामिल हैं।

सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में नगर पुलिस उपाधीक्षक केवी रमण ने बताया कि मामूली विवाद के बाद दो सगे भाइयों ने अपने पिता के साथ मिलकर बुजुर्ग मधेश्वर सिंह की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राकेश रंजन के निर्देश पर गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के भीतर सभी नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, 31 जनवरी की रात लोवर वर्द्धमान कंपाउंड निवासी मधेश्वर सिंह टहलने निकले थे। इसी दौरान मोहल्ले के ही अमन और अनिकेत कच्छप से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों भाइयों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।

मामले की जानकारी देते नगर पुलिस उपाधीक्षक केवी रमण व अन्य ● फोटोन न्यूज

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मांडर-चान्हो में चार विकास योजनाओं का किया शिलान्यास

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के मांडर और चान्हो प्रखंड में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट एवं सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मद से बनने वाली चार विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। मांडर प्रखंड में मंत्री ने डीएमएफटी मद से सरकारी मिडिल स्कूल में आठ नए वर्ग कक्षों के निर्माण तथा झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय, मांडर में तीन अतिरिक्त कमरों के निर्माण की योजना का शिलान्यास किया। वहीं चान्हो प्रखंड में सीसीएल के सीएसआर मद से राजकीय मध्य उत्क्रमित विद्यालय हूटार में सोलर पावर डीप बोरिंग एवं डायनिंग शेड निर्माण तथा डीएमएफटी मद से राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चान्हो में आठ नए कक्षों के निर्माण की योजना की आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विद्यालयों में कक्षा कक्षों एवं बुनियादी सुविधाओं का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि डीएमएफटी मद का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है, ताकि इसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचे। मंत्री ने शिक्षा को विकसित समाज की आधारशिला बताते हुए कहा कि बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है और अनुशासन के साथ अध्ययन करने से सफलता सुनिश्चित होती है।

शिलान्यास करतीं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की व अन्य

सदानंद सेवा धाम पहुंचीं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने की सेवा कार्यों की सराहना

PHOTON NEWS RANCHI : रांची के पुंदाग स्थित प्रणामी ट्रस्ट की ओर से संचालित सदानंद सेवा धाम परिसर में सोमवार को सद्गुरु कृपा अपना घर आश्रम का दौरा करने राज्य की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह पहुंचीं। इस अवसर पर ट्रस्ट पदाधिकारी एवं आश्रम परिवार ने उनका स्वागत किया। मंत्री ने आश्रम का भ्रमण कर वहां रह रहे निराश्रितजनों के लिए किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। उन्होंने आश्रम में उपलब्ध स्वच्छता, रहन-सहन, भोजन, चिकित्सा, वस्त्र सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन कर संतोष व्यक्त किया। मंत्री ने इस मौके पर कहा कि समाज के उपेक्षित और जरूरतमंद वर्गों के लिए इस प्रकार की सेवा सच्चे अर्थों में मानवता की सेवा है और यह अन्य सामाजिक संस्थाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। इस दौरान उन्होंने आश्रम में रह रहे सभी निराश्रितों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उनके साथ भोजन भी किया। मंत्री ने आश्रम प्रबंधन को हर संभव सरकारी सहयोग देने का आश्वासन दिया। ट्रस्ट के प्रवक्ता संजय सर्राफ ने बताया कि स्वामी सदानंद महाराज के सानिध्य में वर्तमान में आश्रम में 42 निराश्रित रह रहे हैं, जिनकी देखभाल और सेवा आश्रम परिवार द्वारा निरंतर की जा रही है। मंत्री ने अपने दौरे के दौरान आश्रम परिसर में संचालित गौशाला का भी निरीक्षण किया और गौ सेवा को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया।

रमा खलखो मेयर पद के लिए तीन को करेंगी नामांकन, मांगा समर्थन

RANCHI : कांग्रेस नेत्री और पूर्व मेयर रमा खलखो नगर निगम चुनाव के लिए मंगलवार को मेयर पद के लिए नामांकन करेंगी। यह जानकारी उन्होंने सोमवार को रांची स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में दी। मौके पर उन्होंने राजधानीवासियों से मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि वे शहर की जनता से पुनः आशीर्वाद और समर्थन की आकांक्षा रखती हैं। उन्होंने अपने पूर्व कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि वर्ष 2008 में जनता के सहयोग से वे मेयर चुनी गई थीं और उस दौरान उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ नगर निगम के माध्यम से जनहित में कार्य किया।

झारखंड में महाशिवरात्रि तक रहेगी ठंड इसके बाद तापमान में तेजी से होगी वृद्धि

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड में महाशिवरात्रि (15 फरवरी) तक ठंड बने रहने की संभावना है। इसके बाद मौसम में बदलाव के साथ गर्मी धीरे-धीरे बढ़ेगी। मौसम विभाग ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

मौसम विभाग के अनुसार, महाशिवरात्रि के बाद तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन इसी दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना भी है। बारिश होने से तापमान में थोड़ी कमी आएगी, फिर उसके बाद तापमान में तेजी से वृद्धि होगी।

राज्य के विभिन्न हिस्सों में वर्तमान में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। बोकारो और चाईबासा में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक है, जबकि रांची और जमशेदपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक है। वहीं, डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम है और अधिकतम तापमान लगभग सामान्य के बराबर है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 29.4 डिग्री और सबसे कम तापमान गुमला में 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

सोमवार को रांची और आसपास के इलाकों में सुबह से आंशिक बादल छाए रहे और मध्यम गति की हवा चली। धूप में जाने पर गर्मी का एहसास हुआ, जबकि छाया में ठंडक महसूस की गई।

सोमवार को रांची में अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री, जमशेदपुर में अधिकतम 28.4 और डिग्री न्यूनतम 14.4 डिग्री, डाल्टनगंज में अधिकतम 27 डिग्री और न्यूनतम 9.1 डिग्री, बोकारो में अधिकतम 27.5 और न्यूनतम 10.1 डिग्री एवं चाईबासा में अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

प्राकृतिक सौंदर्य आम लोगों के लिए उद्यान खुलते ही आकर्षण का केंद्र बन गया लोकभवन

फूलों की बहार, सैकड़ों लोगों ने लिया प्रकृति का आनंद

PHOTON NEWS RANCHI : राजधानी रांची स्थित लोक भवन उद्यान के सोमवार को आम लोगों के लिए खुलते ही आकर्षण का केंद्र बन गया। उद्यान के दीदार के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच खुशनुमा पल बिताए। रंग-बिरंगे फूलों, सुसज्जित गार्डन और फव्वारों की खूबसूरती ने हर किसी को मोहित कर दिया। उद्यान में घूमने पहुंचे लोग इसकी सुंदरता की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सुबह से ही लोक भवन उद्यान के प्रवेश द्वार पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। परिवार के साथ पहुंचे लोग, युवा वर्ग और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उत्साह के साथ उद्यान में घूमते नजर आए। फूलों की क्यारियों और हरियाली के बीच हर कोई अपनी तस्वीर लेने को लेकर खासा क्रेजी दिखा। मोबाइल कैमरों और सेल्फी के जरिए लोग यादगार पलों को कैद करते रहे। लोक भवन उद्यान के खुलने से पहले ही प्रकृति प्रेमी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जैसे ही उद्यान आम जनता के लिए खोला गया, लोग अनुशासित तरीके से अंदर प्रवेश करते नजर आए। विद्यार्थियों में खास उल्लास देखने को मिला। वही बुजुर्गों ने शांत वातावरण में टहलते हुए प्रकृति का आनंद लिया। कई लोग सुबह की सैर के दौरान उद्यान की हरियाली में समय बिताते दिखे।

लोक भवन उद्यान में इस बार गुलाबों की खास बहार देखने को मिल रही है। उद्यान में 30 हजार से अधिक गुलाब के फूल मौजूद हैं। लाल, पीले और गुलाबी गुलाबों से पूरा परिसर रंगीन नजर आ रहा है। खास आकर्षण उन पौधों का है, जिनमें एक ही पेड़ पर अलग-अलग रंगों के गुलाब खिले हुए हैं। यह दृश्य लोगों को रुकने और तस्वीर लेने के लिए मजबूर कर रहा है।

उद्यान में स्वच्छता और अनुशासन की जरूरत : राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि लोक भवन उद्यान आम नागरिकों के लिए प्रकृति के करीब समय बिताने का एक बेहतर अवसर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नागरिक उद्यान की स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करेंगे। इसके साथ ही, उन्होंने आगंतुकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर उद्यान को और बेहतर बनाने की बात कही।

निकाय चुनाव व बोर्ड परीक्षा एक ही दिन एसोसिएशन की आपत्ति

RANCHI : झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने 23 फरवरी को एक ही दिन नगर निकाय चुनाव और झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक बोर्ड) की बोर्ड परीक्षा आयोजित किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। एसोसिएशन ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि चुनाव और बोर्ड परीक्षा दोनों ही बड़े प्रशासनिक आयोजन हैं, जिनमें शिक्षकों, विद्यालय भवनों, प्रशासनिक अमले, परिवहन और सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक जरूरत होती है। ऐसे में एक ही दिन दोनों कार्यक्रमों का आयोजन छात्रों पर अनावश्यक मानसिक दबाव डालेगा और प्रशासनिक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करेगा।

शब-ए-बारात आज, रातभर मस्जिदों में की जाएगी इबादत, तैयारियां पूरी

PHOTON NEWS RANCHI : शब-ए-बारात का पर्व झारखंड समेत रांची जिले में तीन फरवरी मंगलवार की शाम को मनाई जाएगी। इसको लेकर मुस्लिम बहुल इलाकों में खासा तैयारी देखने को मिल रही है। मस्जिदों और कब्रिस्तानों की साफ-सफाई के साथ साज-सज्जा आदि करने में लोग लगे रहे। वहीं घरों में भी महिलाएं सफाई के साथ ही पर्व पर बनाए जाने वाले पकवान आदि की तैयारी में जुटी रहीं। वहीं खाद्य सामाग्री की खरीद-फरोख्त में भी लोग मशगूल रहे। इससे बाजारों में देर शाम तक रौनक बनी रही। इस्लामी कैलेंडर के शाबान महीने की 15वीं, शब(रात) को मनाई जाने वाली शब-ए-बारात एक पाक रात है। इस रात में मुसलमान इबादत में मशगूल रहते हैं। मस्जिदों में नमाज अदा की जाती है। कुरान की तिलावत की जाती है। साथ ही कब्रिस्तान में जाकर अपने पूर्वजों की मगफिरत की दुआएं की जाती है। झारखंड के प्रख्यात कारी कुरान हजरत कारी सोहेब अहमद ने बताया कि इस रात को तौबा और इबादत की खास रात मानी जाती है। इसमें लोग सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं। इस दिन मस्जिदों और घरों में पूरी रात इबादत की जाती है।

समाचार सार

नप अध्यक्ष के लिए सन्नी उरांव ने किया नामांकन

CHAKRADHARPUR : नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए विधायक सुखराम उरांव के पुत्र व झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष सन्नी उरांव ने सोमवार को नामांकन किया। वे गाजे-बाजे और समर्थकों के भारी हुजूम के साथ नामांकन करने पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा सहित तमाम शहीदों की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि समरेश सिंह उर्फ गुड्डू, नगर अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन, शेषनारायण लाल, बापी दत्ता, पंकज शर्मा, सरवार निहाल, जुगनू रहमान, भारत सिंह, चंदन विश्वकर्मा, अमर शर्मा, राजेश गुप्ता, अहमद हुसैन, गोल्डी सिंह, गोनू जायसवाल आदि भी शामिल थे।

नप अध्यक्ष के लिए उदय माझी ने भरा पर्चा

CHAKRADHARPUR : सांसद जोबा मांझी के पुत्र उदय माझी ने सोमवार को नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। एलआईसी बिल्डिंग जुलूस निकालकर उदय माझी समर्थकों के साथ अनुमंडल कार्यालय, आसनलिया पहुंचे। जुलूस के दौरान उदय माझी ने तमाम शहीदों की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्होंने निर्वाचन पदाधिकारी (डीसी-एलआर) जेजे मुंडू को नामांकन पत्र सौंपा। इस मौके पर तुषार नंदा, गोपी चाकी, राज मिश्रा, राजेश शर्मा, आनंद कसेरा समेत कई समर्थक मौजूद थे।

केयू के सीनेट सदस्य बने 6 विधायक

GHATSILA : विधायक सोमेश चंद्र सोरेन सहित कोल्हान के 6 विधायक कोल्हान विश्वविद्यालय के सीनेट (अधिषद) सदस्य बनाए गए हैं। इनका मनोनयन झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 के तहत झारखंड विधानसभा सचिवालय से 20 जनवरी को जारी किया गया था। इन विधायकों में निरल पुरती (मझगांव), सविता महतो (ईचागढ़), मंगल कालिंदी (जुगसलाई), सुखराम उरांव (चक्रधरपुर) व सोनाराम सिंकू (जगन्नाथपुर) भी शामिल हैं।

एसडीयू में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम

GHATSILA : सोना देवी विश्वविद्यालय के फामेर्सी विभाग ने सोमवार को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। संदीप कुमार व मेघा दास के संचालन में हुए कार्यक्रम में छात्रा कृतिका बाल्मीकि व दीपा कुमारी ने गणतंत्र दिवस पर विचार व्यक्त किया। इसके उपरांत मौसमी कुमारी ने देशभक्ति गीत पर नृत्य, बालेश्वरी मंडी ने कविता पाठ, शारदा रानी ने स्लो डांस और मेघा दास, शारदा रानी व नेहा ठाकुल ने राष्ट्रभक्ति पर आधारित नाट्य प्रस्तुति दी।

ब्रह्माकुमारीज में शुरू हुई मेडिटेशन पर कार्यशाला

JAMSHEDPUR : प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सोनारी में मेरीन ड्राइव स्थित यूनिवर्सल पीस पैलेस रिट्रीट सेंटर में सोमवार को आठ दिवसीय प्रशिक्षण व कार्यशाला शुरू हुई। कोल्हान क्षेत्र की वरिष्ठ राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी अंजू ने कहा 4 व 5 फरवरी को सेंटर से जुड़े सभी भाई-बहनों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र होगा। 6, 7 व 8 फरवरी को विभिन्न राज्यों के लोग हिस्सा लेंगे। कोल्हान क्षेत्र के हल्दीपोखर, बलरामपुर, बहरागोड़ा, गालूडीह, चांडिल, टाटीसिलवे, पतरातू, हजारीबाग, बरही आदि से भी भाई-बहन शामिल होंगे।

नक्शा विचलन करने वाले 24 भवनों पर अतिक्रमण हटाने का मिला था ऑर्डर, जेएनएसी ने की कार्रवाई

हाईकोर्ट के आदेश पर इमारतों में शुरू हुई तोड़फोड़, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

PHOTON NEWS JSR : झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर जेएनएएसी ने सोमवार को बिष्टुपुर और साकची के बाराद्वारी में नक्शा विचलन करने वाली दो इमारतों में तोड़फोड़ की जो कार्रवाई शुरू की थी, वह सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही रोक दी गई। यह कार्रवाई सुबह 11 बजे आरंभ की गई थी और लगभग दो बजे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। इसके बाद कार्रवाई रोक दी गई है। अब नक्शा विचलन वाली इमारतों पर तब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट का अगला आदेश नहीं आ जाता।

गौरतलब है कि हाई कोर्ट के आदेश पर सुबह जमशेदपुर शहर की 24 इमारतों से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया था। जेएनएसी की इस कार्रवाई में सुबह लगभग 11 बजे से दो टीमें जुट गई थीं। एक टीम बिष्टुपुर का इलाका देख रही थी तो दूसरी टीम साकची का इलाका। बिष्टुपुर में रमाडा होटल के बगल में पांचमंजिला बिल्डिंग में नक्शा विचलन पाया गया है। जेएनएसी से इसका जी प्लस थ्री का नक्शा पास है, जबकि यहां पांच फ्लोर बना दिया गया है। इसके दो फ्लोर तोड़े जाएंगे। जेएनएसी के उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार खुद यहां मौजूद थे। इसके अलावा, भारी पुलिस फोर्स भी लगाई गई थी, ताकि किसी तरह का विरोध अगर हो तो उसका सामना किया जा सके। बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर पर बने एक कमरे की छत को हथौड़े से धीरे-धीरे तोड़ने का काम चल रहा था। तभी, दो बजे अचानक खबर आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके बाद कार्रवाई रोक दी गई। इसके अलावा, साकची में बाराद्वारी समेत अन्य इलाके में चिह्नित इमारतों को तोड़ा जाना था। बाराद्वारी की एक इमारत से नक्शा विचलन खत्म करने की कार्रवाई शुरू की गई थी। जेएनएसी के नगर प्रबंधक ने बताया कि यह इमारत होल्डिंग नंबर 47 पर बनी है। इसका नक्शा जेएनएसी से ग्राउंड प्लस है। मगर, इसे पांच मंजिला बना दिया गया है। इसके ऊपर के दो फ्लोर अवैध तरीके से नक्शा में विचलन कर बनाए गए हैं। यहां भी जेएनएसी की टीम कटर और हथौड़े के सहारे ऊपर के फ्लोर को तोड़ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। इसके बाद कार्रवाई रोक दी गई है।

जेएनएसी के उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही थी। 24 इमारतों में नक्शा विचलन पाया गया है। किसी में फ्लोर का विचलन है, तो किसी में नक्शे के अनुरूप कार्य नहीं हुआ है। किसी इमारत में बेसमेंट को पार्किंग के तौर पर नक्शे में दिखाया गया है।

बिष्टुपुर स्थित इसी भवन में तोड़फोड़ करते मजदूर ● फोटोन न्यूज

हाईकोर्ट में दायर की गई थी रिट

गौरतलब है कि इस मामले में हाई कोर्ट में रिट दायर की गई थी। इसी मामले में हाई कोर्ट ने नक्शा विचलन हटाने का आदेश दिया है। इसी के बाद 24 इमारतों की सूची तैयार की गई है। जेएनएसी के उपनगर आयुक्त ने बताया कि सभी इमारत के मालिकों को नोटिस जारी कर दी गई है। सभी को तीन नोटिसें दी गई हैं और इसी के बाद कार्रवाई शुरू की गई थी।

तोड़ी जा रही पांच मंजिला अवैध इमारत

रमाडा होटल के बगल में जो बिल्डिंग तोड़ी जा रही है उसके मालिक का कहना था कि उन्होंने नक्शा विचलन को नियमित करने के लिए जुमार्ना भी भरा था। लेकिन इसके बावजूद उनकी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। गौरतलब है कि कुछ साल पहले नगर विकास विभाग की तरफ से नक्शा विचलन को नियमित करने के लिए एक आदेश जारी किया गया था। लेकिन उसकी कुछ शर्तें थीं।

बिना आवेदन मंजूर हुए जमा कर दिया था पैसा

ज्यादातर इमारतें उन शर्तों में नहीं आ रही थीं। इसके बावजूद लोगों ने अपनी तरफ से कुछ रकम सरकार के खाते में जमा कर दी और उसी को इमारत के मालिक यह बता रहे हैं कि उन्होंने सरकार को नियमितीकरण का पैसा दिया है। जबकि, जेएनएसी के अधिकारी पहले से कहते रहे हैं कि जब उनसे पैसा मांगा ही नहीं गया तो उन्होंने पैसा जमा कैसे कर दिया। नियमानुसार मलिक को आवेदन देना था। इसके बाद जेएनएसी के इंजीनियर मौके का जायजा लेते और यह बताते हैं कि यह विचलन नियमित होने योग्य है। इसी के बाद पैसा जमा होना था। लेकिन लोगों ने बिना जांच कराए ही पैसा जमा कर दिया था।

कदमा में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी पर गाड़ी चढ़ाने वाले तीन गिरफ्तार

PHOTON NEWS JSR : कदमा में टोल ब्रिज पर तैनात पुलिसकर्मी हीरालाल महतो पर कुछ अपराधियों ने 4 जनवरी को डिजायर कार चढ़ा दी थी। पुलिस ने इस मामले के आरोपी तीन युवकों को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। पकड़े गए युवक टुइलाडुंगरी के अमनदीप सिंह, कदमा के फार्म एरिया क्वार्टर नंबर-22 निवासी अंकित मुखी और कदमा के धतकीडीह स्ट्रेट माइल रोड निवासी आदित्य मुखी हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की मारुति सुजुकी डिजायर भी जब्त कर ली है। तीनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। कदमा के थाना प्रभारी ने बताया कि 4 जनवरी को जवान हीरालाल महतो टोल ब्रिज पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार कार आती हुई दिखाई दी। हीरालाल महतो ने कार को रोकने का इशारा किया। लेकिन, कार नहीं रुकी। बल्कि कार ने हीरालाल महतो को टक्कर मार दी। इस हादसे में हीरालाल महतो गंभीर रूप से घायल हुए। हीरालाल महतो के आवेदन पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ जान मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और मुखबिरों का जाल फैलाया। पुलिस को सूचना मिली थी कि घटना को अंजाम देने में गोलमुरी के टुइलाडुंगरी का रहने वाला अमनदीप सिंह शामिल है। इस पर पुलिस ने सबसे पहले अमनदीप सिंह को उठाया। उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सारी बात उगल दी। उसने बताया कि इस घटना में उसके साथ कदमा के फार्म एरिया स्टाफ क्वार्टर रोड का रहने वाला अंकित मुखी और कदमा के ही धतकीडीह स्ट्रेट माइल रोड का रहने वाला आदित्य मुखी भी शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने अमनदीप और आदित्य को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ● फोटोन न्यूज

गिरिडीह में रंगकर्मियों ने किया 'सुदामा के चावल' का मंचन

JAMSHEDPUR : गिरिडीह की प्रतिष्ठित नाट्य संस्था कला संगम द्वारा आयोजित 25वें अखिल भारतीय बहुभाषी नाट्य एवं लोकनृत्य महोत्सव (29 जनवरी से 1 फरवरी) में जमशेदपुर की नाट्य संस्था पथ (पीपुल्स एसोसिएशन फॉर थिएटर) के कलाकारों ने अंतिम दिन हरिशंकर परसाई की प्रसिद्ध कृति नाटक 'सुदामा के चावल' का मंचन किया। नाट्य संस्था के निर्देशक मो. निजाम प्रतियोगिता के निर्णायक भी थे। इस नाटक में सुदामा-कृष्ण प्रसंग के पुनर्पाठ के माध्यम से सत्ता, नौकरशाही और नैतिक पतन पर तीखा व्यंग्य प्रस्तुत किया। दान और मित्रता की पारंपरिक कथा को पलटते हुए इस प्रस्तुति ने 'दो मुट्ठी चावल' की कथा को भ्रष्ट तंत्र, 'खुरचन' की संस्कृति, छवि-प्रबंधन और समझौतापरस्त नैतिकता के रूपक के रूप में सामने रखा। सुदामा के आत्म-स्वीकृत 'सौदे' के जरिए नाटक ने आज की व्यवस्था में व्याप्त लालच, दिखावे और प्रशासनिक अमानवीयता को प्रभावी ढंग से उजागर किया, जहां करुणा की जगह प्रचार और सत्य की जगह सुविधाजनक मिथक स्थापित हो जाते हैं।

गोविंदपुर : कुएं में गिरकर बच्चे की मौत, जांच में जुटी पुलिस

JAMSHEDPUR : पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत परसुडीह थाना क्षेत्र के छोटागोविंदपुर स्थित बजरंग नगर में पांच वर्षीय बच्चे की कुएं में गिरने से मौत हो गई है। बच्चे का नाम शिवम कैवर्तो है। घटना रविवार देर रात की है। जैसे ही लोगों को पता चला कि बच्चा कुएं में गिर गया है, इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने टाटा स्टील के गोताखोर मजहरुल बारी को बुलवाया। मजहरुल बारी देर रात मौके पर पहुंचे और पुलिस के आग्रह पर कुएं में जाकर कड़ी मशक्कत के बाद शिवम कैवर्तो को बाहर निकाला। लेकिन, तब तक शिवम कैवर्तो की मौत हो चुकी थी। अभी यह नहीं पता चल पाया है कि बच्चा कुएं में कैसे गिरा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कुएं में डूबा शिवम सरायकेला-खरसावां जिले के जोहाडीह गांव का रहने वाला था। वह स्कूल की छुट्टी होने पर अपने नाना के यहां घूमने आया था। वह रविवार को बच्चों के साथ खेलने निकला था। लेकिन, देर तक नहीं लौटा तो लोगों ने खोजबीन शुरू की। तब पता चला की वह कुएं में गिर गया है।

शिवम कैवर्तो की फाइल फोटो

एक चालक पर कार्रवाई के विरोध में स्कूली वाहन चालकों ने की हड़ताल

बिरसानगर थाना ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में की है कार्रवाई

PHOTON NEWS JSR : जमशेदपुर में सोमवार से स्कूल वैन और स्कूल ऑटो चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। इस हड़ताल की वजह से अभिभावकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे टेल्को, गोलमुरी, बिरसानगर, बारीडीह, टिनप्लेट आदि इलाके ज्यादा प्रभावित रहे। अभिभावकों को अपने बच्चों को खुद स्कूल पहुंचाना पड़ा और वहां से छुट्टी होने पर घर लाना पड़ा। बताया जा रहा है कि करीब 2000 स्कूली वैन और ऑटो चालक सोमवार को हड़ताल पर रहे। ऑटो चालकों का कहना है की कुछ दिन पहले बिरसानगर थाना की पुलिस ने टेल्को के एलएफएस इंग्लिश स्कूल से जुड़े एक मामले में वाहन चालक मन्नू पांडे को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर 27 जनवरी को जेल भेज दिया था। मन्नू पांडे पर आरोप है कि उसने पांच साल की बच्ची से वैन में ही दुष्कर्म किया था। पीड़िता के अभिभावक की शिकायत पर पुलिस ने मन्नू पांडे को गिरफ्तार किया। बच्ची की मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने मन्नू पांडे को जेल भेज दिया था। ऑटो और वैन चालक इसी मुद्दे को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि मन्नू पांडे को छोड़ा जाए। जबकि, पुलिस का कहना है कि मन्नू पांडे के खिलाफ तगड़े सबूत हैं। इसी के चलते उसे जेल भेजा गया है।

स्कूल के पास बच्चों के साथ अभिभावक

अभिभावकों का कहना है कि मन्नू पांडे पर संगीन आरोप हैं। इस तरह उसके समर्थन में हड़ताल करना ठीक नहीं है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूली ऑटो और वैन चालकों को चाहिए कि वह अदालत पर भरोसा रखें। अदालत में केस चलेगा और सबूत के आधार पर फैसला होगा।

सोनारी में 7 को होगा भव्य श्याम वार्षिक महोत्सव

JAMSHEDPUR : सोनारी स्थित लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी मंदिर में 7 फरवरी को 23वां श्री श्याम वार्षिक महोत्सव मनाया जाएगा। इसका आयोजन श्रीश्याम सेवा संघ सोनारी द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में संस्था के अशोक दीवान ने बताया कि आयोजन में आकर्षण का केंद्र श्याम बाबा का भव्य दरबार, छप्पन भोग, अखंड ज्योत व विद्युत सज्जा रहेगा। इस वर्ष भजनो की अमृत वर्षा सुप्रसिद्ध भजन गायक आदर्श दधीच एवं मंच संचालन घाटशिला के शुभम अग्रवाल करेंगे। दोपहर में विशाल शोभा यात्रा निकलेगी, जो दोपहर 12.30 बजे से सोनारी राम मंदिर से प्रारंभ होकर सोनारी के मुख्य मार्ग से होते हुए मारवाड़ी मंदिर तक आएगी। इसे सफल बनाने में श्याम अग्रवाल, अरविंद अग्रवाल, मनीष गर्ग, चेतन अग्रवाल, बजरंग वर्मा, राहुल अग्रवाल, विजय गुप्ता, विवेक अग्रवाल आदि सक्रिय हैं।

साकची से लापता किशोर महाराष्ट्र में बरामद

सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में रहने वाला बच्चा 9 जनवरी को अचानक हो गया था लापता

PHOTON NEWS JSR : सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के इंद्रानगर ह्यूम पाइप एरिया निवासी 14 वर्षीय किशोर के लापता होने के मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। साकची से 9 जनवरी को अचानक गायब हुए किशोर को पुलिस टीम ने महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से सुरक्षित बरामद कर लिया। इस पूरे मामले की जानकारी सोमवार को डीएसपी सुनील चौधरी ने पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।

डीएसपी ने बताया कि किशोर के लापता होने के तीन दिन बाद उसके परिजन सीतारामडेरा थाना पहुंचे और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की। जांच के क्रम में साकची और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, जिससे अहम सुराग हाथ लगे। तकनीकी साक्ष्यों और मिले इनपुट के आधार पर पुलिस को यह पता चला कि किशोर महाराष्ट्र की ओर गया है।

इसके बाद पुलिस की टीम ने महाराष्ट्र पुलिस से समन्वय स्थापित किया और संयुक्त कार्रवाई करते हुए बुलढाणा जिले से किशोर को सकुशल बरामद कर लिया। बरामदगी के बाद किशोर को उसके परिजनों के हवाले करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीएसपी ने कहा कि राहत की बात है कि बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है और उसके साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है।

इस अभियान में डीएसपी सुनील चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें अकरम रजा, रोहित कुमार साव, साकची थाना प्रभारी आनंद कुमार मिश्रा, एएसआई हरि महतो, सुजीत कुमार और राजीव कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।

परिजनों के साथ बरामद किशोर व पुलिस के जवान

समस्या | जनता की शिकायत पर सरयू राय ने किया पारडीह काली मंदिर से डेंटल कॉलेज तक निरीक्षण

एनएच-33 पर धूल के गुबार से राहगीर हो रहे परेशान

PHOTON NEWS JSR : जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने सोमवार को पारडीह काली मंदिर से डेंटल कॉलेज तक एनएच-33 के पर बन रहे ऊपरी पथ के निर्माण के संबंध में जन शिकायतों को लेकर स्थल निरीक्षण किया। उनके साथ एनएचआई के अफसर और अभियंता भी थे। राय और टीम ने पारडीह से लेकर बालीगुमा तक के क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य का अवलोकन किया। इस संबंध में सरयू राय ने शिकायतों को दूर करने के लिए एनएचएआई के अफसरों को आवश्यक निर्देश दिया। सरयू राय ने बताया कि एक शिकायत यह थी कि जगह-जगह पर निर्माण के दौरान काफी धूल उड़ती है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। दूसरी शिकायत यह थी कि निर्माण के दौरान सड़क के इस पार से उस पार जाने के लिए बहुत कम स्थानों पर क्रॉस रोड बनाया गया है। तीसरी शिकायत यह थी कि कोलकाता और रांची की तरफ से आने वाले लोगों को शहर में उतरने के लिए रैम्प दिया गया है, लेकिन वहां काफी संकरापन हो जा रहा है, जहां रैंप उतर रहा है। राय ने अफसरों से कहा कि जहां भी मिट्टी धूल में बदल गई है, वहां पानी का गहरा छिड़काव किया जाए। जहां धूल की मोटी परत जम गई है, उसे पोकलेन से हटवाएं। अफसरों ने इसके लिए हामी भरी। राय ने बताया कि जिन तीन स्थानों पर रैंप गिर रहा है (पारडीह चौक के पास, एक डिमना चौक के पहले और एक डिमना चौक के बाद) वहां रास्ता संकीर्ण हो जा रहा है। भारी वाहनों को ले जाना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि बीच में नाला पड़ जाता है। राय ने अफसरों से कहा कि जितनी दूर तक रैंप के किनारे नाला है, उतनी दूर तक नाला के ऊपर डाले गए ढक्कन के स्थान पर मजबूत पीसीसी ढाला जाए, ताकि उस पर भारी वाहन आ-जा सकें। अफसरों ने कहा कि जहां जरूरत होगी, वहां इसे किया जाएगा। सरयू राय ने बताया कि सड़क के इस पार से उस पार जाने के लिए जहां भी क्रॉस रोड की जरूरत है, वहां क्रॉस रोड बना दिया जाए। जहां भीतर का काम हो रहा है, उसको दोनों तरफ दीवार जैसा टीना खड़ा कर दें, ताकि बाहरी धूल न आ सके। इस पर भी सहमति बनी। अफसरों ने कहा कि उनके सुझाव के अनुसार नया डिजाइन बनाएंगे और उन्हें दिखाएंगे।

एनएच पर सड़क का निरीक्षण करते विधायक सरयू राय ● फोटोन न्यूज

ब्लास्टिंग से कासमार गांव के घरों में आई दरार

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम जिला के डुमरिया प्रखंड स्थित कामार गांव का दौरा करेंगे। वहां भारी ब्लास्टिंग से घरों में दरार आ गई है, तो जलस्तर भी काफी नीचे चला गया है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने सरयू राय से मिलकर की। सरयू राय ने बताया कि कासमार गांव के ग्रामीण उनके बिष्टुपुर स्थित आवास- कार्यालय पर मिलने आए थे। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि डुमरिया के अंचल अधिकारी द्वारा दी गई गलत सूचना के आधार पर जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम ने उनके गांव के समीप पत्थर खनन का पट्टा स्वीकृत कर दिया है। ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया पत्र भी दिखाया, जिसमें कुछ बिंदुओं में गलत उल्लेख है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें दूसरे गांव से पीने का पानी लाना पड़ रहा है।

एचसीएल-आईसीसी कंपनी ने 299 ठेका मजदूरों को बैठाया

कंपनी गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन करते श्रमिक ● फोटोन न्यूज

GHATSILA : एचसीएल-आईसीसी प्रबंधन ने रविवार से 299 ठेका मजदूरों को काम से बैठा दिया। इसके बाद सोमवार को झारखंड श्रमिक संघ का प्रतिनिधमंडल कंपनी प्रबंधन से मिला। अध्यक्ष काजल डान के नेतृत्व में कंपनी के जीएम-माइंस दीपक श्रीवास्तव, चीफ मैनेजर कमलेश कुमार व चीफ मैनेजर अर्जुन लोहरा से मिलकर मजदूरों को काम से बैठाने पर आपत्ति जताई। प्रबंधन ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया में तकनीकी देरी होने के कारण मजदूरों को बैठाना पड़ा है, जैसे ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, पुनः मजदूरों को बुला लिया जाएगा। संघ के अध्यक्ष ने इसकी जानकारी विधायक सोमेश चंद्र सोरेन को फोन पर दी। विधायक ने 4 फरवरी को शाम 4.30 बजे बैठक करने की बात कही। प्रतिनिधिमंडल में संघ के सदस्य शंभू जेना, कमल दास, आजाद बेहरा, मदन मुर्मू, मंटू माहली, गुमदा मुर्मू, एंथोनी सिगार, पप्पू सिंह, गुरमीत सिंह, अनिल रवानी,सुनील सिंह आदि शामिल थे।

दो महिलाओं सहित अंतर जिला चोर गिरोह के पांच गिरफ्तार

AGENCY ARARIA : बिहार में अररिया के फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र में लगातार बंद घरों में हो रही चोरी की वारदात के पीछे काम कर रहे गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। बंद घरों का रेकी कर फिर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अंतर जिला चोर गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनके पास से स्वणार्भूषण समेत नगद भारतीय और नेपाली करेंसी के साथ चोरी के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को बरामद किया है। इस बात की जानकारी एसपी जितेन्द्र कुमार ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी।

मामले की जानकारी देते एसपी जितेंद्र कुमार

पुलिस ने गिरोह के सदस्यों में मुजफ्फरपुर जिला मीनापुर तुर्की वार्ड संख्या 31 के रहने वाले 28 वर्षीय राजा चौधरी, सहरसा के गंजाला वार्ड संख्या 18 के 28 वर्षीय मो. बुचो पिता मो.फिदा हुसैन, 30 वषीर्या मकिना खातून पति मो. बुचो, फारबिसगंज के कटहरा वार्ड संख्या एक निवासी 35 वषीर्या बसंती देवी पति रणजीत मंडल और झारखंड के गोड्डा जिला के मेहरबा थाना क्षेत्र के बरहट दीघी वार्ड संख्या 3 के रहने वाले 27 वर्षीय शशि पासवान पिता संजय पासवान को गिरफ्तार किया है। एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि बंद घरों में लगातार हो रही चोरी की घटना को लेकर फारबिसगंज एसडीपीओ के नेतृत्व में बथनाहा थानाध्यक्ष, फुलकाहा थानाध्यक्ष और डीआईयू की टीम के साथ एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था। छापामारी दल द्वारा सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी अनुसंधान और सूचना संकलन कर चोरी की घटना में संलिप्त लोगों की शिनाख्त की, जिसके बाद सबों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार गिरोह के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि चोरी के लिए एक संगठित गिरोह काम करता है, जो पहले बंद घरों का रेकी करता है और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देता है। एसपी ने बताया कि जिले के कई थाना क्षेत्र में हुए चोरी की घटना में गिरोह की संलिप्तता की बात सामने आई है। जिसको लेकर सभी कांडों में गिरफ्तार गिरोह के सदस्यों को रिमांड पर ली जाएगी। फिलहाल चोरों को बथनाहा थाना कांड संख्या 14/2026 दिनांक 30.01.26 धारा 305, 331(4) बीएनएस में सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। गिरोह के सदस्यों के पास से चांदी का पायल एक, जोड़ा पायल एक, चांदी का सिक्का, मछली, अंगूठी, दो सोने की सिकड़ी, कान की बाली, लोहे का चार रिंच,पांच एंड्रॉयड मोबाइल, तीन कीपैड मोबाइल, एक पेचकस, एक लोहे की आरी, 29 हजार 670 भारतीय रुपए, 38 सौ नेपाली रुपए, दो लोहे का रॉड आदि बरामद किया गया है।

NEWS BOX

ट्रेन की चपेट में आकर महिला की मौत, पहचान में जुटी पुलिस

AGENCY BUXAR : दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत टुड़ीगंज स्टेशन के पश्चिमी छोर के पास सोमवार की दोपहर बाद एक दर्दनाक हादसा हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक महिला दक्षिण दिशा से रेलवे ट्रैक पार कर उतर दिशा की ओर जा रही थी। इसी दौरान अप लाइन पर तेज रफ्तार से आ रही मेल ट्रेन की चपेट में वह आ गई। हादसा इतना भीषण था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेन की टक्कर से महिला का शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। घटना के बाद स्टेशन के आसपास अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर बक्सर रेल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। बक्सर रेल थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि मृत महिला की पहचान की जा रही है। आसपास के थानों को भी सूचना दे दी गई है। मामले की जांच जारी है।

दाखिल-खारिज के लंबित मामलों में सीओ से मांगा गया स्पष्टीकरण

AGENCY BUXAR : जिला पदाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय में आयोजित हुयी। बैठक में जिले में

संचालित राजस्व एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि राजस्व महा अभियान एवं ई-मापी अभियान 31 मार्च तक संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में भूमि सुधार उप समाहर्ता बक्सर/डुमराँव को प्रतिवेदन समर्पित करने तथा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक दो दिनों पर प्रगति प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया। सभी अंचलाधिकारियों को भूमि उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही भूमि बैंक, आर्द्र भूमि, अतिक्रमण एवं विभिन्न प्रयोजनों से संबंधित प्रतिवेदन भूमि सुधार उप समाहर्ता बक्सर को सौंपने का आदेश दिया गया। अंचल रैंकिंग, अतिक्रमण एवं न्यायालय से जुड़े लंबित मामलों को लेकर राजस्व अधिकारी सिमरी का वेतन स्थगित करने तथा नगर परिषद बक्सर के कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया। दाखिल-खारिज, भूमि विवाद, ई-मापी आदि मामलों के समयबद्ध निष्पादन पर जोर देते हुए 75 दिन से अधिक लंबित मामलों को लेकर अंचलाधिकारी इटाढ़ी, चौसा एवं राजपुर से स्पष्टीकरण मांगा गया। इसके अतिरिक्त, जियो टैगिंग एवं आवास प्लस सर्वे में रुचि नहीं लेने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी नावानगर से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया।

गृह सचिव ने सुनी जनता की समस्याएं, हुआ त्वरित समाधान

AGENCY PATNA : बिहार के गृह सचिव सह कारा महानिरीक्षक प्रणव कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जन-सुनवाई का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक चला। जन-सुनवाई के दौरान गृह सचिव ने सभी मामलों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निष्पादन के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जनसमस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष बल देने को कहा। इस अवसर पर प्रणव कुमार ने बताया कि ₹सबका सम्मान-जीवन आसान₹ अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना और प्रशासन तथा जनता के बीच विश्वास को और मजबूत बनाना है। गृह विभाग के तहत इस योजना के अंतर्गत सोमवार को सुबह 11:00 से 01:00 तथा शुक्रवार को अपराह्न 03:00 से 05:00 दो दिन जन-सुनवाई आयोजित की जाती है। इसमें विभाग के अपर मुख्य सचिव, सचिव और विशेष सचिव फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं और प्रभावी निष्पादन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश देते हैं।

BRIEF NEWS

हर्षोल्लासपूर्वक मनाई गई संत रविदास की जयंती

BHAGALPUR : आनन्दराम ढांढनियां सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में सोमवार को संत रविदास जी की जयंती हर्षोल्लासपूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य सुमंत कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्वेता झा एवं कक्षा एकादश के भैयाझबहनों द्वारा संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर कक्षा एकादश के भैया-बहनों ने संत रविदास जी की जीवनी पर प्रकाश डाला तथा गीत एवं कविता के माध्यम से उनके विचारों को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य सुमंत कुमार ने कहा कि संत रविदास जी एक महान संत एवं समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपने जीवन में गरीबों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया।

डायन का आरोप लगा कर की गई मारपीट

BHAGALPUR : डायन के आरोप में मारपीट की घटना में घायल भागो देवी, उसकी पुत्री आरती कुमारी, दूसरी पुत्री पूजा कुमारी, उसके पति और बेटे को इलाज के लिए सोमवार को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसमें कई घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। मामला चौसा थाना क्षेत्र का है। मारपीट का आरोप किरो देवी, केली देवी, फूली देवी, बीरन देवी और भूलचरण मंडल पर लगा है। सभी के सिर और शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। मामले को लेकर घायल भागो देवी ने बताया कि पड़ोस के रहने वाले भूलचरण मंडल उसे डायन कहकर प्रताड़ित करता है।

नौ को होगा रोजगार मेला का आयोजन

SARAN : श्रम संसाधन विभाग, बिहार के तत्वावधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय छपरा द्वारा आगामी 09 फरवरी 2026 को शहर के राजेन्द्र स्टेडियम में एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले की खास बात यह है कि इसमें कई स्थानीय और बाहरी कंपनियां शिरकत कर रही हैं। कंपनियों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन मौके पर ही किया जाएगा।

बिहार विधानसभा में पेश हुआ 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण

राज्य की विकास दर राष्ट्रीय औसत से 3.3 प्रतिशत अधिक

AGENCY PATNA : बिहार विधानमंडल में सोमवार को बजट सत्र-2026 के पहले दिन वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार की ओर से बिहार विधानसभा में वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार की विकास दर राष्ट्रीय औसत से 3.3 प्रतिशत अधिक है, जो राज्य की तेज आर्थिक प्रगति को दर्शाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पांच वर्षों में बिहार को विकसित राज्य बनाना है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 76,490 रुपये हो गई है। इस अवसर पर वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर भी उपस्थित थे।

वित्त मंत्री ने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की विकास दर अधिक है और तमिलनाडु के बाद बिहार की विकास दर सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने शुरूआती 10 वर्षों में राज्य की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बिजली, पानी और सड़कों का व्यापक नेटवर्क पूरे बिहार में विकसित किया गया। अब आगामी पांच वर्षों में सरकार का विशेष जोर औद्योगिकरण पर होगा, जिससे प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया जा सके।

बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकल्प है कि अगले पांच वर्षों में बिहार को विकसित राज्य बनाया जाए। 'संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार' के लक्ष्य की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में विकास की इस सोच की झलक साफ दिखाई देगी।

वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 8.6 प्रतिशत और वर्तमान मूल्य पर 13.1 प्रतिशत रहा है। इस दौरान जीएसडीपी बढ़कर क्रमशः 5,31,372 करोड़ रुपये और 9,91,997 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान मूल्य पर बिहार की विकास दर 13.1 प्रतिशत रही, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 9.8 प्रतिशत है, यानी बिहार राष्ट्रीय औसत से 3.3 प्रतिशत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

आनंद किशोर ने बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 2020-21 में 46,412 रुपये से बढ़कर 2024-25 में 76,490 रुपये हो गया है। वहीं, 2011-12 के स्थिर मूल्य पर यह आंकड़ा 30,159 रुपये से बढ़कर 40,973 रुपये पहुंच गया है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार का संकेत है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2020-21 में 1.28 लाख करोड़ रुपये रही राजस्व प्राप्ति 2024-25 में बढ़कर 2.18 लाख करोड़ रुपये हो गई है। कुल राजस्व में कर प्राप्ति का हिस्सा 70 प्रतिशत से बढ़कर 84 प्रतिशत हो गया है, जबकि राजस्व और सहायता अनुदान का हिस्सा क्रमशः घटा है।

विधानसभा में उपस्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य मंत्री

शोक प्रस्ताव के बाद कार्यवाही स्थगित, आज 11 बजे फिर बैठेगा सदन

PATNA : बिहार विधानमंडल में बजट सत्र-2026 के पहले दिन सोमवार को शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में प्रस्तुत शोक प्रस्ताव के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की गई। इनमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री स्व. अजीत पवार, बिहार के पूर्व राज्यसभा सदस्य स्व. राजनीति प्रसाद, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य स्व. अशोक चौधरी, बिहार विधानसभा की पूर्व सदस्य स्व. वीणा वादिनी पाण्डेय, प्रसिद्ध साहित्यकार एवं वरिष्ठ पत्रकार स्व. अवधेश प्रीत तथा अम्बेडकरवादी समाजसेवी स्व. बुद्धशरण हंस के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। सदन के सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मौन रखा और उनके योगदान को स्मरण किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सदन की कार्यवाही मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की।

राज्यपाल के अभिभाषण में हर जगह हरियाली लेकिन वास्तविकता उससे अलग : तेजस्वी यादव

AGENY PATNA : बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने राज्यपाल के संबोधन को सरकार का 'वही पुराना और रटा-रटाया भाषण' करार देते हुए कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है और यह जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे पिछले 10 वर्षों से सदन में हैं और इस दौरान चाहे कोई भी राज्यपाल आए हों, सभी ने सरकार द्वारा दिया गया वही भाषण पढ़ा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में हर जगह हरियाली और विकास की तस्वीर दिखाई गई है, लेकिन वास्तविक बिहार की स्थिति इससे बिल्कुल अलग है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाषण में जिन कई योजनाओं का जिक्र किया गया है, वे ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें सरकार ने सत्ता में आने से पहले राष्ट्रीय जनता दल की योजनाओं से कॉपी किया है। तेजस्वी ने कहा कि सरकार केवल कागजों पर विकास दिखा रही है, जबकि आम जनता आज भी बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है। कानून-व्यवस्था को लेकर भी तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। राज्य में दिनदहाड़े हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण और गोलीकांड जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सुशासन का दावा करती है, लेकिन हकीकत में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में कई सरकारी योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ब्लॉक या थाना स्तर पर जाए, तो हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला साफ नजर आता है। आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे देश में आर्थिक मोर्चे पर बिहार सबसे फिसड्डी राज्य क्यों बना हुआ है। यदि बिहार में वास्तव में विकास हुआ है, तो वह अन्य राज्यों की तरह आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है।

भागवत कथा के दूसरे दिन महापुराण के महात्म्य प्रसंग पर चर्चा

ARARIA : शहर के शिशु भारती विद्यालय के निकट लोक शिक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रकाश प्रसाद के निज निवास पर आयोजित आठ दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान-यज्ञ के दूसरे दिन सोमवार को महापुराण के महात्म्य प्रसंग, सृष्टि की उत्पत्ति,भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के महत्व पर हुई चर्चा हुई। सुप्रसिद्ध कथा वाचक आचार्य श्री नारायण शर्मा ने श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य प्रसंग, सृष्टि की उत्पत्ति, तथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के महत्व पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालते हुए कहा कि श्रीमद्भागवत महापुराण मानव जीवन को अज्ञान से ज्ञान की ओर तथा मोह से मोक्ष की ओर ले जाने वाला दिव्य ग्रंथ है।

पटना में बनेगा अत्याधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र, 10 को खोली जाएगी टेक्निकल बिड

AGENCY PATNA : कोच्चि वाटर मेट्रो की तर्ज पर पटना में 1200 करोड़ रुपये की लागत से वाटर मेट्रो संचालन की योजना तैयार की जा रही है। इस परियोजना के तहत जेटी निर्माण, टर्मिनल विकास और जहाजों की खरीद शामिल होगी। बिहार सरकार में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) कोटे से परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

परिवहन मंत्री ने बताया कि डीपीआर राइट्स की ओर से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद पटना और आसपास के घाटों से नियमित फेरी सेवा के लिए 22 हाइब्रिड जहाज लाने का प्रस्ताव है। ये जहाज मात्र एक मीटर गहराई वाले पानी में भी संचालित हो सकेंगे, जिससे यात्रियों को सस्ती, सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा मिलेगी।

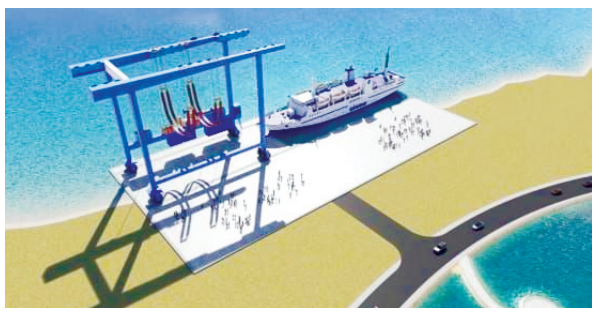

मंत्री ने बताया कि पटना में जहाज मरम्मत केंद्र (शिप रिपेयर फैसिलिटी) के निर्माण के लिए इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईडब्ल्यूएआई) ने टेंडर प्रक्रिया तेज कर दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 243.20 करोड़ रुपये है। आईडब्ल्यूएआई की ओर से जारी टेंडर के तहत टेक्निकल बिड 10 फरवरी को खोली जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य शुरू होने के 24 महीनों के भीतर इस केंद्र को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

उपलब्धि इस प्रकार की भूमि पर साल भर जमा रहता है पानी

राज्य के 6 वेटलैंड्स को मिल चुकी है अंतरराष्ट्रीय मान्यता

AGENCY PATNA : 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया गया। यह एक महत्वपूर्ण दिन है जो विश्व भर में आर्द्रभूमि के संरक्षण और महत्वता को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह बिहार के लिए भी खास है। बिहार में कई ऐसे वेटलैंड्स हैं जिसको संरक्षित करने के लिए सरकार योजना चला रही है।

इसे आर्द्रभूमि भी कहा जाता है। यानि ऐसी भूमि जहां सालभर पानी जमा होता है। भू-भाग का बड़ा क्षेत्र झील और तालाब जैसा हो। यह प्राकृतिक रूप से या मानवनिर्मित भी होता है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार दलदल, नदियां, झीलें आदि शामिल हैं, जो 6 मीटर से कम गहराई की हो। ऐसे क्षेत्र में सालभर पानी भरा होता है। यहां की मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि इस भूमि पर सालोभर पानी जमा होता है। यहां ऐसे पौधे पाए जाते हैं, जो पानी में डूबने के बावजूद जीवित रहते हैं। इस जल में मछली, कीट और जंगली जीवों का वास होता है।

वेटलैंड्स को पृथ्वी का गुदा भी कहा जाता है, क्योंकि यह पानी को शुद्ध करने में मदद करता है। यहां की भूमि बाढ़ को नियंत्रण करने में मदद करती है। बारिश और बाढ़ के दौरान इन क्षेत्रों में पानी जमा होता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी कम जमता है।

इस क्षेत्र में सालोभर पानी जमने के कारण भू-जल स्तर को बढ़ावा मिलता है। कार्बन को अवशोषित कर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करता है। यह क्षेत्र जीविका के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। लाखों लोग मछली पालन और खेती कर अपना जीविका चलाते हैं। बिहार में मछली पालन और मखाना के लिए ऐसे क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं।

बिहार में वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि को संरक्षित करने की चुनौती है। वेटलैंड भूमि का दायरा काफी व्यापक है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वेटलैंड्स फैले हुए हैं। इनमें झीलें, तालाब, नदियों से जुड़ी जलभूमि और जलाशय शामिल हैं। राज्य के 6 वेटलैंड्स को अंतरराष्ट्रीय रामसर साइट के रूप में मान्यता मिल चुकी है, जो बिहार की जैव विविधता और पर्यावरणीय महत्व को दर्शाता है।

वेटलैंड एरिया में होता 64% प्रजनन

जमुई जिला स्थित नागी नकटी वेटलैंड मानव निर्मित बताया जाता है। बेगूसराय स्थित कावर झील, कटिहार के गोगा बिल झील उदयपुर (पश्चिम चंपारण) और गोकुल जलाशय प्राकृतिक वेटलैंड की श्रेणी में आता है। ये ऐसे इलाके हैं, जहां दुर्लभ प्रजाति के पक्षी प्रजनन, आहार और विहार के लिए आते हैं। देश में चार प्रतिशत वेटलैंड एरिया है, जिसमें 64% प्रजनन होता है।

कार्यालयों में लटके रहे ताले, हड़ताल पर गए सीओ व राजस्व अधिकारी

NAVADA : नवादा जिला मुख्यालय सहित जिले के विभिन्न राजस्व अंचलों के अंचलाधिकारी तथा राजस्व अधिकारी सोमवार से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं इस कारण कार्यालय में ताले लटके हैं। राज्यस्तरीय संघ के आहवान पर कौआकोल सीओ मनीष कुमार एवं राजस्व अधिकारी अनीश कुमार ने बताया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से अंचल कार्यालय में सन्नाटा छा गया है। जिले के सीओ एवं राजस्व अधिकारी के हड़ताल पर चले जाने से दाखिलखारिज सहित विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र निर्गत करने का काम ठप हो गया है।

छपरा की वीआईपी गली में होटल मैनेजर के भाई को मारी गोली

AGENCY SARAN : बिहार में सारण जिले के छपरा शहर के भगवान बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत वीआईपी गली में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली युवक के बाएं जांघ में लगी है। आनन-फानन में घायल को छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल युवक की पहचान कोपा थाना क्षेत्र के बसडीला गांव निवासी स्वर्गीय सुभाष पांडेय के पुत्र अभिषेक कुमार पांडेय के रूप में हुई है। सदर अस्पताल में भर्ती अभिषेक के भाई और ललिता होटल के मैनेजर पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि वे दोनों भाई होटल में बैठे थे। इसी दौरान कोठेया निवासी

रितिक सिंह और नैनी निवासी सोनू सिंह वहां पहुंचे और अभिषेक को जबरन खींचकर गली में ले जाने लगे। पंकज के अनुसार, जब उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की। इसी छीना-झपटी के दौरान अपराधियों ने अभिषेक पर फायरिंग कर दी। एक गोली सीधे उसके बाएं जांघ में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने दो राउंड फायरिंग की आवाज सुनी जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

मुख्यधारा के विकास से जुड़तीं महिलाएं

संप्रति महिलाओं के माध्यम से एक प्रभावी आर्थिक क्रांति आकार ले रही है। लाखों महिलाएं सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, स्थानीय व्यापार और हस्तशिल्प जैसे छोटे, अनौपचारिक उद्यमों से अपनी आजीविका चला रही हैं। यह उनका पहला स्थायी और स्वतंत्र आय का स्रोत बनता है। इस परिवर्तन में माइक्रोफाइनेंस ने एक निर्णायक भूमिका निभाई है। बिना गारंटी वाले ये छोटे कर्ज, जो घर की दहलीज पर ही आसान किस्तों पर उपलब्ध हैं, महिलाओं की आजीविका और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, परिवार की आय को सुदृढ़ करने और अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदारी करने में सक्षम बनाते हैं। इन महिलाओं के लिए माइक्रोफाइनेंस केवल वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि सम्मानजनक आजीविका का माध्यम और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने वाली एक जीवनरेखा बनकर उभरा है। एक ऐसे दौर में जब तमाम प्रयासों के बीच ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में पारंपरिक बैंकों की पहुंच अब भी कुछ अपेक्षाकृत रूप से सीमित है, तब इस स्थिति में माइक्रोफाइनेंस एक वरदान बनकर उभरा है। आज माइक्रोफाइनेंस भारत के दूर-दराज वाले इलाकों तक गहराई से अपनी पैठ बना चुका है। यह देश के 720 जिलों में लगभग 7.5 करोड़ ऐसे लोगों को अपनी वित्तीय सेवाओं का लाभ दे रहा है, जिस तबके के लोगों की आय कम है। इनमें देश के 112 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। इन लाभार्थियों में लगभग 100 प्रतिशत महिलाएं हैं, जिनके लिए माइक्रोफाइनेंस औपचारिक ऋण प्रणाली से जुड़ाव की पहली कड़ी बन गई है। इसने आर्थिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर तक औपचारिक वित्त को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दृष्टि से यह कहना उचित होगा कि माइक्रोफाइनेंस वित्तीय समावेशन का सशक्त स्तंभ बनकर उभरा है। माइक्रोफाइनेंस के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले अधिकांश लोग पहली पीढ़ी के उद्यमी होते हैं, जिनके व्यवसाय समय के साथ धीरे-धीरे विकसित होते हैं। प्रारंभिक ऋण जोकि 30,000 से 50,000 के बीच होता है, उसका उपयोग बुनियादी उपकरण खरीदने में किया जाता है। अगले चरण के ऋण चक्र आय के स्रोतों में विविधता और उत्पादन विस्तार को संभव बनाते हैं। तयशुदा किस्तें वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देती हैं और नियमित आय परिवारों को अस्थायी मजदूरी की अनिश्चितता से बाहर निकालने में सहायक होती है। यह परिवर्तन केवल अनुभवजन्य नहीं, बल्कि संरचनात्मक भी है। वर्ष 2021 में एनसीएईआर के एक अध्ययन के अनुसार माइक्रोफाइनेंस का भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान कुल सकल मूल्य वर्धन का लगभग 2.03 प्रतिशत है और यह लगभग 1.30 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करने में सहायक बना है। इससे स्पष्ट है कि माइक्रोफाइनेंस आज वर्तमान भारत की आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक बन चुका है। माइक्रोफाइनेंस परिदृश्य पर आरबीआइ द्वारा विनियमित संस्थाएं सख्त दिशानिदेर्शों, फेयर प्रैक्टिसेज कोड और उद्योग की आचार संहिता के तहत जिम्मेदार ऋण प्रथाओं का पालन करती हैं, जिससे महिला उधारकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। आरबीआई के अनुसार किसी उधारकर्ता की कुल माइक्रोफाइनेंस ऋण चुकौती उसकी घरेलू आय के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। इसके साथ ही आरबीआइ द्वारा मान्यता प्राप्त स्व-नियामक संगठन माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क यानी एमएफआइएन द्वारा निर्धारित प्रविधान भी लागू होते हैं। इसमें उधार की सीमा को निर्धारित कर ऋण जोखिम को कम किया जाता है। इसके साथ ही त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली भी मौजूद है, जिसमें एमएफआइएन दूसरे स्तर की व्यवस्था को चौबीसों घंटे संचालित करता है। ये सभी सुरक्षा प्रविधान जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। उधारकताओं की रक्षा करते हैं और समग्र सेक्टर की दीर्घकालिक स्थिरता को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके बावजूद अपने प्रमाणित प्रभाव के बावजूद माइक्रोफाइनेंस सेक्टर इस समय गंभीर नकदी संकट से जूझ रहा है। इसके कारण करीब 50 लाख जरूरतमंद औपचारिक ऋण व्यवस्था से बाहर हो गए हैं। इससे उनके फिर से साहूकारों और बिना नियमन वाली अनौपचारिक ऋण व्यवस्थाओं के शिकंजे में फंसने का जोखिम बढ़ गया है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को महंगे कर्ज के दुष्चक्र में फंसने से बचाने के लिए संगठित और विनियमित माइक्रोफाइनेंस में औपचारिक वित्त का प्रवाह बनाए रखना आवश्यक हो गया है। प्रभाव के स्तर पर भी देखा जाए तो आय अर्जन से इतर माइक्रोफाइनेंस का सामाजिक प्रभाव गहरा और स्थायी है। यह महिलाओं की घरेलू निर्णय भूमिका को सशक्त करता है, शिक्षा-स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाता है और बचत की आदत को प्रोत्साहित करता है। जैसे-जैसे महिलाएं वित्तीय योगदानकर्ता और रोजगार सृजनकर्ता बनती हैं, वे परिवार और समुदाय दोनों में सामाजिक सम्मान और आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करती हैं। महिला-केंद्रित विकास की दिशा में बढ़ते भारत के लिए निरंतर पूंजी प्रवाह और सशक्त नियामक निगरानी के साथ माइक्रोफाइनेंस एक बुनियादी स्तंभ बना रहेगा, जो आजीविका के माध्यमों को मजबूत कर भारत की विकास गाथा में निर्णायक योगदान देने में सक्षम बन रहा है।

विदेशी निवेश, संयुक्त राष्ट्र और भारत की स्थिति

ANALYSIS

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

साल 2014 के दौरान मेक इन इंडिया अभियान से ही भारत ने अपने को विनिर्माण हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ा दिया था, जिसके कि अब 10 साल बाद सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं, क्योंकि जब इस पहल ने 25 क्षेत्रों में स्वतः अनुमोदन मार्ग से एफडीआई खोल दिया, तब कुल एफडीआई स्टॉक एक ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया। सरकार ने रक्षा, रेलवे और बीमा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी एफडीआई सीमा 74 प्रतिशत तक बढ़ाई है। यही वजय है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम ने 14 क्षेत्रों में 1.97 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन दिए, जिसके फलस्वरूप ऐपल, सैमसंग जैसी कंपनियां भारत में बड़े प्लांट लगा रही हैं। डेटा सेंटर्स के क्षेत्र में 2025 की पहली तीन तिमाहियों में ही सात अरब डॉलर का निवेश भारत आ चुका है, जिसका परिणाम यह हुआ कि ये भारत को वैश्विक सूची में सातवें स्थान पर ले गया। चौथी तिमाही में यह और तेज हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2014 से 2025 के बीच एफडीआई इक्विटी प्रवाह 7 लाख 27 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो पूर्व यूपीए शासन के मुकाबले दोगुना है। अक्टूबर 2025 में गूगल ने आंध्र प्रदेश में एआई हब के लिए 15 अरब डॉलर का निवेश घोषित किया, जो अब जमीन पर उतारा जा रहा है।

भारत की अर्थव्यवस्था इन दिनों वैश्विक निवेशकों की नजरों में छाई हुई है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) की सामने आई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2025 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में 73 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है। कुल 47 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले देशों में शीर्ष पंक्ति में नजर आ रहा है। वस्तुतः यह वृद्धि मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में बड़े निवेशों से प्रेरित रही, जहां वित्तीय सेवाएं, आईटी, अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों ने प्रमुख भूमिका निभाई। उत्पादन क्षेत्र में भी निवेश बढ़ता हुआ दिखा है। कहना होगा कि इस निवेश उछाल के पीछे केंद्र की मोदी सरकार के दूरदर्शी प्रयास दिखाई देते हैं। साल 2014 के दौरान मेक इन इंडिया अभियान से ही भारत ने अपने को विनिर्माण हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ा दिया था, जिसके कि अब 10 साल बाद सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं, क्योंकि जब इस पहल ने 25 क्षेत्रों में स्वतः अनुमोदन मार्ग से एफडीआई खोल दिया, तब कुल एफडीआई स्टॉक एक ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया। सरकार ने रक्षा, रेलवे और बीमा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी एफडीआई सीमा 74 प्रतिशत तक बढ़ाई है। यही वजय है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम ने 14 क्षेत्रों में 1.97 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन दिए, जिसके फलस्वरूप ऐपल, सैमसंग जैसी कंपनियां भारत में बड़े प्लांट लगा रही हैं। डेटा सेंटर्स के क्षेत्र में 2025 की पहली तीन तिमाहियों में ही सात अरब डॉलर का निवेश भारत आ चुका है, जिसका परिणाम यह हुआ कि ये भारत को वैश्विक सूची में सातवें स्थान पर ले गया। चौथी तिमाही में यह और तेज हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2014 से 2025 के बीच एफडीआई इक्विटी प्रवाह 7 लाख 27 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो पूर्व यूपीए शासन के मुकाबले दोगुना है। अक्टूबर 2025 में गूगल ने आंध्र प्रदेश में एआई हब के लिए 15 अरब डॉलर का निवेश घोषित किया, जो अब जमीन पर उतारा जा रहा है। दिसंबर में माइक्रोसॉफ्ट ने एआई, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स में 17.5 अरब डॉलर तथा अमेजन ने एआई एवं अन्य क्षेत्रों में 35 अरब डॉलर निवेश की पेशकश की गई है। एक तरह से देखें तो ये सभी घोषणाएं आज डिजिटल इंडिया और नेशनल डेटा सेंटर पॉलिसी का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। यहां यह भी उल्लेख करना जरूरी लगता है कि इसमें केंद्र की नीतियां जितनी प्रभावी हैं, उतने ही महत्वपूर्ण हैं राज्य सरकारों के प्रयास, जिन्होंने निवेशकों को जमीन से जोड़ने सफलता प्राप्त की। उदाहरण स्वरूप आज हम मप्र और उप्र के प्रयासों को देख सकते हैं, ऐसे ही अन्य राज्यों में पिछले दिनों हुए कार्य हैं। मध्य प्रदेश (मप्र) ने इन्वेस्ट मप्र पोर्टल के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया, जिससे 2025 में 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में 420 अरब डॉलर के एमओयू साइन हुए, जिसमें डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी प्रमुख थे। भोपाल इंदौर कॉरिडोर में एचपी और फॉक्सकॉन जैसे निवेशक आ रहे हैं। मप्र ने पीएलआई स्कीम के तहत सोलर मैन्युफैक्चरिंग में 10 गीगावाट क्षमता जोड़ी, जिससे 50,000 नौकरियां सृजित हुईं। राज्य की नीति 25 ने भूमि बैंक तैयार किया, जिसके माध्यम से निवेशकों को तत्काल जमीन उपलब्ध हो रही है। उत्तर प्रदेश (यूपी) ने निवेश आकर्षण में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के बाद 2025 में 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश फलीभूत हुए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप रैंकिंग हासिल कर उप्र ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डेटा सेंटर्स के लिए पांच अरब डॉलर आकर्षित किए। सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत माइक्रोन ने एक अरब डॉलर का प्लांट लगाया, जबकि अडानी और हीरानंदानी ग्रुप ने सोलर प्रोजेक्ट्स में 20,000 करोड़ निवेश किया। उप्र की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ने एफडीआई को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया। परिणाम स्वरूप दोनों राज्यों ने जीएसटी संग्रह में वृद्धि दर्ज की, मप्र में 20 प्रतिशत और यूपी में 25 प्रतिशत, जोकि निश्चित ही निवेश के सकारात्मक प्रभाव को दर्शा रहा है। इसी प्रकार के प्रयास अन्य राज्यों के भी कम-अधिक रहे हैं। यही कारण है कि सामने आई ये यूएनसीटीएडी रिपोर्ट वैश्विक एफडीआई में 14 प्रतिशत वृद्धि दिखाती है, जोकि 1.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसमें डेटा सेंटर्स ने निवेश को नई दिशा दी है, कुल नए प्रोजेक्ट्स का 20 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं से जुड़ा हुआ है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर

270 अरब डॉलर से अधिक घोषित हुए। सेमीकंडक्टर में 35 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसमें भी खास बात यह है कि ये वृद्धि वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी में 25 प्रतिशत गिरावट के सामने आने के बाद है । यहां भारत की यदि हम अन्य देशों से तुलना करें तो विकसित देशों में 43 प्रतिशत उछाल से 728 अरब डॉलर निवेश पहुंचा, किंतु विकासशील देशों में दो प्रतिशत कमी के साथ ये 877 अरब डॉलर रहा। भारत इसका अपवाद बना। चीन में तीसरे साल निवेश में गिरावट आई, आठ प्रतिशत घटकर 107.5 अरब डॉलर। वस्तुतः भारत यहां कई चुनौतियों का सामना प्लेसिबल नीतियों से करने में सफल दिखता है। चिप्स एक्ट और सेमीकंडक्टर मिशन ने ताइवान, जापान से निवेश खींचा। रिन्यूएबल एनर्जी में 500 गीगावाट लक्ष्य ने ग्रीन निवेश को बढ़ावा दिया। इस साल 2026 में भारत ने अपने लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लक्ष्य 100 अरब डॉलर निर्धारित किया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था जिसे लेकर भारत का सबसे अधिक भरोसा है, अनुमान है कि जीडीपी का 20 प्रतिशत योगदान देगी, इसकी कुंजी बनेगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भारत को विकासशील दुनिया का चमकता सितारा बता रही है, जहां केंद्र और राज्य सहयोग मिलकर आर्थिक क्षेत्र के अनेक चमत्कार कर रहे हैं। यदि यह गति बनी रही तो कहना होगा कि भारत 2030 तक पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना साकार करने में सफल हो जाएगा। निश्चित ही भारत का आर्थिक क्षेत्र में ये वैश्विक उभार आज प्रत्येक भारतवासी को गर्व से भरता है।

विवाद बढ़ाने का काम करता चीन

जब अमेरिका भारत के समक्ष समस्याएं खड़ी करने से बाज नहीं आ रहा है, तब चीन भी चिंता का कारण बन रहा है। वास्तव में चीन ने जबसे 1951 में तिब्बत पर जबरन कब्जा करके भारत-तिब्बत सीमा को भारत-चीन सीमा में बदल दिया, तबसे उसके भारत-विरोधी रुख में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। पहले तो उसने 1962 में तिब्बत को छावनी की तरह इस्तेमाल करके भारत पर हमला किया। इसके बाद से वह सैकड़ों किलोमीटर लंबी इस सीमा पर उकसावे की कोई न कोई हरकत करता आ रहा है। आर्थिक और सैनिक शक्ति हासिल करने के बाद तो चीन की यह आक्रामकता सीधी दादागीरी में बदल चुकी है। पहले वह भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के इलाकों पर जुबानी दावे करता था, लेकिन 2017 में डोकलाम घाटी पर कब्जे की कोशिश में मुंह की खाने के बाद उसने पूरी सीमा पर बड़े पैमाने पर सैन्य निर्माण शुरू करके भारत के लिए नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। पिछले दिनों अंतरिक्ष से सीमाओं की टोह लेने वाले भारतीय उपग्रहों से पता चला कि लद्दाख में चीनी कब्जे वाले शक्सगाम इलाके में चीनी सेना एक ऐसी सड़क बना रही है, जो भारत-पाकिस्तान और चीन के इस मिलन क्षेत्र में सियाचिन की सुरक्षा के लिए नए खतरे पैदा कर सकती है। शक्सगाम घाटी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के भारत में विलय के बाद भारत का हिस्सा थी, लेकिन अक्टूबर 1947 में उस पर हमले में पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था। 1962 के भारत-चीन युद्ध के एक साल बाद ही पाकिस्तान ने चीन को खुश करने के लिए 1963 की एक संधि के तहत शक्सगाम का लगभग 5180 वर्ग किमी क्षेत्र चीन को सौंप दिया। रणनीतिक दृष्टि से शक्सगाम के भौगोलिक महत्व को इससे समझा जा सकता है कि यह पाकिस्तान द्वारा भारत से छीने गए गिलगित-बाल्टिस्तान और चीन द्वारा 1949 में कब्जाए गए ईस्ट-तुर्किस्तान (चीन द्वारा दिया गया नया नाम शिनजियांग) को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा यह सियाचिन के बहुत निकट है जो शक्सगाम और भारत के उस अक्साई चिन को अलग करता है, जिस पर 1950 के दशक में चीन ने गुपचुप कब्जा कर लिया था। शक्सगाम में चीन की यह नई सड़क बन जाने के बाद दुनिया के सबसे ठंडे युद्धक्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तानी हमलों से बचाने में जुटी भारतीय सेनाओं के लिए खतरा दोगुना हो जाएगा। आज सियाचिन पर उपस्थिति के कारण भारतीय सेना चीन के सैनिक महत्व वाले काराकोरम हाईवे पर नजर रख सकती है, जिसकी वजह से सियाचिन चीन के आंख की किरकिरी बना हुआ है। इसी क्षेत्र पर कब्जे के लिए 2021 में चीनी सेना ने गलवन में धोखे से हमला किया था। दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में गिने जाने वाले इस क्षेत्र में सड़कों के सैनिक महत्व को इससे समझा जा सकता है कि गलवन कांड के तुरंत बाद भारतीय सेना ने जिस गति और संख्या के साथ चीनी सैनिकों पर जवाबी हमला करके चीन को झकझोर दिया, वह केवल इसलिए संभव हो पाया कि उससे पहले ही भारतीय सेनाओं को लेह और श्योक से गलवन होते हुए दौलतबेग ओल्डी तक पक्की सड़क मिल चुकी थी। मोदी सरकार को इसका श्रेय जाता है कि उसने भारत-तिब्बत सीमा पर लगने वाली लगभग हर चौकी को 70 से ज्यादा नई और बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया है। जैसी उम्मीद थी, सैटेलाइट चित्रों के बाद भारत सरकार ने चीन के समक्ष विरोध दर्ज किया है। न केवल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, बल्कि थलसेना अध्यक्ष ने भी चीन को याद दिलाया है कि शक्सगाम घाटी एक भारतीय क्षेत्र है और उसे चीन को सौंपने वाला 1963 का पाकिस्तान-चीन समझौता गैरकानूनी और अस्वीकार्य है। चीन ने अपने परंपरागत अक्खड़ अंदाज में इस विरोध को अस्वीकार करते हुए इसे दो सार्वभौम देशों के बीच हुआ समझौता बताने का प्रयास किया, लेकिन यह कहते हुए चीनी प्रवक्ता ने इस तथ्य को छिपा लिया कि उस समझौते में साफ-साफ लिखा है कि शक्सगाम भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित इलाका है और भविष्य में इस विवाद के सुलझने पर इस इलाके के अधिकार वाली सरकार से नया समझौता किया जाएगा। शक्सगाम घाटी को लेकर विवाद के बीच सवाल यह है कि चीन ने नई सड़क बनाकर भारत के साथ नया विवाद शुरू करने का फैसला करने के लिए यही समय क्यों चुना। इसे समझने के लिए चीनी रणनीति और इतिहास पर एक नजर डालना काफी होगा। 1912 में स्वतंत्र चीनी गणराज्य की स्थापना के बाद चीन ने तिब्बत, दक्षिणी मंगोलिया और मंचूरिया पर कब्जा करके जिन 14 देशों के साथ सीमाएं साझा की हैं, उनमें से 12 में से अधिकांश के साथ उसने सीमा समझौते ऐसे मौकों पर किए, जब वे किसी न किसी कारण से कमजोर थे और चीन के दबाव में थे, लेकिन भारत और भूटान के साथ उसने सीमा समझौते इस कारण टाले हुए हैं कि धीरे-धीरे लक्षित इलाकों में उनकी जमीन हड़पने के बाद ही और ह्यउचितह्ल अवसर आने पर ही वह ये समझौते करेगा। चीन ने एशिया में हर बड़ी सैन्य कार्रवाई के लिए ऐसे समय का चुनाव किया, जब बड़ी शक्तियां किसी बड़े विवाद में उलझी हुई थीं। उदाहरण के लिए तिब्बत पर कब्जा जमाने के लिए उसने मुख्य सैनिक हमला तब किया, जब उसने सोवियत संघ के साथ मिलकर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच युद्ध शुरू करके अमेरिका को उस झगड़े में उलझा दिया। इसके बाद 1962 में उसने अक्टूबर में भारत पर तब हमला किया, जब क्यूबा में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों की तैनाती को लेकर पूरी दुनिया का ध्यान इस तनाव पर टिका हुआ था। आज भारत के एकमात्र भरोसेमंद दोस्त रूस ने खुद को यूक्रेन के साथ अपने अंतहीन युद्ध में उलझा लिया है और इस कारण काफी कमजोर हो चुका है। चीन-विरोध के नाम पर भारत की मदद का फैसला कर सकने वाला अमेरिका भी इस समय दुनिया भर के साथ आर्थिक टकराव में बुरी तरह उलझा हुआ है।

Social Media Corner

सच के हक में...

मनरेगा गरीबों की जीवनरेखा है। ये कोई प्रशासनिक योजना नहीं बल्कि संविधान के अंतर्गत, करोड़ों मजदूरों के काम का अधिकार थी। ठीक 20 साल पहले कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार ने योजना आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से चालू की थी। मनरेगा पर भारत सरकार ने अब तक करीब 10.63 लाख करोड़ खर्चा किये, जो मनरेगा मजदूरों को दो जून की रोटी, उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन रोकने और उनको शोषण से मुक्त करने में काम आई। मनरेगा के माध्यम से कुल मिलाकर लगभग 4,879 करोड़ व्यक्ति-दिवस का रोजगार सृजित हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 10.10 करोड़ ग्रामीण संपत्तियों का निर्माण हुआ है। पंचायतों का करीब 40 प्रतिशत खर्च मनरेगा पर होता है, जिससे महात्मा गांधी का देखा ग्राम स्वराज का सपना साकार हुआ। आज अहंकारी और गरीब विरोधी मोदी सरकार ने करोड़ों गरीब मजदूरों की जीवनरेखा को छीनने का काम किया है।

(मल्लिकार्जुन खड़गे का 'एक्स' पर पोस्ट)

झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित कर बेसहारा छोड़ने वाले मुख्यमंत्री जी असम में एक छात्र संगठन के कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे और वहां अपने भाषण में शालीनता व मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दीं। अपने संबोधन में उन्होंने चुनाव आयोग, राजभवन और केंद्र सरकार पर आपत्तिजनक व ओछी टिप्पणियां कीं। यह वही संविधान है, जिसके तहत हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, और उसी संविधान में चुनाव आयोग को प्रदत्त अधिकारों का भी स्पष्ट उल्लेख है, जिनके अंतर्गत एसआईआर जैसी प्रक्रियाएं आती हैं। राजभवन पर जेल भेजने का आरोप लगाने से पहले हेमंत जी को यह याद रखना चाहिए कि जमीन घोटाले में ईडी के नोटिस की अवहेलना उन्होंने स्वयं की थी। राजभवन ने उन्हें तलब नहीं किया था, बल्कि वह तो खुद दिल्ली से आधी रात को भागकर राजभवन पहुंचे थे, ताकि गिरफ्तारी से बच सकें।

(बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)

राष्ट्र निर्माण और पंच परिवर्तन

भारत में जीवन आदिकाल से अविरल प्रवाह के समान बह रहा है। इसी में अपनी आहुति डालने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार, जो अपने जीवनकाल में राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए चल रहे सामाजिक, धार्मिक, क्रांतिकारी व राजनैतिक क्षेत्रों के सभी समकालीन संगठनों व आंदोलनों से सम्बध्द रहे व अनेक महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व भी किया था, उन्होंने समाज के स्वाभिमानी, संस्कारित, चरित्रवान, शक्तिसंपन्न, देशभक्ति से ओत-प्रोत, व्यक्तिगत अहंकार से मुक्त व्यक्तियों के ऐसे संगठन जो स्वतंत्रता आंदोलन की रीढ़ होने के साथ राष्ट्र व समाज पर आने वाली प्रत्येक विपत्ति का सामना कर सके, उसकी कल्पना के साथ संघ का कार्य शुरू किया। डॉक्टर हेडगेवार द्वारा 1925 में शुरू हुई संघ की यात्रा, शताब्दी वर्ष तक पहुंच कर भारत के कोने-कोने तक फैल चुकी है। इसी के साथ विश्व के लगभग 80 देशों में 50 से अधिक संगठन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की मथुरा के परखम गांव में स्थित दीनदयाल उपाध्याय गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित बैठक में भारतीय समाज में अनुशासन के भाव को बढ़ाने के उद्देश्य से सरसंघचालक जी ने पंच परिवर्तन- अपने दैनिक जीवन में सामाजिक समरसता, कुटुंब भाव, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, स्वदेशी का आग्रह और नागरिक कर्तव्य बोध के पालन आह्वान किया है, जिससे अनुशासन एवं देशभक्ति से ओतप्रोत युवा वर्ग अनुशासित होकर राष्ट्रोन्नयन की दिशा में कार्य करने के लिए उद्यत हों। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी के शब्दों में, संघ के प्रति समाज आशान्वित है। ऐसे में जो भी बात हम समाज में रखेंगे, उसे समाज स्वीकार करने के लिए तैयार है इसलिए हमें पूर्ण तैयारी के साथ समाज में जाने की आवश्यकता है। सामाजिक समरसता- इसके माध्यम से समाज में जाति और आर्थिक भेदभाव को मिटाना। कुटुंब प्रबोधन- परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार में एक साथ बैठकर भोजन, कीर्तन और त्योहार मना कर हम समाज की टूट रही मूल कड़ी कुटुंब को बनाए रख सकते हैं स्वदेशी- दैनिक जीवन में स्वदेशी का प्रयोग कर भारत की आर्थिक उन्नति में अपना सहयोग कर सकते हैं। स्वदेशी के माध्यम से ह्यस्वह्ल का बोध हो और अपनी समृद्ध संस्कृति पर स्वाभिमान होना चाहिए। पर्यावरण- सनातन में प्रकृति की पूजा की प्रमुखता रही है। अपनी संस्कृति में पेड़ों और जानवरों की पूजा भी की जाती है। अधिक से अधिक पौधे लगा कर, प्रदूषण रोकने के उपायों और नदी, तालाब, पोखर आदि को स्वच्छ बनाते हुए हम इसमें योगदान दे सकते हैं। नागरिक कर्तव्य- प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के बारे में जानकारी लेकर उनका पालन सुनिश्चित करना चाहिए। नागरिक कर्तव्य, एक समृद्ध और लोकतांत्रिक समाज के स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। नागरिक कर्तव्यों को पूरा करना एक प्रकार से सरकार और जनमानस के बीच एक-दूसरे का सम्मान है। आज के संदर्भ में हमारे बच्चों को संवैधानिक कर्तव्यों के पालन, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान, राष्ट्रीय सेवा में योगदान, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा, हिंसा से दूर रहने के प्रति शिक्षित करने की आवश्यकता है। हम सभी को अपने राष्ट्र की गरिमा बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को थोड़ा समय निकाल कर राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करना ही चाहिए। समाज को छोटे मतभेदों भूलकर एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रे होसबाले के शब्दों में, भारत तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है, सामरिक और कूटनीति मोर्चों में बढ़ती महत्ता से सभी परिचित हैं। ऐसे समय में भारतीय समाज को एकजुट होकर सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना है। देश और विदेश में ऐसी अनेक शक्तियां हैं, जो भारत को इस रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं, किंतु स्व के बोध के साथ हमें मिलकर इन शक्तियों को प्रभाव शून्य बनाना है।

बेमतलब की औपचारिकता

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और केरल में उनके समकक्ष राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 20 जनवरी को अपने दस्तूरी विधानसभा संबोधनों के दौरान जो किया, उस पर गैर-भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों के आचरण से बाखबर लोगों को कोई हैरत नहीं हुई। चेन्नई में रवि ने भाषण पढ़ने से मना कर दिया। उनके कार्यालय ने कहा कि भाषण में बेबुनियाद दावों और भ्रामक बयानों को देखते हुए उनका बहिर्गमन उचित था। पिछले तीन सालों में राज्यपाल या तो तैयार भाषण से भटके हैं या बहिर्गमन करने से पहले इसे पढ़ने से इनकार किया है। तिरुवनंतपुरम में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्यपाल के नीतिगत संबोधन को दुरुस्त किया। विजयन के मुताबिक, राज्यपाल ने कैबिनेट द्वारा मंजूर कई हिस्सों को छोड़ दिया और अपनी ओर से चीजें जोड़ीं। लंबे समय से सेवारत राज्यपालों, रवि और आर्लेकर को यह मालूम ही होगा कि किसी राज्यपाल के लिए निर्वाचित सरकार की नीतियों के बारे में राज्य को जानकारी देने वाले भाषण या विशेष संबोधन को हूबहू पढ़ना एक संवैधानिक परंपरा है जिसका वर्षों से मान रखा जा रहा है। ऐसी कोई घटना मौजूद नहीं है, जब ब्रिटिश राजा या रानी आधिकारिक भाषण से हटे हों और भारतीय प्रणाली संसदीय लोकतंत्र के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। फिर भी उन्होंने परंपरा का उल्लंघन करना चुना, जबकि उनके पास राज्य सरकारों के प्रवक्ता (माउथपीस), जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण ने कहा था कि बतौर काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रवि को विवादों को न्योता देने में मजा आता है, लेकिन आर्लेकर ने पिछली बार से अलग आचरण किया। पिछले साल उन्होंने आधिकारिक बाकायदगी से काम किया था और लिखित भाषण से जरा भी इधर-उधर नहीं हुए थे। ऐसा लगता है कि रवि द्वारा परंपरा के बार-बार उल्लंघन से तंग आकर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने साल के पहले विधानसभा सत्र का आरंभ राज्यपाल के संबोधन से करने की प्रथा समाप्त करने के लिए संविधान संशोधन का समर्थन किया है।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

The GPU gap in India's AI dream

India has entered its AI awakening, driven by talent, investment and a fast-modernising digital population. But the country's ambitions face an undeniable bottleneck: the near-total reliance on foreign-made Graphics Processing Units (GPUs) and accelerators.India's AI momentum is real, but it is also fragile. The country seems to be entering a rare convergence of talent, capital and policy intent. AI-first startups are emerging fast, global investors are paying attention and the government is also moving fast on deep-tech infrastructure. As per a paper released by Bessemer, the Indian IT sector is projected to reach $400 billion by 2030, with AI playing a key role in this growth.

However, the foundations of the AI boom rest on a narrow and vulnerable layer: the access to computer or hardware resources that make AI models work. For decades, India's tech dominance has come from scale through millions of engineers, global outsourcing contracts and cost efficiency. AI is reshaping that equation.Ranjit Tinaikar, CEO of Ness Digital Engineering, says, "GenAI is transforming the entire software development industry by significantly increasing productivity and accelerating innovation cycles, ultimately reducing time to market. However, its potential will not be fulfilled if it is viewed as a mere code generation tool, a flawed approach that is common in the world of software development."

The new winners are not service providers but platform builders, like companies that own models, data pipelines and automation systems. With players like Sarvam AI, NxtGen, and BharatGen, India is beginning to build core AI IP, foundation models, agentic platforms and developer tools.That shift is already visible. AI-native firms such as Graph AI and Leena AI are building software-first businesses with minimal human intervention. Hybrid players like Crescendo and Shopdeck are combining automation with human oversight to increase speed and reduce costs. Infrastructure firms like Scale and Turing are becoming essential enablers by supplying data pipelines and model evaluation layers.At the same time, a new class of founders, smaller teams, younger builders and solo entrepreneurs, competing directly in global categories, is emerging. NxtGen entered the AI space, bringing India's first full-stack agentic AI platform, "M," while powering the IndiaAI Mission alongside Jio Platforms, Tata Communications, Yotta and others. Solo founder Bishal Saha started building the Duolingo alternative, backed by AI and Bhashini datasets. Prominent AI-first founders include Bhavish Aggarwal (Krutrim), who is building Indian language LLMs, Maithra Raghu (Samaya AI) for financial AI and Sharbel Cherian (KeyValue Software), known for bootstrapped AI products.

This signals a break from the traditional outsourcing mindset and the beginning of an IP-led ecosystem.

Global capital is responding quickly. Google and Accel have announced investments of up to $2 million in Indian AI startups through a new partnership. In September, Google also partnered with Sarvam AI, Soket AI and Gnani.ai, while IIT-Bombay's BharatGen initiative focussed on advancing AI for Indian languages. Such initiatives show that India is being taken seriously as an AI development hub. Telecom players are also repositioning themselves as AI distribution platforms, bundling models into consumer services and accelerating adoption at scale.

et this expansion is running into a structural limit, namely hardware.

India's AI growth today depends almost entirely on foreign-made GPUs from NVIDIA, AMD and Intel. The IndiaAI Mission relies on roughly 34,000 GPUs, a modest number compared to what leading AI labs consume globally. And unlike software, hardware resources cannot be scaled overnight.Export controls, geopolitical tensions and supply concentration mean that GPU access is not guaranteed. Analysts warn that tighter controls, similar to those imposed on China, could eventually restrict availability or inflate costs.

Faith-based science limits

At a time when India's health system is facing challenges, research funds should be used transparently and efficiently

The recent revelations about a decade-long government-funded Panchagavya research project on cancer at Nanaji Deshmukh Veterinary Science University, Jabalpur, Madhya Pradesh, raise concerns about public accountability, scientific rigour and responsible use of taxpayers' money. An official probe indicates that Rs 1.9-3.5 crore was spent on cow dung, cow urine, raw materials and travel expenses, though the market value of the materials was far lower. Also, there was little to show in terms of credible scientific outcomes after 10 years of work. At a time when India's health system is facing challenges, research funds should be used transparently and efficiently. Research must have a scientific basis. Fundamental disease treatment research requires strict methodology, peer review and evidence-based frameworks. The substantial spending on air travel, vehicles and non-essential equipment under this project suggests poor judgment as also possible mismanagement of public resources, especially when basic cancer research demands robust laboratory capacity.Even if the team believes that it followed the procurement rules, following procedure alone is not enough when the outcome lacks scientific credibility. Funding alternative or traditional remedies can be part of research portfolios, but clear hypotheses and rigorous oversight are needed. Research projects must also have transparent reporting and measurable results. In this case, after years of funding, tangible research outputs are missing. There is also no evidence of effectiveness against cancer. This calls the project's initial approval and oversight into question.The controversy underscores the need for stricter research governance, independent audits of publicly funded projects and a reaffirmed commitment to evidence-based science over speculative or symbolic pursuits. Nanaji Deshmukh Veterinary Science University's defence that all purchases were made according to procedure does not fully address the deeper issue: whether this project met the basic standards of credible scientific research worthy of significant public investment or it succumbed to the difference between science and pseudoscience.How to distinguish science from pseudoscience? 'Falsifiability' is one of the criteria. The research in question or such researches cannot be 'falsified' by another laboratory research and ad hoc hypotheses used in such researches keep them out of the purview of scientific testing, For example, the relation between treatment of cancer and cow dung/cow urine will always remain susceptible to one's faith and belief in the karma theory of diseases and diagnosis and the wrath of Sitala Mata. In this case, there is also another belief about religious sanctity accorded to the cow and cow dung; the same status is not accorded to other members of the cow family (Bovidae) or to their dung. This is called the 'protective belt of auxiliary hypotheses', which is not from science but religion and mythology. The cow will be hailed as 'gau mata'. In progressive research, theory tends to precede data, and theory about the Bovidae family hardly calls for collecting data from only one of its members or its dung or urine.There cannot be a clear demarcation between science and pseudoscience, but fuzzy boundaries (cow or desi cow?), an indefinitely extendable indicator list (first urine or dung of the morning or the later ones), and an unclear nature (age of the cow, does it matter or dairy cows or not?). This research is a project of pseudoscience.Similarly, this cannot be corrected. If the research had produced 'negative' findings, the researcher or methodology would get the blame, not the unscientific belief. This kind of research is expected to deliver 'confirmation' to our beliefs rather than reputation or falsification. Moreover, the 'burden' of reversal proof is shifted to the critic -- that you prove that cow dung does not treat cancer, aka ignorantium falicy.

Anecdotal evidence, whether coming from mythologically guided patients or with no established connectivity, is the characteristic of such research across the world, including about aliens, UFOs or extrasensory perception. The use of obscurantist language and jargon (Kamdhenu) provides such research with family resemblance to science.Science may suffer from its own unique concerns of idioglossia tautology as being a coded private language or seemingly appropriate repetitions, but it never breached the boundaries it had set. Astrology may claim validation akin to astrology but it is not. Decolonising science does not mean throwing rationality, validity and replicability out along with the content created and produced in the Western world. Science can play the pivotal role that we expected from it only when we perceive it as a subject matter for wonder and inquiry rather than taking it ass tool to reclaim Vishwagurudom.Ancient Indian health science and indigenous practices will lose their credibility due to such research. The rigour of systemic review of literature and asking the right questions can only take the 'Indian' science to newer heights. But to assert this, we also need to acknowledge that 'science' will remain science if no adjectives of black or Indian or Hindu or Islamic are added to it. The method of science and science as a discipline are two distinct domains; one may apply the method of science to study a religion, but when science is confined to a region or religion, it will only produce another dogma.Many years ago, Nehru insisted that 'Science alone can solve the problems of hunger and poverty'. Cultivating a scientific temper is not an abstract philosophy but an essential foundation for building a society liberated from superstition, fatalism and irrationality, for which people like Dabholkar, Kalburgi, Pansare and Gauri Lankesh lived and died.

Easing drug trials: Cutting red tape must not risk safety

The Tribune Editorial: The Central government aims to reduce regulatory friction and accelerate pharmaceutical innovation.

REGULATORY relaxation carries inherent risks, especially in a sector as sensitive as drug development, where public health, scientific integrity and commercial interests intersect. The Union Health Ministry's amendments to the New Drugs and Clinical Trials (NDCT) Rules, 2019 — easing trial norms and removing the requirement of test licences for several research activities — must therefore be assessed as much for what they loosen as for what they promise to deliver.The intent behind the reforms is clear. By replacing prior approvals with a system of intimation for low-risk research, waiving permissions for certain bioavailability and bioequivalence studies and shortening approval timelines where licences are still required, the government aims to reduce regulatory friction and accelerate pharmaceutical innovation. For an industry long hampered by procedural delays that added little to safety, these changes could shorten development cycles and lower costs, particularly for generics and early-stage research. Yet faster approvals must not translate into weaker scrutiny or reduced accountability. India's reputation as a reliable supplier of affordable medicines rests on the credibility of its regulatory oversight. Any perception that safeguards are being diluted in the name of ease of doing business risks eroding public trust and inviting global scepticism about the robustness of India's drug approval process.

The shift from a permission-based system to post-intimation places a heavier burden on regulatory vigilance. It demands stronger monitoring mechanisms, transparent reporting and enhanced institutional capacity at the Central Drugs Standard Control Organisation. Without effective audits, real-time data scrutiny and meaningful penalties for violations, regulatory relaxation could open gaps rather than improve efficiency. These reforms, therefore, represent a critical test of balance. If supported by rigorous oversight and accountability frameworks, they can encourage innovation while protecting patient safety. If not, they risk substituting speed for science.

Clubbing anew to old chants

Trendy bhajan gatherings aren't new, but their structure has truly evolved. From George Harrison to Baaba Maal and Jai Uttal, many singers across eras have blended genres to deliver soulful music. The science behind the benefits of chanting align with the spiritual claims of past masters

When none less than the Prime Minister takes note of 'bhajan clubbing', it is time to deconstruct the cool. Speaking in his Mann Ki Baat broadcast last week, he called it a powerful blend of devotion, culture, spirituality and modernity, mentioning Gen-Z to make sure the young and the restless heard him out.

Trendy bhajans are not exactly new to me, though the phrase and the more evolved structure are. When large groups, especially of youngsters, come together in a community event to sing praises to gods, bhajan clubbing gets the 'sober rave' tag in a Hindu package. What is new is the high-energy and nightclub-like atmosphere along with a no-alcohol, all-clean feel.

We now have fancily-named bhajan groups like Backstage Siblings and Keshavam. What's more, their concerts carry ticket prices that resemble club gigs. They are not your everyday free session at the local temple.The phenomenon took me on a reverse swing in time.I had my own brush with bhajan cool in the 1970s and 80s when The Beatles era spawned its early seeds. Guitarist George Harrison embraced Hinduism with a zeal that coincided with the rise of the Hare Krishna movement. As a youngster, I heard 'I am missing you', produced by Harrison, composed by Pandit Ravi Shankar and sung by the sitarist's sister-in-law Lakshmi Shankar. The song expressed a longing to encounter Lord Krishna with English lyrics: "Though I can't see you, I hear your flute all the while." Frankly, I found it somewhat amusing, though melodic, and not quite spiritual, especially as it played as part of Western pop music shows on All India Radio.

Then in 1981, Afro-rock band Osibisa staged a live show on the India Gate lawns in the heart of New Delhi and sang 'Raghupati raghava raja ram' (officially titled 'Joy of Om') that kept spiritual Indi-pop bubbling amid a growing fascination for rock.Spiritual pop goes back in time. Lucknow-born Cliff Richard, who spent his early childhood in Calcutta, embraced Christianity publicly at a rally by American evangelist Billy Graham in 1966, putting behind his hits like 'Bachelor boy' and 'Summer holiday'. His guitar embraced Christian gospel music.

Hinduism was not far behind. In the early 2000s, I saw a bhajan-club act closer to the contemporary version in suburban Bengaluru at the 250-acre Art of Living headquarters founded by Sri Sri Ravi Shankar. The evening saw long-haired rockers wielding electric guitars singing energetic bhajans to thunderous claps.

Looking back, I found Harrison's plaintive 'My sweet lord', released in 1970 soon after the Beatles split, truly devotional because of its rhythmic chanting that blended "Hallelujah" with "Hare Krishna" in a non-denominational spirituality. It seemed to go beyond the shifting sands of cultural modernity.There is a spiritual logic and modern science to this that deserves attention. I have attended meditation sessions led by followers of Paramahansa Yogananda, which were preceded by simple words sung in chants that made way for long spells of silent meditation.Chanting is half the battle," Yogananda famously said. He released a book titled Cosmic Chants that contained songs that had a clearer purpose to invoke devotion. The guru said loud chanting was a good start to meditation in creating a "magnetic flow", but advised transitions into whisper chanting, mental chanting, subconscious chanting and what he called "superconscious chanting".Yogananda said: "Sound or vibration is the most powerful force in the universe. Music is a divine art, to be used not only for pleasure but as a path to god-realisation." That reminds one of Carnatic composer Thyagaraja's description of god as "Nada Brahmam" (Sound as the divine).

I find chants spiritual when done in a coherent, enchanting fashion, irrespective of their origin or religion. I like listening to Gregorian chants that follow Christian traditions, and in a strange way, found Freddie Mercury's chanting chemistry with the crowd at London's Wembley Stadium in his Live Aid concert in 1985 uplifting in a soulful way. After all, the rock bands were raising funds for famine-hit Africans and nursed charitable thoughts. I also find solace in the soulful 'Dunya Salam' by 1 Giant Leap featuring Senegalese singer Baaba Maal, which praises god as Allah in an Islamic prayer. Its lyrics set to a haunting tune are like an Afro version of John Lennon's piano ballad for peace, Imagine.On a more orthodox groove is Jai Uttal, an American devotee of Neem Karoli Baba. Born Douglas Uttal, the Grammy-nominated guitar-wielding singer is called a 'kirtan artist' and hailed as a pioneer in 'world spirit music', a derivative of the more popular world music genre. He sings bhakti-filled chants on Hindu deities and uses elements of jazz, reggae and ballads.

That takes us to the neuroscience behind chants and meditation.The US government's National Library of Medicine says, "The simple act of repeating a sound may increase focused attention while decreasing awareness of bodily sensations. Further, if the repetition of the sound is vocalised, slowed breathing is likely to activate the parasympathetic nervous system," adding that "even if one is distracted, vocalisation is likely to have positive respiratory and hormonal changes that may contribute to feelings of relaxation and positive mood".Bhajan clubbing may thus be just a trendy word for what they call satsang in religious circles and the science behind chants does show the power of congregation as well as health benefits. But there is evidently a need to differentiate between headbanging decibels and soulful chants.

Gold, silver prices continue to fall. Should you buy now

Gold and silver prices have tumbled sharply over the past few days. Read on to know the reason behind the rapid decline, and whether investors should buy or wait for further correction.

New Delhi.(Agency)

Gold and silver have dropped sharply from their recent record highs, raising the natural question for investors: is this dip a buying opportunity or the start of a deeper correction?According to Ponmudi R, CEO of Enrich Money, the latest fall is a cooling phase, not a trend reversal.

SHARP FALL IN GOLD PRICE

MCX gold futures have slipped back into the Rs 1,38,000–1,48,000 band after touching fresh all-time highs near Rs 1,80,779. Ponmudi says the recent swings reflect short-term profit-taking, not long-term weakness."The broader structure remains bullish," he says. "The rising channel is intact and pullbacks are still attracting buyers. Selling pressure is being absorbed efficiently."He highlights the Rs 1,43,000–1,45,000 zone as a strong support area. A sustained move above Rs 1,50,000 could re-open upside toward Rs 1,65,000–1,70,000.

Internationally, COMEX gold has cooled to the $4,580–$4,700 range after briefly crossing $4,900.Ponmudi describes the correction as technical rather than structural."The rally pushed indicators into overbought territory, so this cooling-off is healthy," he explains. "Prices are still holding above major moving averages, which shows the correction is orderly."Strong demand is visible at $4,400–$4,500, which he calls a critical support zone. A breakout above

$5,000–$5,100 could restart the move toward earlier peaks.

SILVER CRASHES

MCX silver has dropped to the Rs 2,50,000–2,60,000 region after a massive surge above Rs 4,00,000 and record highs of Rs 4,20,048.Ponmudi acknowledges the intensity of the pullback. "Silver had become extremely overbought, so fast intraday corrections were expected," he says.

However, he remains confident in the overall trend. "The broader trend is decisively bullish. The rising channel is intact and key EMAs are providing strong support."He identifies Rs 2,35,000–3,40,000 as a critical base zone for silver. Resistance lies near Rs 2,90,000–2,92,000, with room toward Rs 3,25,000 if momentum holds."Dips continue to offer accumulation opportunities," he adds.Meanwhile, COMEX silver is now trading in the $75–$85 consolidation band after hitting a record high above $121.6. Ponmudi says the sharp rise followed by an equally sharp fall is not a red flag.

US futures, Asian shares slip, tracking Wall Street's retreat, while oil falls more than $2

New Delhi.(Agency)

U.S. futures and Asian shares skidded Monday and oil prices fell more than $2 a barrel.

In South Korea, the Kospi tumbled 4.6% to 4,982.54 as worries revived over a potential bubble in the craze for artificial intelligence. Samsung Electronics gave up 3.5%, while chip maker SK Hynix sank 5.6%.

The Kospi has been forging records for weeks as major tech companies piggybacked on the AI craze with deals with major players like chip maker Nvidia.

In other dealigns, the price of gold fell 1%, while silver gained more than 2% after both plunged on Friday in a halt to record runs in precious metals markets.

Markets appeared jittery as investors studied what President Donald Trump's new nominee to lead the Federal Reserve, Kevin Warsh, will mean for interest rates. The future for the S&P 500 sank 0.9% while that for the Dow Jones Industrial Average fell 0.5%.

U.S. benchmark crude lost $2.80 to $62.41 per barrel. Speaking to reporters aboard Air Force One, Trump said Iran should negotiate a "satisfactory" deal to prevent the Middle Eastern country from getting any nuclear weapons. "I don't know that they will. But they are talking to us. Seriously talking to us," he said.That comment apparently assuaged some worries over potential disruptions to oil supplies that had pushed prices higher, analysts said. Brent crude fell $3 to $66.32 per barrel.In Tokyo, the Nikkei 225 index edged 0.2% higher to 53,422.01, but other regional benchmarks retreated.Hong Kong's Hang Seng dropped 2% to 26,841.45, while the Shanghai Composite index sank 1.1% to 4,071.14. In Australia, the S&P/ASX 200 fell 1.1% to 8,766.70. Taiwan's Taiex lost 2.1%.

Budget holds little promise for election-bound states

New Delhi.(Agency)

As Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Assam gear up for fiercely contested Assembly elections in the coming months, the Union Budget 2026–27 has drawn criticism from Opposition-ruled states.

While the poll bound states received allocations from rare earth corridor to high-speed rail corridor, turtle trails, and coconut promotion scheme, Opposition leaders argued that the proposals lacked allocations or new schemes that could provide immediate relief or long-term support to states facing fiscal stress.

While the BJP is eyeing a major breakthrough in Tamil Nadu in this election, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced sops including high speed rail links for Chennai, ecologically sustainable mountain trail in Podhigai Malai in the Western Ghats and a rare earth corridor for the state."We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated Rare Earth Corridors to promote mining, processing, research and manufacturing." For Kerala, the Budget has proposed a Coconut Promotion Scheme to enhance productivity by replacing non-productive trees withnew varieties.

While West Bengal received a new dedicated freight corridor linking Dankuni in West Bengal to Surat in Gujarat, an integrated East Coast Industrial Corridor with a major node at Durgapur to support industrial growth. Another state Assam received an infrastructure boost on Tier-2 and Tier-3 cities, as well as the announcement of Buddhist Circuits.

Customs duty tweaked to reduce manufacturing costs

New Delhi.(Agency)

The Union Budget 2026-27 has introduced a wide set of changes to customs duty aimed at lowering input costs for manufacturing and exports, while tightening tax rules in selected areas.

Customs duty on all dutiable goods brought in for personal consumption has been cut to 10% from 20%. This is expected to reduce the cost of items carried back from overseas travel. Medicines have also received significant relief. The government has removed basic customs duty on 17 cancer medicines and expanded duty exemptions for drugs used to treat rare diseases.Further, a series of exemptions targets manufacturing and energy security. Specified parts used to manufacture microwave ovens have been exempted from basic customs duty. Capital goods required for processing critical minerals in India will now attract zero duty, while exemptions on capital goods used for lithium-ion cell manufacturing, including battery storage systems, have been continued. Inputs such as sodium antimonate used in solar glass manufacturing have also been made duty-free.The Budget extends relief to the aviation and power sectors. Aircraft manufacturing and maintenance will benefit from exemptions on specified components and raw materials. Imports required for nuclear power projects will remain duty-free until 2035. Fish caught by Indian fishing vessels in international waters have been made fully exempt from customs duty.Revenue Secretary Arvind Shrivastava said, "Customs duty reductions have a logic for each sector, based on the need for certain items to be brought into India and to ensure that customs duty does not add to their cost." He added that the focus was on boosting manufacturing volumes and exports rather than relying on higher tax rates.In cleaner energy, the entire value of biogas has been excluded while calculating excise duty on biogas-blended CNG, effectively lowering taxes on greener fuel blends.Exporters have also been given more flexibility. Exporters in textiles, leather garments, footwear and leather products will now get one year, instead of six months, to export finished goods after importing inputs duty-free.The Budget has also opened the door for foreign companies providing cloud services to customers outside India using data centres located in India, offering them a tax holiday until 2047.

Why the government raised STT, making F&O trading more expensive

New Delhi.(Agency)

The cost of trading in futures and options was raised in the Union Budget 2026, a move that has drawn attention from traders and retail investors. Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear in her Budget speech that the Securities Transaction Tax, or STT, will go up for derivatives trades from April 1, 2026."I propose to raise the STT on Futures to 0.05 percent from present 0.02 percent. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15 percent from the present rate of 0.1 percent and 0.125 percent respectively," said the Finance Minister.The government says the decision is aimed at addressing excessive speculation in the derivatives market rather than targeting long-term investors.

WHAT EXACTLY HAS CHANGED IN

STTUnder the existing framework introduced through the Finance Act (No. 2), 2004, STT is charged on trades carried out on recognised stock exchanges.Until now, futures attracted an STT of 0.02 percent on the traded price, while options were taxed at 0.1 percent on the option premium and 0.125 percent on the intrinsic value when exercised.Budget 2026 has revised these rates upward. STT on futures has been increased to 0.05 percent, while both option premium and option exercise now attract a uniform rate of 0.15 percent.These revised rates will apply to all derivatives transactions entered into on or after April 1, 2026.

WHY THE GOVERNMENT FELT A NEED TO STEP IN

According to the Income Tax Department, the scale of futures and options trading in India has become extremely large when compared with the real economy.In a post shared by the Income Tax Department, the government pointed out that the total volume of transactions in options and futures is more than 500 times India's GDP.In simple terms, while India's GDP stands at around Rs 300 lakh crore, the volume of derivatives trading has crossed Rs 1.5 lakh lakh crore. The department said this gap shows that a large part of F&O trading is driven by short-term bets rather than genuine hedging or investment needs.

Why LTCG tax is back in the spotlight after Budget 2026

New Delhi.(Agency)

Long-term capital gains, or LTCG, has suddenly become one of the most talked-about tax terms after the Union Budget 2026. Even though the government largely kept capital gains tax rules unchanged, investors across equities, gold and derivatives are paying close attention. The reason is simple: expectations were high, but the Budget chose stability over relief.

WHAT BUDGET 2026 SAID ON CAPITAL GAINS

In Budget 2026, the government decided not to disturb the existing capital gains framework for FY 2026–27. For equity investors, long-term capital gains continue to be taxed at 12.5 % after one year, with the annual exemption limit staying at Rs 1.25 lakh. Short-term gains on equity remain taxed at 20%.

Many investors were hoping for a higher exemption limit or a lower tax rate, especially with markets touching record highs. That did not happen, which is why LTCG quickly started trending in searches and discussions.EQUITY INVESTORS REACT TO STATUS QUO

Equity investors form the largest group affected by LTCG rules. Since there was no tax relief, many are reassessing their selling plans. Investors sitting on long-term profits are now more cautious, as crossing the exemption limit still triggers tax liability. The Budget has overhauled share buyback taxation by shifting it from dividends to capital gains and increasing the effective tax on promoters. The new rules, once legislated, will apply to buybacks carried out after April 1.This has brought LTCG back into everyday money conversations, from social media to brokerage forums.

GOLD TAX RULES ADD TO THE BUZZ

Gold taxation has also played a role in pushing LTCG into the spotlight. The Budget continues to tax gold without indexation benefits.Whether it is physical gold, digital gold or gold ETFs, long-term gains are taxed at 12.5%. Short-term gains are added to income and taxed as per slab rates. With gold prices rising sharply over the past year, investors are realising that tax outgo on profits can be higher than expected.SOVEREIGN GOLD BONDS LOSE SOME SHINE

Another big reason LTCG is in the news is the change in Sovereign Gold Bonds. While original subscribers still enjoy tax-free maturity, those buying SGBs from the secondary market after April 1, 2026 will no longer get this benefit.

Their gains will now be taxed like other capital assets, making investors rethink earlier assumptions.

Sensex, Nifty open flat but surge ahead a few minutes into early trade

The S&P BSE Sensex was up 161.62 points to 80,884.56, while the NSE Nifty50 added 9.80 points to 24,835.25 as of 9:28 am.

New Delhi.(Agency)

Benchmark stock market indices opened flat but traded higher a few minutes after the opening bell, helped by gains in metal and energy stocks.The S&P BSE Sensex was up 161.62 points to 80,884.56, while the NSE Nifty50 added 9.80 points to 24,835.25 as of 9:28 am.Dr. VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Investments Limited, said that it is important to understand that the Budget is a growth-oriented Budget with fiscal prudence.The 10% nominal GDP growth projected in the Budget is achievable and has the potential to deliver around 15% earnings growth in FY27. The market will soon start discounting this positive. But it is

possible that FIIs may continue to sell impacting the market," he added.After the opening bell, Adani Ports and Special Economic Zone Ltd led the Sensex gainers, rising 3.26%. Asian Paints Ltd followed with a gain of 2.20%, while Larsen and Toubro Ltd was up 2.15%. Reliance Industries Ltd gained 1.24%, and Eternal Ltd also opened higher, rising 1.11%.

On the losing side, Infosys Ltd saw the sharpest fall, dropping 1.99%. ITC Ltd declined 1.95%, Titan Company Ltd was down 1.78%, Hindustan Unilever Ltd slipped 1.39%, and State Bank of India Ltd fell 1.01%.Retail investors should keep their cool and remain invested and continue to invest systematically. A significant upturn in the market may take time; perhaps a retreat from AI trade globally. We don't know when this will happen. But we know that an earnings rebound is imminent in response to this growth oriented Budget. That is a clear positive.

Modest rise in agriculture budget, but research funding cut amid calls for infrastructure investment

The budgetary allocation for 2026–27 represents an increase of around 2.56% over the previous year's Budget Estimates and over 6% compared to last year's Revised Estimates.

New Delhi.(Agency)

Despite describing agriculture as the primary engine of growth, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced only a modest increase in funding for the sector, while allocations for agricultural research have declined.

The budgetary allocation for 2026–27 represents an increase of around 2.56% over the previous year's Budget Estimates and over 6% compared to last year's Revised Estimates. However, funding for agricultural research has been reduced by approximately 5%.The total allocation for the Department of Agriculture and Farmers' Welfare stands at ?1,30,661.38 crore for 2026–27, up from ?1,27,290 crore in 2025–26. Nearly half of this amount will be disbursed directly to farmers through the PM-KISAN scheme, which provides income support of ?6,000 per year to each farm household.

A significant increase has been announced for the Krishonnati scheme, which has received a 40% boost compared to the previous year. The allocation for the scheme has risen to ?11,200 crore from ?8,000 crore last year. Krishonnati serves as an umbrella programme encompassing 11 initiatives, including missions for fruits and vegetables and village uplift programmes in tribal areas.

Funding for the Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) has remained largely unchanged, with a marginal increase from ?8,500 crore in 2025–26 to ?8,550 crore in 2026–27.There is a renewed focus on natural farming, with allocations for the National Mission on Natural Farming (NMNF) increasing by over 21% from the previous year. While the Revised Estimate for the current year stands at ?725 crore, exceeding the original allocation, the budget for 2026–27 has been set at ?750 crore.

For coconut cultivation, the Finance Minister has maintained the allocation at ?37.16 crore, in line with the Revised Estimate for the current fiscal year, compared to ?35 crore in the previous year.In addition, Sitharaman announced a

new support scheme for high-value crops, including coconut, sandalwood, cocoa and cashew in coastal regions, as well as almonds, walnuts and pine nuts grown in hilly areas. This push is aligned with recently signed free trade agreements with European countries and the UK. The government aims to strengthen value chains for crops such as cashew, cocoa and almonds, which India largely imports and often sends abroad for processing despite domestic production.Commenting on the budget, Siraj Hussain, former Secretary of the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, said, "The support for fisheries, animal husbandry, dairy, coconut, almond, walnut and sandalwood is commendable, but there is no allocation for direct investment in agricultural infrastructure. We need to invest in our Agricultural Produce Market Committees (APMCs) to develop at least some of them into world-class facilities."Allocations for the Price Stabilisation Fund have been increased by around 4%, taking the total to ?7,200 crore.The government has also proposed the introduction of a multilingual AI chatbot that will integrate the Agristack portals with Indian Council of Agricultural Research (ICAR) packages on agricultural practices, leveraging artificial intelligence to support farmers.

Weeks after Delhi HC's rap, Lawrence Bishnoi rival Parvesh Mann sentenced to 7-year jail by sessions court

Along with Parvesh, five of his allies — Sachin Mann, Ajay Mann, Yudhveer, Sahil Dahiya and Gaurav Tyagi — were also convicted on January 28. Judge Chander Jit Singh sentenced the four — in jail since 2021 — to five-year imprisonment.

New Delhi.(Agency)

Weeks after the Delhi High Court rapped the sessions court over the delay in the pronouncement of verdict in a 2019 Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA) case against gangster Parvesh Mann, a rival Lawrence Bishnoi, the sessions court in Karkardooma on Saturday sentenced the gangster to seven years in jail.

Parvesh Mann alias Sagar Mann was tried under sections 3 and 4 (conspiring, committing or facilitating organised crime) of MCOCA, stemming from a FIR lodged by the Delhi Police Special Cell, which took note of his involvement in organised crime. The case was probed by ACP Jasbir Singh.

Along with Parvesh, five of his allies — Sachin Mann, Ajay Mann, Yudhveer, Sahil Dahiya and Gaurav Tyagi — were also convicted on January 28. Judge Chander Jit Singh sentenced the four — in jail since 2021 — to five-year imprisonment. He directed that they "undergo the period of custody already undergone" and also pay a fine of Rs 5 lakh. If they default on the fine, they would have to serve two years in jail.

Mann and his aide Gaurav Tyagi — also sentenced to seven years in jail – have been behind bars since 2020 and 2021, respectively. Mann also has to pay a fine of Rs 5 lakh.

Tyagi, allegedly the key henchmen for Mann, was arrested after an exchange of fire with the Special Cell sleuths in November 2021.An officer said that Tyagi, once hailed as a wrestling prodigy, became a sharpshooter for Mann after he lost his chances of making it big as a sportsman due to an injury. The delay in trial

Even as the Delhi Police's Special Cell had arrested Mann in 2020, the trial was completed after nearly five years while the gangster remained behind bars in Northwest Delhi's Mandoli jail.

While the sessions court had concluded Parvesh's trial on July 4, 2025, and fixed July 30, 2025, as the date to pronounce the verdict, the final judgement was not announced on four subsequent dates. On November 7, 2025, the sessions court again deferred the pronouncement, directing that the accused be produced physically not virtually, as it fixed November 28, 2025, as the date for the pronouncement of the verdict. However, the judge, who had heard the matter, was transferred on November 18, 2025. The sessions court then issued directions that the final arguments be heard again. Mann had then moved the High Court, seeking that the order for fresh trial be set aside.

Justice Swarana Kanta Sharma of the HC last month ordered that the trial be completed in the sessions court in two-three weeks. Setting aside the lower court's decision, the Judge recorded in the order, "Judicial proceedings cannot oscillate between readiness and uncertainty in this manner, particularly after the trial has concluded…"

The bloody 'Mann' wars

Parvesh Mann, a key member of the Neeraj Bawana gang, had 14 cases lodged against him. He has been known for his rivalry with gangster Kapil Mann, a Lawrence Bishnoi ally and Pavesh's neighbour from Outer Delhi's Khera Khurd village.

Their rivalry, according to the police, began about 17 years ago, when Parvesh and Kapil's families got embroiled in a battle for control over Khera Khurd village — including a 100 yard long boundary wall.

Pune Porsche crash: 3 accused get bail, Supreme Court cites long incarceration

New Delhi.(Agency)

The Supreme Court has granted bail to three accused in the 2024 Pune Porsche case, in which two people were killed. Aditya Avinash Sood, Ashish Satish Mittal, and Amar Santosh Gaikwad were arrested on charges of swapping blood samples of the primary accused, who were minors and inside the car at the time, with their own.

During the hearing, the bench comprising Justice BV Nagarathna and Justice Ujjal Bhuyan, said that there was no point in multiplying the witnesses in the case when the petitioners have been in undertrial custody for more than three years. As many as 159 witnesses are yet to be examined in the matter.

"Even if it is held that it was the juvenile who caused the accident, he is being procedured against before the JJB. Thus, it was contended that continued incarceration of these appellants in the absence of any progress in the trial and the possibility of delay due to more than a hundred prosecution witnesses would cause them prejudice," the bench noted. The Pune case had drawn nationwide backlash as the primary accused in the case was 17 at the time. He had driven the luxury sports car in a drunken state and fatally knocked down two techies, Aneesh Awadhiya and Ashwini Koshta, who were on a scooter. Hours later, the Juvenile Justice Board granted bail to the teen, directing him to do work in police for 15 days, write a 300-word essay on road accidents, undergo treatment for drinking habits and take counselling sessions. The decision invited even more nationwide outrage.

Sood and Mittal were arrested on August 19 last year after their blood samples were used for tests and swapped out with the two minors who were in the Porsche along with the 17-year-old at the time of the incident. The Bombay High Court rejected Sood and Mittal's pleas along with six others in December last year.

Delhi University case against blind equity policies

New Delhi.(Agency)

The Supreme Court has come to the timely rescue of the government by staying the UGC Equity Regulations 2026. Before the things could get out of the hands, more within the core supporters of the ruling BJP, the apex court may have given the ruling establishment breathing space by putting the matter onto the back burner.

Has such 'affirmative' measures in the higher education institutes like the UGC Equity Regulations 2026 always yielded desired results? If we were to take a case study of the Delhi University, the introduction of reservation for the OBCs has created a considerable loss to the academic environment. If one were to limit the study to the conduct of DU Students Union (DUSU) elections alone, the contests

for the main posts have come to be limited between two prominent OBC communities. What should ideally be a democratic exercise representing the collective student body has gradually turned into a contest dominated by caste consolidation.

Elections have ceased to be driven by ideological debate, policy vision, or student welfare. They have become vulgar ostentation of money power and community muscle. Campaigns are marked by extravagant spending, aggressive mobilisation, and patronage networks that resemble mainstream electoral politics rather than campus democracy. In such an atmosphere, the election machinery often appears reduced to the role of helpless minions.

Delhi wakes up to cleaner air after overnight drizzle. Here's the week's forecast

New Delhi.(Agency)

Light rain in several parts of NCR and calm winds overnight triggered dense fog across Delhi on Monday, prompting the India Meteorological Department (IMD) to first issue a red alert in the wee hours. This was later scaled down, and a yellow alert now remains in place for the forenoon hours.

As a result of the dense fog stretching late into the morning, the visibility dipped to as low as 100 m for several hours at Safdarjung and Palam. The weather conditions, however, helped improve Delhi's air quality as it turned to 'Moderate' (181 AQI) by Monday morning, after the daily average AQI was reported at 265 in the 'Poor' range on Sunday. February, meanwhile, is expected to remain warmer and relatively dry.

What led to the dense fog?

Senior meteorologists attributed the fog formation to stable atmospheric conditions created after the overnight rain spill. High moisture levels coupled with very weak winds allowed cool air to be trapped near the ground, resulting in condensation to fog.

"After the overnight rain, there were only very light winds which didn't allow the moisture to disperse. This is why,

earlier when rainfall was heavier on January 23 and 27, no such fog was seen because stronger winds had prevented it," said R K Jenamani, senior scientist and head of weather forecast services in IMD.

On Sunday, moisture-laden easterly winds of up to 15 kmph were recorded, which increased humidity across the region. According to the IMD Meteorological Centre, Lucknow, the overnight rain was observed in parts of NCR, including Gautam Buddha Nagar (1 mm), Meerut (5 mm), Muzaffarnagar (6 mm) and Agra (2.2 mm). There was no rainfall recorded in Delhi. Impact of 'feeble western disturbances': No rain, increase in temperature The IMD has said that a fresh feeble western disturbance is likely to affect the higher reaches of the Himalayan region from Monday night. Another western disturbance is expected to impact northwest India from the night of February 5.

Dr Mrutyunjaya Mohapatra, Director General (IMD), had earlier on Saturday said that Northwest India, including Delhi, would see higher day and night temperatures because of "weaker western disturbances". He said the cloud cover will lead to increase in night temperatures, but a lack of rain would result in warmer days.

Traffic cops, officials blackmailed using video clips: 2 more linked to 'sticker extortion racket' arrested, 10 held so far

New Delhi.(Agency)

Two men linked to the 'sticker extortion racket' — involving gangs that allegedly targeted traffic police personnel and government officials in Delhi by covertly recording and manipulating videos to blackmail them — have been arrested, officers said on Sunday, adding that this takes the total number of arrests related to the racket to 10 so far. While one of the accused allegedly collected the extortion money, the other recorded videos used for blackmailing the officials and traffic police personnel, said police.

Three such gangs — that together operated the alleged syndicate violating the city's pollution-control and traffic regulations — have been busted by the Delhi Police over the last month. All three gang leaders — Raju Meena, Jeeshan Ali and Rinku Rana — have been arrested. The gangs allegedly assured transporters that no challan would be issued against their vehicles bearing the stickers that were sold to them by the syndicate.Sanjay Gupta, one of the two suspects recently arrested, was a member of the Raju Meena Gang, said police. He was apprehended on January 20. "He was trained for preparing videos for the purpose of extortion after manipulating traffic police personnel and officials," DCP (Crime) Sanjeev Yadav said. He is the third arrest from the Raju Meena gang.

Amir Chaudhary, the other suspect, worked for the Jeeshan Ali gang.

He was caught while he was blackmailing a Delhi Traffic police officer on January 17. "He is a cab driver by profession and also a key associate of Jeeshan Ali. He was apprehended red-handed during an extortion bid," DCP Yadav said.

4.78% more funds for Delhi Police in Union Budget 2026-27, eye on modernisation

New Delhi.(Agency)

Delhi Police has been allocated Rs 12,846.1 crore in the 2026-27 Union Budget, an increase of 4.78% from the 2025-26 fiscal year.

The higher allocation is aimed at meeting routine expenditure while also supporting modernisation efforts, particularly in traffic management and communication infrastructure, across the National Capital Region (NCR).

For the current financial year 2025-26, the Budget allocated to the force was Rs 12,259.1 crore.

The funds will be used to pay for day-to-day operational costs, salaries, and pensions, as well as for specific schemes such as the development of a model traffic management system and the strengthening of an integrated communication network.

Officers said investments are also planned for upgrading technological capabilities, installing traffic signals at critical junctions, and training personnel to handle emerging challenges in urban policing. Delhi Police is tasked with maintaining law and order in the National Capital Territory of Delhi, a responsibility that includes traffic regulation, crime control, crowd management, counter-terror operations,

and ensuring security during major public events.

With Delhi witnessing steady population growth, rising number of vehicles, and increasing interconnectivity with surrounding NCR cities, the force has repeatedly flagged the need for improved infrastructure and technology-driven policing.

The 2026-27 allocation places particular emphasis on traffic management, an area that has emerged as a critical concern amid mounting congestion, frequent accidents, and the expansion of road networks in Delhi-NCR. The proposed model traffic system is expected to focus on better signal coordination, real-time monitoring, and improved enforcement mechanisms. Strengthening communication networks is also seen as crucial for enhancing coordination between police units and with other law enforcement agencies operating in the region. In recent years, budgetary allocations to the Delhi Police have shown a pattern of incremental increases rather than sharp jumps.

Funds worth Rs 12,259.1 crore allotted to the force in 2025-26 followed an allocation of around Rs 11,300 crore in 2024-25 and approximately

Finance Commission recommends Rs 66,100-cr grant for urbanisation, revamp of drainage in cities

New Delhi.(Agency)

Flagging the urgent need for improving the drainage system in cities and the slow pace of urbanisation, the 16th Finance Commission has recommended a Rs 56,100 crore grant for wastewater management projects in selected cities and a Rs.10,000 crore urbanisation premium.

The report of the 16th Finance Commission, which was tabled in the Parliament on Sunday, said it's primarily focussing on "accelerating urbanisation".

"First, there is an urgent need for the revamp of the drainage system in Indian cities. While the large metros are in a position to raise their own fiscal resources for this purpose, the same is not true of the smaller cities.

Therefore, taking into account the availability of limited resources, we have recommended the provision of some fiscal resources for revamping the drainage system in the middle-level municipalities on a cost-sharing basis," the report said. The Finance Commission recommended a Special Infrastructure Component of Rs.56,100 crore for wastewater projects of selected cities. A total of 22 cities, including Pune, Jaipur, Lucknow, Kanpur, Nagpur, Patna, Rajkot, Amritsar, Madurai and Howrah, are eligible for this component.

The report highlighted the example of Indore's wastewater management as a successful model, saying it had transformed itself, ranking number one in the Swachh Survekshan for seven consecutive years. Incidentally, Indore has seen a spate of deaths of residents who drank contaminated water in the past month.

"Efficient liquid waste management was achieved through comprehensive interception of household and grey water sewage outfalls into rivers and stormwater drains, coupled with the establishment of a robust sewerage network," it said of Indore. The report also noted that the process of urbanisation was taking too long.

"Second, we have observed that there are unusually long delays in conferring a statutory urban status on areas that come to exhibit all urban characteristics. India's

urbanisation process remains constrained by the slow and ad-hoc conversion of census towns into statutory towns and the hesitant merger of peri-urban areas into nearby urban local bodies. Such areas continue to be governed by rural local bodies (RLBs), which are ill-equipped to manage the burgeoning demands of an urbanising population," the report said.

It recommended a Rs.10,000 crore urbanisation premium to incentivise the transition from rural to urban. The report recommended the incorporation of peri-urban areas, or rural areas that have acquired substantial urban features, into the adjacent municipal bodies.

The Finance Commission recommended a total of Rs.3,56,257 crore for urban local bodies from 2026-2027 to 2030-2031, of which Rs.2,32,125 crore is the basic grant, Rs.29,016 crore ULB performance component, Rs.56,100 crore Special Infrastructure Component and Rs.10,000 crore as the urbanisation premium.

NEWS BOX

Russian drone attack on bus carrying mine workers in Ukraine's Dnipropetrovsk kills 12

KYIV. (Agency)

A Russian drone attack on a bus carrying mine workers in Ukraine's central-eastern Dnipropetrovsk region Sunday killed at least 12 people, officials said.

The bus was driving in the vicinity of Ternivka, a town about 65 kilometres (40 miles) from the front line, according to police.DTEK, Ukraine's largest private energy firm, said those killed were travelling from one of its mining facilities in the region after they had finished their shift.Images published by Ukraine's state emergency service showed what appeared to be an empty bus, its side windows shattered and windscreen hanging from the front."The enemy drone hit near a company shuttle bus in the Pavlograd district. Preliminarily, 12 people were killed and seven more were wounded," the head of the regional military administration, Oleksandr Ganzha, said on Telegram.AFP was not able to immediately verify the circumstances of the attack.An earlier drone attack in the region overnight killed a man and a woman in the central city of Dnipro, Ganzha said in an earlier post.

The attacks came the same day a unilateral reduction in Russian strikes on Ukraine announced by US President Donald Trump was due to end.Trump said Thursday that Putin had agreed to stop strikes on Kyiv and "various towns" during cold weather.The terms of his agreement with Russian President Vladimir Putin were not clear, and the Kremlin did not link the alleged truce to the weather.Earlier Sunday, a Russian drone struck a maternity hospital in Ukraine's southern Zaporizhzhia region, wounding at least seven people including two women receiving a medical examination, the region's governor said.

Nvidia CEO Denies Being "Unhappy" With OpenAI, Reaffirms Plans For Investment

World. (Agency)

Nvidia plans to make a "huge" investment into OpenAI, probably its largest ever, CEO Jensen Huang said on Saturday, denying he was unhappy with the ChatGPT maker.The chipmaker in September announced plans to invest up to $100 billion in OpenAI, a deal that would give OpenAI the cash and access it needs to buy advanced chips that are key to maintaining its dominance in an increasingly competitive landscape.The Wall Street Journal reported on Friday that the plan had stalled after some inside the chip giant expressed doubts about the deal.The report said Huang had privately underlined to industry associates in recent months that the original $100 billion agreement was non-binding and not finalised.Huang has also privately criticised what he has described as a lack of discipline in OpenAI's business approach and expressed concern about the competition it faces from the likes of Alphabet's GOOGL.O Google and Anthropic, the WSJ said.Speaking to reporters in Taipei, Huang said it was "nonsense" to say he was unhappy with OpenAI."We are going to make a huge investment in OpenAI. I believe in OpenAI, the work that they do is incredible, they are one of the most consequential companies of our time and I really love working with Sam," he said, referring to OpenAI CEO Sam Altman."Sam is closing the round (of investment) and we will absolutely be involved," Huang added. "We will invest a great deal of money, probably the largest investment we've ever made."Asked whether it would be over $100 billion, he said: "No, no, nothing like that".It was up to Altman to announce how much he wanted to raise, Huang added.

US Partial Shutdown May End On Tuesday. How It Differs From Full Cease

World. (Agency)

The partial government shutdown is vastly different from the record closure in the fall. That is mostly because this shutdown, which started Saturday, does not include the whole of government and may not last long, even as it now drags into the new week.

The House had hoped to pass funding legislation quickly when lawmakers return Monday evening, and that would have ended the shutdown. But House Speaker Mike Johnson, R-La., now says he is hoping to have the package considered "at least by Tuesday" as he scrambles to round up votes and Democrats hold out for deeper changes to immigration enforcement.

Congress already has passed half this year's funding bills, ensuring that several important federal agencies and programs continue to operate through September. Nutrition assistance programmes, for example, should be unaffected.Funding is lapsing, at least temporarily, for the Pentagon and agencies such as the departments of Homeland Security and Transportation. Essential functions are continuing, but workers could go without pay if the impasse drags on. Some could be furloughed.The government funding process had been going smoothly, with key lawmakers in the House and Senate finding bipartisan agreement. But the shooting deaths this month of two US citizens, Alex Pretti and Renee Good, by federal agents in Minneapolis, changed the dynamic.Democrats were incensed after Pretti's killing and demanded that one of the six remaining funding bills, for DHS and its associated agencies, be stripped from the package passed by the House. They said the bill must include changes to immigration enforcement, including a code of conduct for federal agents and a requirement that officers show identification.

Pakistan says it has killed 145 'terrorists' in Balochistan after deadly attacks

QUETTA. (Agency)

Pakistani police and military forces killed over a 100 terrorists in counterterrorism operations across the restive southwestern province of Balochistan over the past 40 hours, government officials said on Sunday, a day after coordinated suicide and gun attacks killed 33 people, mostly civilians.

The raids began early Saturday at multiple locations across Balochistan, and left 18 civilians, including five women and three children, and 15 security personnel dead, authorities said.Sarfraz Bugti, the provincial chief minister, told reporters in Quetta that troops and police officers responded swiftly, killing 145 members of "Fitna al-Hindustan," a phrase the government uses for the allegedly Indian-backed outlawed Baloch Liberation Army, or BLA.The number of militants killed over the past two days was the highest in decades, he said."The bodies of these 145 killed terrorists are in our custody, and some of them are Afghan nationals," he said.Bugti claimed that the "Indian-backed terrorists" wanted to take hostages but failed to make it to the city center.

He spoke alongside senior government official Hamza Shafqat, who often oversees such operations against insurgents in the province, and praised the military, police and paramilitary forces for repelling the assaults.Militant attacks erupted on Saturday in a resource-rich region where Pakistan is seeking to attract foreign investment in mining and minerals. In September 2025, a U.S. metals company signed a $500 million investment agreement with Pakistan, a month after the U.S. State Department designated BLA and its armed wing as a foreign terrorist organization.Residents described scenes of panic after a suicide bombing killed several police officers on Saturday. "(It) was a very scary day in the history of Quetta," said Khan Muhammad, a local resident. "Armed men were roaming openly on the roads before security forces arrived."

Bugti repeatedly accused India and Afghanistan of backing the assailants and said senior leaders of the BLA, which claimed responsibility for the latest attacks in Balochistan, were operating from Afghan territory. Both Kabul and New Delhi deny the allegations.He said on Sunday Afghanistan's Taliban had pledged under the 2020 Doha agreement not to allow Afghan soil to be used as a base for

attacking other countries, but "unfortunately, the Afghan soil was still being used against Pakistan."Tensions between Pakistan and Afghanistan have persisted since early October when Pakistan carried out airstrikes on what it described as Pakistani Taliban hideouts inside Afghanistan, killing dozens of alleged insurgents.Bugti said militants stormed the home of a Baloch laborer in Gwadar and killed five women and three children. He condemned the killings. He said the attackers had planned to seize hostages after storming government offices in Quetta's high-security zone but were thwarted. "We were aware of their plans, and our forces were prepared," he said.The BLA is banned in Pakistan and has carried out numerous attacks in recent years, often targeting security forces, Chinese interests and infrastructure projects.Authorities say the group has operated with support from the Pakistani Taliban, known as Tehrik-e-Taliban Pakistan, or TTP. The TTP, a separate group, is allied with Afghanistan's Taliban, who returned to power in August 2021.

Balochistan has long faced a separatist insurgency by ethnic Baloch groups seeking greater autonomy or independence from Pakistan's central government. The BLA regularly targets Pakistani security forces and has also attacked civilians, including Chinese nationals among the thousands working on various projects in the province.

Tibetan spiritual leader Dalai Lama wins first Grammy for spoken-word album

NEW YORK (Agency)

Tibetan spiritual leader the Dalai Lama has won a Grammy Award for his spoken-word audiobook Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama, marking a notable moment at the 68th Grammy Awards.

The album earned the top honor in the spoken-word category, beating out a diverse field of nominees that included US Supreme Court Justice Ketanji Brown Jackson for Lovely One: A Memoir, Trevor Noah for Into The Uncut Grass, Kathy Garver for Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story, and Fab Morvan for You Know It's True: The Real Story of Milli Vanilli.The Dalai Lama did not attend the ceremony. Singer-songwriter Rufus Wainwright accepted the award on his behalf, drawing laughter from the audience when he quipped during his speech, "I am not the Dalai Lama."

The Dalai Lama had collaborated with sarod maestro Amjad Ali Khan and his sons, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash, on the album, blending spoken word and music to celebrate universal values of peace, compassion, kindness and hope.In a statement following the win, the Dalai Lama said, "I receive this recognition with gratitude and humility. I don't see it as something personal, but as a recognition of our shared universal responsibility. I truly believe that peace, compassion, care for our environment, and an understanding of the oneness of humanity are essential for the collective well-being of all eight billion human beings. I'm grateful that this Grammy recognition can help spread these messages more widely."The Dalai Lama joined a list of first-time Grammy winners this year that also included K-pop artists and acclaimed filmmaker Steven Spielberg.

Apartment Prices Have Risen Every Single Week For A Year In This City

World. (Agency)

Bohyun Lee followed South Korea's prescribed route to success. She entered the country's top university to study economics, moved to Seoul in 2010 and built an adult life there - working, forging relationships and treating the capital as home.

The one thing she doesn't have is an actual home of her own. Over the past 16 years Lee has packed her belongings and moved seven times, cycling through a dormitory and rental homes as two-year leases expired. The hope of owning an apartment in Seoul, once a realistic goal, has steadily slipped out of reach."I've learned how to live without owning a home, but the dream hasn't disappeared," said Lee, 33, who works in the financial services industry. "Moving so many times wears you down, and it feels unfair."Homes she once considered buying in the mid-2010s that were priced around 400 million won ($280,960) now trade at roughly three times that value, far exceeding what even a well-paid professional can accumulate through wages alone. For Lee, the market's relentless rise isn't an abstract chart but a lived reality in which she's seeing the bottom rung of the property ladder float out of reach with every extension of the rally.The persistent increase in Seoul's property prices threatens to undermine support for President Lee Jae Myung as the young adults flocking to the capital for jobs decry their inability to put down real-estate roots. It also limits the central bank's scope to stimulate the economy at a time when persistent trade tensions threaten growth, as a rate cut might stoke excessive borrowing.Apartment prices in Seoul have now risen for 52 consecutive weeks, according to Korea Real Estate Board. The rally has defied repeated attempts by successive governments to cool the market with steps including tighter lending rules, extending pressure on would-be buyers.Tougher mortgage limits have transformed South Korea's capital into one of the most restrictive home-loan markets in the world, effectively locking out many potential buyers as prices advance further out of reach. Under the latest framework, buyers can borrow a maximum of 600 million won for homes valued up to 1.5 billion won. For properties priced between 1.5 billion won and 2.5 billion won, the cap drops to 400 million won, while homes above that range qualify for loans of just 200 million won.The government lowered loan-to-value ratios to 40% in October in designated regulated districts that now cover all of Seoul, while maintaining a higher 70% cap for first-time buyers and those refinancing existing mortgages. The special restriction applying to properties in the nation's capital comes as apartment prices in Seoul rose almost 9% in 2025. Gains across the rest of the country were around 1%, underscoring the extent to which demand is concentrated in the capital.In global terms, South Korea is not alone in tightening access to home loans. Other markets, including New Zealand, Australia, Canada and Singapore, have imposed strict loan-to-value ratios, debt-servicing limits or stress tests to cool overheated housing markets, while cities such as Hong Kong have paired lending curbs with hefty stamp duties, according to Pamela Ambler, head of investor intelligence and strategy Asia Pacific at Jones Lang LaSalle Inc.

Indian-origin climate scientist Veerabhadran Ramanathan wins prestigious Crafoord prize in US

HOUSTON. (Agency)

Indian-origin climate scientist Veerabhadran Ramanathan has been awarded the 2026 Crafoord Prize in Geosciences by the Royal Swedish Academy of Sciences.Often described as the "Nobel of Geosciences," the prize recognises Ramanathan's decades of research on super-pollutants and atmospheric brown clouds, which have reshaped understanding of global warming.Ramanathan, 82, made a landmark discovery in 1975 while working at NASA: chlorofluorocarbons (CFCs), widely used in aerosols and refrigeration, trap heat in the atmosphere up to 10,000 times more effectively than carbon dioxide."Until 1975, we thought global warming was mainly from CO2. I was shocked at the capacity of technology and human beings to change the environment," Ramanathan told the Royal Swedish Academy of Sciences.Born in Madurai and raised in Chennai, Ramanathan began his career as an engineer in a refrigerator factory in Secunderabad, where he first handled CFCs. He later earned degrees from Annamalai University and the Indian Institute of Science.His Indian roots informed his work in the Indian Ocean Experiment (INDOEX), which identified atmospheric brown clouds over South Asia.The study linked air pollution to a weakened Indian Monsoon and accelerated melting of Himalayan glaciers.

Now, a Distinguished Professor Emeritus at the Scripps

Institution of Oceanography, University of California, San Diego, he has also advised global leaders and the Vatican on climate ethics.The Crafoord Prize carries a cash award of 8 million Swedish kronor (approximately $900,000) and a gold medal.

The award will be presented during Crafoord Days in Stockholm and Lund in May 2026.Ramanathan's work underpins key international treaties, including the Montreal Protocol, which has prevented millions of tons of harmful emissions from entering the atmosphere.

Kennedy Center to close for two years for renovations in July, Trump says, after performers' backlash

WASHINGTON. (Agency)

President Donald Trump said Sunday he will move to close Washington's Kennedy Center performing arts center for two years starting in July for construction, his latest proposal to upturn the storied venue since returning to the White House.Trump's announcement on social media follows a wave of cancellations by leading performers, musicians and groups since the president ousted the previous leadership and added his name to the building.

Trump made no mention in his post of the recent cancellations.His proposal, announced days after the premiere of "Melania, " a documentary of the first lady was shown at the center, he said was subject to approval by the board of the Kennedy Center, which has been stocked with his hand-picked allies. Trump himself chairs the center's board of trustees."This important decision, based on input from many Highly Respected Experts, will take a tired, broken, and dilapidated Center, one that has been in bad condition, both financially and structurally for many years, and turn it into a World Class Bastion of Arts, Music, and Entertainment," Trump wrote in his post.Neither Trump nor Kennedy Center President Ric Grenell, a Trump ally, have provided evidence to back up their claims about the building being in disrepair, and last October, Trump had pledged the center would remain open during renovations. In Sunday's announcement, Trump said the center will close on July 4th, when he said the construction would begin.

The sudden decision to shutter and reconstruct the Kennedy Center is certain to spark blowback as Trump upturns the popular venue, which began as a national cultural center but Congress renamed as a "living memorial" to President John F. Kennedy in 1964, in the aftermath of the slain president's death.Opened in 1971, it is open year-round as a public showcase for the arts, including the National Symphony Orchestra.Since Trump returned to the White House, the Kennedy Center is one of many Washington landmarks that he has

sought to overhaul in his second term. He demolished the East Wing of the White House and launched a massive $400 million ballroom project, is actively pursuing building a triumphal arch on the other side the Arlington Bridge from the the Lincoln Memorial, and has plans for Washington Dulles International Airport.Leading performing arts groups have pulled out of appearances, most recently, composer Philip Glass, who announced his decision to withdraw his Symphony No. 15 "Lincoln" because he said the values of the center today are in "direct conflict" with the message of the piece.Last month, the Washington National Opera announced that it will move performances away from the Kennedy Center in another high-profile departure following Trump's takeover of the U.S. capital's leading performing arts venue.The head of artistic programming for the center abruptly left his post last week, less than two weeks after being named to the job.

A spokesperson for the Kennedy Center could not immediately be reached and did not respond to an emailed request for comment.

NEWS BOX

Delhi Capitals edge past UP Warriorz to book WPL 2026 Eliminator spot, MI bow out

NEW DELHI. (Agency)

Delhi Capitals did just enough when it mattered, holding their nerve in a tense run chase to beat UP Warriorz by five wickets and secure a spot in the WPL 2026 Eliminator on Sunday. The win not only extended DC's remarkable record of making the playoffs in every season so far, but also confirmed the defending champions Mumbai Indians' exit from the tournament.Set a modest target of 123, Capitals appeared to be cruising early before a late wobble threatened to undo their work. They eventually reached 126 for five with eight balls to spare, thanks to a composed finish from captain Jemimah Rodrigues, who remained unbeaten on 34 off 18 balls, and youngster Niki Prasad, who stayed calm at the other end to seal the result.

Bowlers set the platform for Capitals

The chase was built on a solid foundation laid by Laura Wolvaardt and Shafali Verma. After an early blow with the dismissal of Lizelle Lee, the pair steadied the innings with a 73-

run stand. Wolvaardt anchored the effort with a patient 47 off 36 balls, striking seven boundaries, while Shafali played the supporting role with a measured 29.

Just when the finish line seemed comfortably in sight, Delhi lost their way. From 84 for one, they slipped to 101 for five, allowing UP Warriorz to sniff a dramatic turnaround. Sophie Ecclestone and Deepti Sharma kept things tight and picked up key wickets, but the lack of runs on the board ultimately hurt UPW. Jemimah ended any remaining doubts by striking two crucial boundaries off Deepti in the penultimate over.

Calm Jemimah wins it for Delhi, ends MI's run

Earlier in the evening, Delhi's bowlers set the tone. Marizanne Kapp led the charge with figures of 3 for 30, while Chinelle Henry chipped in with two wickets as UP Warriorz were restricted to 122 for eight. UPW never quite recovered from losing an early wicket and struggled to build partnerships throughout the innings.

Gavaskar trolls Pakistan's India boycott: Like their cricketers, a U-turn awaits

NEW DELHI. (Agency)

Batting great Sunil Gavaskar did not hold back in his assessment of Pakistan's decision to boycott India's match at the T20 World Cup 2026, suggesting that, much like their retired cricketers who frequently reverse decisions, Pakistan could also be forced into a U-turn under pressure from voices within the game, both globally and domestically.Speaking to India Today's sister channel AajTak, Gavaskar took a swipe at Pakistan, remarking that their cricketers have set a precedent by often going back on major decisions — an indirect jab at the likes of Shahid Afridi, who repeatedly announced retirements only to reverse them."I think in the next four or five days, when reactions start pouring in from across the world and even from their former players, there is a possibility that Pakistan will change their stance," Gavaskar said.India and Pakistan were scheduled to

meet in a league-stage match of the T20 World Cup in Colombo on February 15. However, the Pakistan government created a stir on Sunday evening by announcing that its national team would boycott the match against India.The decision comes after Pakistan cricket chief Mohsin Naqvi — who also serves as the country's Interior Minister — threatened to boycott the T20 World Cup in solidarity with Bangladesh, who were replaced by Scotland in the 20-team tournament starting February 7."What's new in this? We all know Pakistan cricketers retire and then, four days later, take back their retirement, saying 'our fans told us to play more'. This might happen again," Gavaskar said.What's the problem with making U-turns in your decisions? There's no issue, as far as I know."Pakistan players have set examples. They keep coming back from retirement. So something like that might happen before the 15th."Gavaskar also warned Pakistan of potential sanctions and penalties from the International Cricket Council (ICC) if it goes ahead with its decision to avoid playing India on February 15.

Boycott India match, but what about the final? Ex-cricketers question Pakistan stance

Pakistan's decision to boycott the India match has opened a bigger question. If the teams meet again later in the tournament, will Pakistan walk away from a World Cup final too?

New Delhi. (Agency)

Pakistan's decision to boycott their marquee T20 World Cup clash against India has left the cricketing world more puzzled than persuaded. What was meant to be a political statement has instead opened up a flood of uncomfortable questions, especially about how far the stance is meant to go.The flashpoint is February 15 in Colombo, where India and Pakistan were scheduled to meet in the league stage of the T20 World Cup 2026. While the Pakistan government's announcement caught fans off guard, it has been former cricketers who have voiced the sharpest doubts, wondering whether selective participation in a global tournament is even feasible.Pietersen and Ashwin question boycott stanceFormer England captain Kevin Pietersen was among the first to publicly challenge the logic behind the move, questioning whether Pakistan would maintain the same position if the two sides crossed paths later in the tournament."Not sure if India can meet Pakistan in this World Cup final due to groups and play-offs, but if they can, would Pakistan refuse to play the World Cup final?" Pietersen wrote in his post.Soon after, former India spinner Ravichandran Ashwin also weighed in, pointing out the complications such a boycott could create in knockout scenarios."An India-Pakistan clash, even in the knockout is ruled out? Sure? We get there it will be a "World T 20 bye" ?" Ashwin's post read.Why did Pakistan threaten an IND vs PAK boycott?Pakistan's boycott announcement stems from comments made by PCB chairman and Interior Minister Mohsin Naqvi, who threatened withdrawal in solidarity with Bangladesh after they were replaced by Scotland in the 20-team competition. While the political messaging was clear, the cricketing fallout has been anything but.The International Cricket Council (ICC) has already flagged serious concerns, warning that selective participation undermines the tournament and its global audience. The ICC has said it is awaiting formal communication from the Pakistan Cricket Board, but stressed that such decisions can have long-term consequences for the sport.Meanwhile, sources within the Board of Control for Cricket in India maintain that India will stick to protocol. The side will be travelling to Colombo, attending training sessions and media commitments, and leaving the final call to match officials.The India–Pakistan fixture remains cricket's most valuable property, which is why the ICC has consistently placed the two teams in the same group since 2012 despite frozen bilateral ties. If Pakistan hold firm, the 2026 T20 World Cup could become the first men's ICC event since 2010 without an India–Pakistan contest.

Football hasn't left Man United's Casemiro: Carragher makes U-turn after Fulham show

London. (Agency)

Former Liverpool defender-turned-pundit Jamie Carragher has made a notable U-turn on Casemiro, admitting that "the football has not left him" after the Brazilian's standout display in Manchester United's dramatic 3-2 win over Fulham. Carragher's reassessment comes months after he had openly questioned whether Casemiro was still cut out for Premier League football.

Speaking to Sky Sports after United's 3-2 win against Fulham on Sunday, Carragher acknowledged that his earlier criticism no longer holds, with Casemiro producing performances that resemble the elite midfielder United thought they were signing."It is now fair to say the football has not left him. Considering what he's producing this season in the Premier League, and not just Fulham at home, you think what he did last week against Arsenal away and Manchester City at home," he said.With a touch of humour pointed at himself, Carragher said Casemiro's recent run of form demanded a rethink."Casemiro is well within his rights to, if he wants to come back at me and say, 'leave the punditry before the punditry's left you!' He could definitely get one of those back in. Credit to him, he looks a completely different player," Carragher said."He looks like a different player physically as well. Even when I said that, you looked at him and he looked like an old man coming to the end of

his time as a player and whether he let himself go a little bit, or now he's being ultra professional, physically, he looks completely different," he added.What did Carragher say first about Casemiro?

The praise marked a sharp contrast to Carragher's stance in May 2024, when he was brutally critical of Casemiro after a heavy defeat at Crystal Palace, suggesting the midfielder's legs were gone and that it might be time to step away from top-level football. At that stage, Casemiro's form had dipped noticeably and he appeared out of sync with the pace of the league.Fast-forward to this season, and the narrative has flipped. Casemiro has been one of Manchester United's most consistent performers, rolling back the years with commanding midfield displays. Against Fulham on Sunday, the 33-year-old dominated the centre of the pitch, opened the scoring in the 19th minute, and then even assisted United's second.

Man United continue on winning ways

The match itself was a thriller. United raced into a 2-0 lead through Casemiro and Matheus Cunha, only for Fulham to stage a late comeback with a Raul Jimenez penalty and a stoppage-time equaliser. Just when it seemed two points had slipped away, substitute Benjamin Sesko struck deep into added time to seal a 3-2 win and send Old Trafford into raptures.The victory continued United's resurgence under interim manager Michael Carrick, lifting them to fourth in the Premier League table, with Chelsea a point behind in fifth.

Benjamin Button of the baseline: Novak Djokovic, at 38, is still the great disruptor

NEW DELHI. (Agency)

Novak Djokovic may have fallen short of the elusive No. 25 yet again, but at 38, he delivered a reminder that his greatest current era rivals, Carlos Alcaraz and Jannik Sinner, are still not coasting through this era unchallenged.

The duopoly, Djokovic screamed loud, can be shaken.His run to the final of the season-opening Australian Open was proof.For Djokovic, and for those who still believe, Sunday in Melbourne may have felt more encouraging than some of his Grand Slam victories.That sounds strange. But at 38, Djokovic is doing things not many in sport, and no one in men's tennis, has ever managed.

A few months ago, it almost felt like Djokovic had given up. That isn't who he is. Yet there he was acknowledging the widening gap between himself and the two men who had seized control of men's tennis. Alcaraz and Sinner had won all eight Grand Slams over the last two years between them.Since winning the US Open in 2023, Djokovic had reached just one Grand Slam final. In 2025, he couldn't get past the semifinals of any of the four majors. And

when Alcaraz hammered him in straight sets in New York, Djokovic sounded beaten – a tone rarely heard from him.But time, finally, appeared to be winning , even against the man who once bent it to his will. The Sincaraz era felt inevitable.

The most telling moment came after his semifinal defeat in New York.

"It will be very difficult for me in the future to overcome the hurdle of Sinner and Alcaraz in best-of-fives at Grand Slams. I think I have a better chance in best-of-three, but best-of-five, it's tough," he said after the US Open exit.

He stressed he wasn't giving up. But the tone was subdued, almost doubtful – as if the chase for a record 25th Grand Slam title might never be complete.

BUT, DJOKOVIC IS DJOKOVIC

After skipping the preseason, he arrived in Melbourne with quiet hope - and very little external belief. The conversation revolved around Alcaraz's bid for a Career Grand Slam and Sinner's push for a third straight Norman Brookes Challenge Cup.Djokovic was placed in Sinner's half. His presence was barely discussed as a threat.

Carlos Alcaraz plans kangaroo tattoo to celebrate his Australian Open title win

NEW DELHI. (Agency)

Carlos Alcaraz is considering a permanent reminder of his maiden Australian Open title win, revealing that he may get a small kangaroo tattoo to celebrate the biggest milestone of his career.The 22-year-old said the idea came naturally after his victory over Novak Djokovic in the men's singles final, a win that made him the youngest male player to complete a career Grand Slam. The design is clear in his mind, but the location is still undecided."I already know it's going to be a kangaroo. I just don't know the place," Alcaraz said. "I'm just thinking about the leg but I don't know which calf, whether it will be the right or left one."Alcaraz posed with the ornate Australian Open trophy on Monday during a photo shoot at Melbourne's Royal Exhibition Building, looking relaxed and stylish in black, wearing loafers without socks. A day earlier,

women's singles champion Elena Rybakina was photographed with her trophy along the banks of the Yarra River.According to Australian media reports, Alcaraz spent the night after his victory quietly with his family in his hotel suite, celebrating with pizza, beer and champagne.

In a social media message shared with fans during the photo shoot, Alcaraz admitted the scale of the moment was still sinking in. "I still can't believe that I just made it. A dream come true for me, a career Grand Slam. I'm enjoying this amazing moment. I can't forget the support and the love I've received."After closing out a 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 win over the 10-time Australian Open champion, Alcaraz spoke about the nerves he felt before the last point."Before the last point, a lot of things came to my mind, to be honest," he said. "I was really nervous, I was shaking almost. So once I saw the ball go out, I was like, alright, I made it. It was a great feeling, thinking about my family and my team as well."

CHASING COMPLETION

With the career Grand Slam secured, Alcaraz has already turned his attention to what remains unfinished. He is aiming to win the three Masters 1000 titles that have so far eluded him, the Canadian Open, Shanghai and Paris, along with the season ending ATP Finals and the Davis Cup with Spain.

IND vs PAK fiasco won't end here: Former Pakistan skipper on T20 World Cup boycott row

Rashid Latif has warned that Pakistan's T20 World Cup boycott threat could spark prolonged chaos beyond one tournament. With future ICC events at stake, the former captain believes the controversy is only beginning.

NEW DELHI. (Agency)

"Former Pakistan captain Rashid Latif has warned that the T20 World Cup boycott controversy involving Pakistan is far from over, suggesting the standoff could trigger wider complications for international cricket. Latif believes the decision has been taken with long-term consequences in mind and could resurface across multiple ICC events.Speaking in an interview with Times of India, Latif said Pakistan's stance should not be viewed as a one-off reaction and hinted that the ripple effects could extend well beyond the ongoing men's T20 World Cup."Pakistan generally don't take such decisions. The PCB is not even scared of sanctions. It will have a big impact. There is a Women's T20 World Cup in England this year, and Pakistan might play India there as well. Then there is a Champions Trophy in 2028, hosted by India. So this will not end here. It seems that Pakistan has taken this step after a lot of thought," Latif said.Latif pointed out that relations between the two boards had appeared stable until recently, with both sides agreeing on a hybrid model for ICC events over the next three years."Till now, everything was going well. Pakistan and India both agreed that we would play in a hybrid model for the next three years. The Asia Cup happened in Dubai. Pakistan's women's team played in Sri Lanka in the Women's ODI World Cup. Everything was going well, but things have changed since the Bangladesh episode happened," he said from

Islamabad.Why did Pakistan threaten a boycott?The issue began when Pakistan announced it would boycott its league-stage T20 World Cup match against India in Colombo on February 15. The decision followed comments from Pakistan cricket chief Mohsin Naqvi, who spoke about a possible boycott in support of Bangladesh after they were replaced by Scotland in the tournament.The International Cricket Council (ICC) has raised serious concerns over any team choosing to skip matches in a global event. The ICC said such a move is not in the best interest of the game or its fans. While it is still waiting for official communication from the Pakistan Cricket Board, the ICC has urged Pakistan to think carefully about the long-term impact this decision could have on world cricket.Latif explained why a prolonged standoff would affect more than just India and Pakistan."Whether it is in India or Pakistan, 60–70 percent of people watch the World Cup because of India–Pakistan matches... You know how powerful broadcasters are. They will find some solution," he said."Now that Pakistan has joined, it will impact Australia and England financially as well....The businessmen are above our governments. Now the game has gone out of their hands.

Karan Kundrra On Falling In Love With

Tejasswi Prakash

on Bigg Boss 19: 'All Filters Are Dropped...'

Karan Kundrra and Tejasswi Prakash met on Bigg Boss, and their friendship soon turned into love. Now, five years later, the two are going strong and never shy away from giving major couple goals. Karan Kundrra, who is currently hosting the couple-based reality show alongside Sunny Leone, opened up about what it is like to fall in love in a captive reality space.

Speaking to Screen, Karan shared, "I was on a reality show when I found Tejasswi. What I really like about a captive reality show is that your true nature comes out very soon. All the filters are dropped within 7–8 days. There is no adulteration from the outside world, be it your managers, your family, or friends. You are alone, and you feel exactly what you feel. Nobody is guiding your judgment, so it's the purest feeling."

He further continued and spoke about how what people see on Instagram is very different from what a relationship means in real life and added, "I would like to tell everybody that love is not what you see on Instagram; it's very different from what is being told to you or shown to you in films or between couples you follow or idealize. It is so much more real, but I feel people take cues from all of these and start putting pressure on their relationships. That's not how it is. It's just the basic little things, not grand things."

Karan Kundrra on Constant Scrutiny

Earlier, while speaking to Pinkvilla, the actor opened up about facing constant scrutiny and shared that maturity plays an important part. He said, "The idea is that as long as Teju and I have the maturity to not get affected by all of this, then we are fine. Listen, we chose to be actors, we chose to do a show like Bigg Boss, and we chose to be out there. So we cannot complain about it. We cannot be hypocritical and say, 'ki nahi yaar mat capture karo.' (…meaning, 'No, don't capture us.') We are there; we are public figures."

About Karan and Tejasswi

For the uninitiated, Karan Kundrra and Tejasswi Prakash have been dating since 2021, after their relationship blossomed on the reality show Bigg Boss 15. While Karan finished at number three, Tejasswi lifted the trophy of Salman Khan–hosted Season 15.

'Everyone Will Think...': Faisal Shaikh On Doing The 50 With Friends Adnaan And Faiz

Indian television's most popular names enter The 50, a new reality show, and among them are social media influencer Faisal Shaikh, aka Mr Faisu, along with his friends Adnaan Shaikh and Faiz Baloch. While having your close friends by your side in a show where you will not have any connection with the outside world can be a major advantage, it can also cause problems between the three. Speaking about being on such a show with two of his closest friends, Faisal Shaikh, aka Mr Faisu, shared its advantages and disadvantages.

Speaking to Screen, Mr Faisu shared, "Having your friends in the game has its advantages and disadvantages. Having my brothers when I break down will be an advantage; they will stand by me when needed. In every show, I have an emotional breakdown, so them being around is great. But yes, it will also be a disadvantage when it comes to nominations; everyone will think I have come with my group, so I am playing it safe."

"My fitness will also be an advantage in the game; physical activities will be a plus point for me. I haven't played any mind games yet. I am cunning in real life, so I might show that on the show. I don't like it when someone keeps poking me or even comes at me; I cannot stand it, so it can be a disadvantage. In a captive reality show, people do anything when they get frustrated. I don't know what I will do," he continued.

The 50, India's newest high-voltage reality show, is set to debut on February 1, 2026, and has already generated immense buzz thanks to its ambitious format and star-studded lineup. Produced by Banijay Asia and streaming on JioHotstar, while also airing on Colors TV, the show promises to bring together 50 well-known personalities from television, film, and the digital world in a competitive environment that blends strategy, survival, and social gameplay.

The show is expected to run for approximately 50 days, with eliminations and twists keeping the competition intense. The show boasts a massive, attention-grabbing lineup that has already got fans talking. Contestants set to grace The 50 include popular names like Karan Patel, Divya Agarwal, Prince Narula, Urvashi Dholakia, Nikki Tamboli, Faisal Shaikh aka Faisu, Krishna Shroff, Shiv Thakare, Archana Gautam, and Bigg Boss 19 contestant Neelam Giri, among many others.

Shanaya Kapoor Is Listening To THIS Song On Loop From Tu Yaa Main, Ananya Panday Reacts

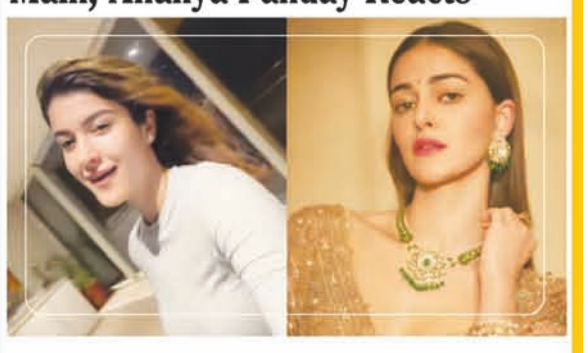

Shanaya Kapoor is all set for her second release, Tu Yaa Main, with Adarsh Gourav. The makers have recently released a teaser that grabbed attention. And today she shared a video in which she was seen enjoying the song on a balcony. The survival drama is releasing on February 13, 2026.Taking to her Instagram handle, Shanaya Kapoor shared a video in which she is seen singing the song Jee Liya and wrote, "saturday night lights with jee liya on loop." Ananya Panday immediately reacted, "be careful near railing". Fans too reacted.

Shanaya Kapoor Celebrates Tu Yaa Main Song 'Jee Liya'

Shanaya Kapoor is giving fans plenty to smile about with her latest Instagram post. The 12-slide carousel gives fans a behind-the-scenes glimpse of her recent promotional event, starting with a video that captures all the key moments in one fun compilation. The following slides capture her at the event, mingling with the film's team and sharing candid and joyful moments. One of the most playful highlights is a crocodile-themed setup inspired by the film, where Shanaya and co-star Adarsh Gourav are seen having a great time. From chic poses to fun, personal glimpses, the post perfectly showcases Shanaya's charm while building excitement for her upcoming film. The caption of her post read, "Jee Liya out now" Recently released, 'Jee Liya' from the film is crooned by Adarsh himself, along with Lothika.

Tu Yaa Main Teaser

The teaser takes audiences into the world of two content creators from completely different backgrounds who come together for a collaboration driven by curiosity, clout and chemistry. What starts off as a fun, high-energy adventure quickly takes a dark turn, turning into a pulse-pounding fight for survival as they come face to face with a menacing crocodile. Will they manage to escape, or will the croc turn their collaboration into a nightmare? Blending romance, adrenaline and danger with fresh, new-age storytelling, the Bejoy Nambiar directorial, starring Adarsh Gourav and Shanaya Kapoor, promises an experience that will turn an ordinary date into a chilling memory, making it the perfect #DateFright experience for audiences seeking something beyond the usual Valentine's watch. The film also stars Parul Gulati in a key role.

Bhumi Pednekar

Felicitated At Kala Ghoda Arts Festival Inauguration In Mumbai

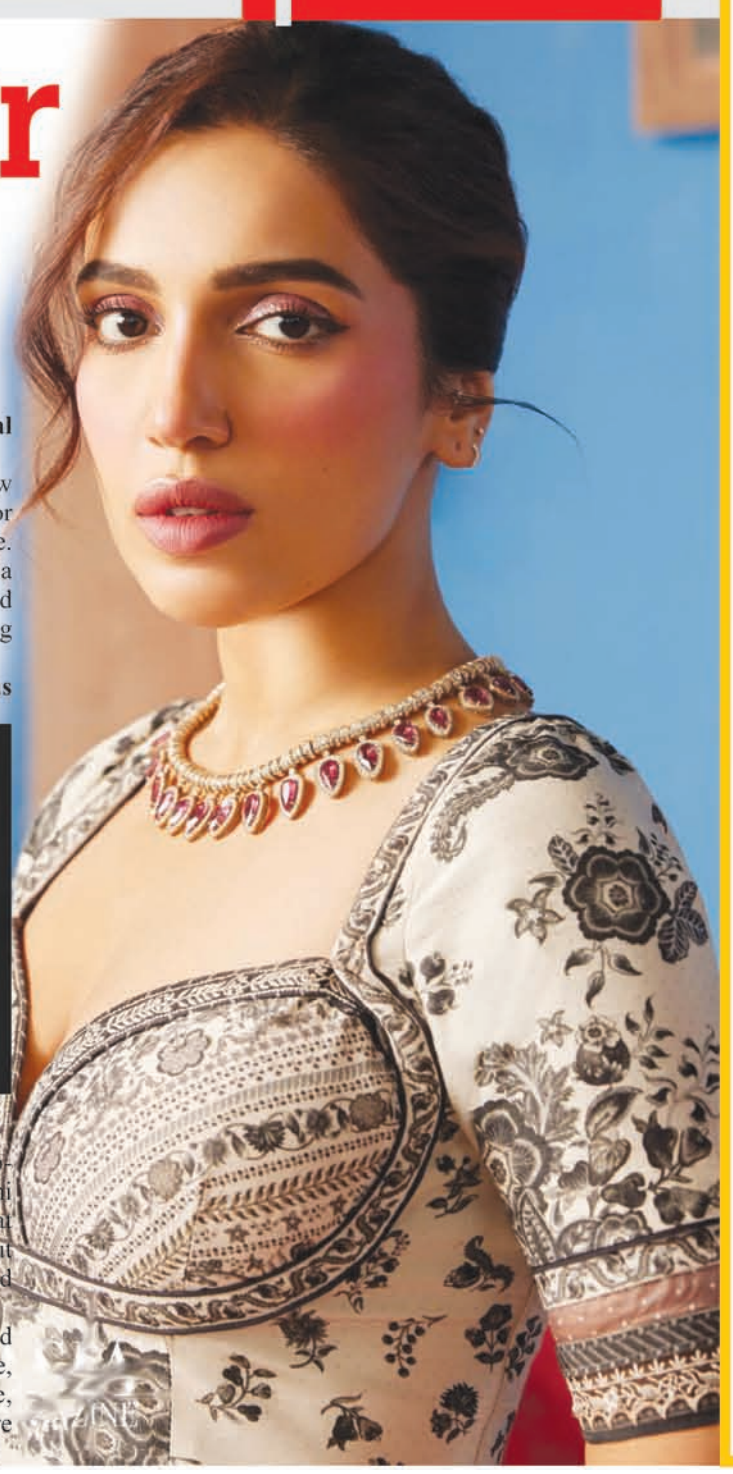

The inauguration of Mumbai's iconic Kala Ghoda Arts Festival featured a memorable moment as actor and climate advocate Bhumi Pednekar was felicitated on stage during the opening ceremony. The honour was presented by Brinda Miller, Honorary Festival Director and Chairperson of the Kala Ghoda Association, recognising Bhumi's contribution at the intersection of art, awareness, and social responsibility.Held at the historic Kala Ghoda precinct, the inaugural evening marked the beginning of Asia's largest multidisciplinary street arts festival, bringing together artists, cultural leaders, and prominent voices from across creative fields.

'Without Art, There Is No Empathy,' Says Bhumi Pednekar

While accepting the honour, Bhumi Pednekar spoke about the deeper role art plays in shaping society. Emphasising the emotional power of creative expression, she said, "In a society where there is no art, there will be no empathy," drawing attention to how storytelling and creativity help foster understanding and compassion.

Her words resonated strongly with the audience, reinforcing the festival's core philosophy of art as a catalyst for social connection and reflection.

A Proud Mumbaikar Moment for the Actor

Bhumi also shared a personal note during the ceremony, describing herself as a "true blue Mumbaikar at heart." She expressed pride in being recognised at a festival that she said embodies the cultural soul of the city. The moment was met with warm applause from those present at the opening ceremony.

Brinda Miller on Bhumi Pednekar's Cultural Impact

Presenting the honour, Brinda Miller highlighted how the Kala Ghoda Arts Festival has always stood for the idea that art is inseparable from everyday life. She noted that Bhumi Pednekar's journey reflects a balance between meaningful cinema and responsible public engagement, making her a fitting presence at the festival's inauguration.

Kala Ghoda Arts Festival Celebrates Art as Connection

As the evening continued with traditional lamp-lighting rituals and inaugural addresses, Bhumi Pednekar's felicitation stood out as a reminder that culture is not just about celebration, but about connection — to the city, its people, and shared human experiences.

The Kala Ghoda Arts Festival once again reaffirmed its role as a platform where heritage, performance, visual arts, literature, and dialogue converge, celebrating artists who use their voice to inspire empathy and awareness.